साप्ताहिक

पृथ्वी पर हम सब समय माया के यात्री हैं

समय माया

R.N.I. No.: MP/HIN/2006/20685

प्रधान संपादक- अजमेरा एस.पी. कुमार
B.COM., M.A., LLB, CAIIB, DLLLW&PM

Webite: www.samaymaya.com
Email: samaymaya@gmail.com
samaymaya@rediff.com

Cell: +91 9425125569
Phone Fax: +91 731 2530859

(C) All Copyrights reserved with chief editor, do not publish any matter without prior written permission

In case of any dispute, may be solved only in Indore Court Jurisdiction

वर्ष 10 अंक 41 | प्रति सोमवार इंदौर, 23 से 29 मई 2016 | पृष्ठ 12 | मूल्य 2/- रुपए

अमेरिका-चीन व अन्य औद्योगिक उन्नत राष्ट्र फैलाते है सबसे ज्यादा प्रदूषण

पेरिस जलवायु परिवर्तन चिंतन नौटंकी खास मुद्दों पर चुप्पी

पेरिस में नव-दिस्मबर 15 में हुए जलवायु परिवर्तन पर कई चिंतन सभा यथार्थ में पूर्णतः 150 राष्ट्रों के शासकों यथा राष्ट्रपति व प्रधानमंत्रियों ने भाग लेकर यथार्थ में उनके राष्ट्रों के जनधन से पूर्णतः नौटंकी की ही, क्योंकि अधिकांश ने केवल स्वचलित वाहनों में प्रयोग किए जाने वाले जीवाश्म ईधन यथा पेट्रोल, डीजल, ज्वलन वायु से उत्पन्न कार्बन युक्त वायव्यीय यथा कार्बन डाइ आक्साइड, कार्बन मोनोआक्साइड आदि के उत्सर्जन में कटौती करने के तथ्य को स्वीकार किया, जबकि यथार्थ में स्वचलित वाहनों के उत्पादन पर प्रतिबंध लगाने या उनकी संख्या में कमी करने की बात ओबामा, अमेरिकी राष्ट्रपति, चीनी प्रधानमंत्री शी जिन पिंग या भारतीय प्रधानमंत्री मोदी, ब्रिटेन के प्रधाममंत्री केमरान या फ्रांस के ओलांद किसी ने नहीं की। उल्टे ही पुराने वाहनों को जो 15 वर्ष से ज्यादा के थे उन्हें हटाने की चर्चा अवश्य ही भारत के केन्द्रीय मंत्रालयों में यदा-कदा चलती रहती है। ताकि जनता नए वाहनों को खरीदे और वाहनों का उत्पादन बढ़ता हुआ जारी रह सके, जबकि अनेकों राष्ट्रों में पुरानी कारों को नष्ट करना भी एक बड़ी समस्या के रूप में उभरा है।

दुनिया के सबसे बड़ी आबादी के राष्ट्र चीन की राजधानी बीजिंग

जीवाश्म ऊर्जा उत्सर्जित कार्बन कम करने पर सहमति पर औद्योगिकीकरण से उत्पन्न घातक रसायनों का प्रदूषण, फ्लोराकार्बन, कॉलोनाइजेशन इलेक्ट्रानिक्स, परमाणु ऊर्जा जनित विकिरण राख, घातक रसायनिक हथियारों उपभोक्ता वस्तुओं की पैकिंग में उपयोग की गई पॉलीथिन, एल्युमिनियम फाइल आदि का कचरा भी ढंक रहा व बिगाड़ रहा पर्यावरण चक्र पर चुप्पी

में न केवल वाहनों के जीवाश्म ईंधन के उपयोग से हुए उत्सर्जन वरन औद्योगिकी प्रदूषण से स्थिति भयावह हो जाने से वहां पर 20 दिसम्बर से 30 दिसम्बर तक स्कूलों को बंद करना पड़ा, क्योंकि वहां पर 70 प्रश 15 वर्ष के बच्चों के साथ बड़ों को भी सांस लेने में तकलीफ होने लगी थी, ऐसा केवल चीन के बीजिंग में हुआ हो ऐसा नहीं है चीन के अनेकों शहरों में न केवल कार्बन उत्सर्जन जो वाहनों में जीवाश्म ईंधन उपयोग से उत्पन्न होता है, वरन् औद्योगिकीकरण से उत्पन्न फ्लोरोकार्बन गैसेज व अन्य तरह जल, मृदा और वायुमंडलीय प्रदूषण भी फैलता है उसके बारे में प्रत्यक्ष प्रमाण के बाद भी कोई चर्चा न किया जाना सिद्ध करता है कि पेरिस में जलवायु परिवर्तन पर चिंतन केवल नौटंकी मात्र था।भारत में भी मोदी मात्र अपनी महानता सिद्ध करने और पूरे राष्ट्र को पूंजीपतियों के इशारे पर जिस औद्योगिकीकरण और परमाणु ऊर्जा उत्पादन के लिए धकेल रहा है, जबकि अधिकांश युरोपीय राष्ट्र जिसमें अमेरिका, आस्ट्रेलिया, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन, कनाडा, परमाणु ऊर्जा, और उसके कचरे को नष्ट करने को लेकर ही भारी परेशान है और अपने समय बाधित संयंत्रों, जो न केवल कबाड़ा हो चुके है वरन् रेडियो एक्टिव होने के कारण घातक अल्फा, बीटा, गामा किरणें भी उत्सर्जित कर रहे है ऐसी परमाणु भट्टियों को भारत में कहीं भी लगाने का औचित्य केवल घातक रेडियो एक्टिव प्रदूषण फैलाना ही होगा, जबकि भारत में गामा किरणों के टंगस्टन पर परावर्तन से तैयार चिकित्सीय कार्यों में प्रयोग किए जाने वाली एक्स-रे किरणों के माध्यम से शरीर की आंतरिक बीमारियों और अस्थियों की क्षति के छाया चित्रों की मशीनों पर पर कार्य करने वाले कर्मचारी जो कि इस क्षयकारी विकिरण की सीमा से ज्यादा की अवस्था में पहुंच कर घातक रोगों का शिकार हो रहे हैं, (शेष पेज 3 पर)

सिंहस्थ आयोजन के नाम भ्रष्टाचार और लूटपाट का तांडव

जनधन के रुपए 10000 करोड़ में से रुपए 5000 करोड़ हजम

उज्जैन नगर निगम, विकास प्राधिकरण, लो.स्वा.यां.लो.नि.वि., गृह जल संसा, स्वास्थ्य, स्वा. एवं नागरिक आपूर्ति, जिला पंचायत आदि में सैकड़ों करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार कर हजम किए

मप्र के शक्ल से भोला दिखने वाला मुख्यमंत्री शिवराज का दोहरा चरित्र सबको ज्ञात है। घोर आपराधिक और भ्रष्ट होने के बाद भी तीसरी बार मु.मं. बन जाने के कारण इतना तो अच्छी तरह से जानता है कि जनता के सामने बड़े विनम्र और दीनहीन अंदाज में प्रस्तुति की आड़ में आसानी से जनता और जनधन और जनसंपत्तियों के साथ नोंच-खसोंट कर लूटते रहो, प्रचार प्रसार माध्यमों पर और जनधन का अरबों रुपए लुटाते रहो, अपनी झूठी वाहवाही करवाते रहो कोई कुछ नहीं बोलेगा। उज्जैन का सिंहस्थ 2016 का आयोजन उसकी एक छोटी सी बानगी है जहां हर विभाग में चुन-चुन कर भ्रष्ट अधिकारियों का मेला

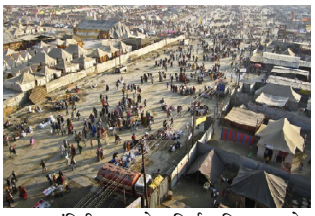

प्राधिकरण, नगर निगम, जिलाधीश कार्यालय, संभागीय आयुक्त कार्यालय विकास प्राधिकरणन, मप्र लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय, प्र लोक निर्माण विभाग, मप्र विद्यु वितरण, जन संसाधन विभाग, मप्र स्वास्थ्य विभाग उसके अंतर्गत कार्यरत, खाद्य एवं औषधि, मप्र नागरिक आपूर्ति, गृह जिला पंचायत आदि में बैठाया गया, ताकि वो सिंहस्थ आयोजन की आड़ में जनसुविधाओं के लिए सन् 2010 से आवंटित रुपए 10000 करोड़ से ज्यादा के धन में आसानी से 50 से 60 प्रश तक धन डकारकर उसे भी 10-20 प्रश धन की कमाई लौटा सके, यही कारण था कि सिंहस्थ जनसुविधाओं के नाम पर मुक्त हस्त से जन-धन लुटाने के बाद भी कार्य पूरे नहीं हो सकते, क्योंकि यहां पर सिंहस्थ के नाम काम कम से कम यहां तक कि अरबों रुपए के कार्य केवल कागजों पर ही पूरे कर दिए जाकर मु.मं., मंत्रीयों से लेकर प्रधान सचिवों, सचिवों प्रमुख अभियंताओं, आयुक्तों, संचालकों से लेकर उपर्यत्रियों, निरीक्षकों, बाबुओं तक सबको दोनों हाथों से भ्रष्टाचार कर धन उलीचने का 12 साल में मौका मिला है। (शेष 8 पर)

बजट 16-17 जनता से लूट- पूंजीपतियों पर मत लुटाओ जन-धन

रक्त पिपासु दानव मोदी-सत्ता बाप की जागीर नहीं, चारों तरफ बर्बादी

रुपए 17 का पेट्रोल रुपए 70 में, हर सेवा पर कर, उस पर भी सेस कर, अपनी विदेश यात्राओं में खर्च किए रुपए 40 लाख करोड़, जनता से वसूलने का बजट, जबसे सत्ता संभाली हर, तरफ कृषि फसलें बिगड़ी, हजारों कृषकों ने की आत्महत्याएं, बेरोजगारी बढ़ी, चारों तरफ महंगाई का बोलबाला, बस पूंजीपत्तियों के घर भर, जनता को लूटवा रहा

भारतीय पुराणों में कहा गया है कि जहां नीच और दुष्ट राजा होगा, वहां प्रकृति भी जनता का साथ नहीं निभाती, जबसे मोदी ने सत्ता संभाली चारों तरफ धूर्त ने बर्बादी कर डाली, किस्मत से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रो-क्रूड कीमतें गिर कर 120 डॉलर से 30 डॉलर पर आ गई तो भी पेट्रोल की कीमतें रुपए 80 से गिरकर रुपए 65-70 के बीच ऊपर-नीचे होती रही। क्योंकि सत्ता मिलते ही ये गरीब चाय बैचने वाला सत्ता को बाप की जागीर समझ लाखों रुपए के सूट पहन रुपए 40 लाख करोड़ से ज्यादा बर्बाद

कर आया, उसकी वसूली के लिए पूंजीपतियों को खूब छूट दी। 15-16 के और 16-17 के बजट में और जनता से वसूलने के लिए उसके मुंह से इस रक्त पिपासु ने दाल, रोटी तक छीन ली। रुपए 50-60 प्रति किलो की दाल इन पूंजीपति अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला, आईटीसी, युनि लीवर व अन्य के गोदामों में भरवाकर रखवा दी और रुपए 200 से 250 तक बिकवा दी। उस पर शिगूफा ये कि इन पूंजीपतियों को सरकारी खजाने से अनुदान देकर दालों की कीमत स्थिर की जाएगा रुपए 150 पर।

15-16 के बजट में अनेकों सेवाओं पर सेवा कर लगाया था, 16-17 बजट में भी सेवाकर के दायरे में बाल कटाई से लेकर, होटलों में खाने ठहरने पर भी कर लगाया और बढ़ाया, छोटे निवेशों पर ब्याज दर घटाना और छोटे ऋणों पर ब्याज मनमाने तरीके से वसूला जाता है।

(शेष 7 पर)

मप्र बजट 2016-17 झूठे आंकड़ों की बाजीगरी... ऋण लो... घी पियो.. की आदत

बजट के माध्यम से लूट और अपनों की कमाई व्यवस्था जनता का आंसू

बजट पेश करने के बाद अनुपरूक मांगे और धन की व्यवस्था की जालसाजियां वित्त शोषण मंत्री जयंत मलैया बनते ही वित्त प्रबंधन बिगाड़ा, बजट में सिंहस्थ के लिए 3500 करोड़ कहां से आया, विद्युत के लिए 20000 करोड़ क्यों जब रुपए 5000-7000 करोड़ की विद्युत निर्यात की जाती है अन्य प्रदेशों को, जनता से भी 10-20 गुना कपट से वसूली

मप्र को अर्थशोषण मंत्री जयंत मलैया ने 27 फरवरी 16-17 का बजट पेश किया, बजट पेश करने केसे लेकर 31 मार्च तक आखिर क्यों अनुपूरक बजट बार पेश किए गए, जब सिंहस्थ के लिए श्रव्य-दृष्य और मुद्रित प्रचार-प्रसार माध्यमों से प्रदेश में देश में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ही रुपए 500 करोड़ से ज्यादा खर्च कर दिए जिसमें प्रदेश के और देश के समाचार पत्रों, पत्रिकाओं पिछले 2 माह में 20-20 पेज से ज्यादा के विज्ञापन, हर दिन 30 मिनट से लेकर 60-60 मिनट तक विज्ञापनों के स्लाट दिए गए आखिर ये जन-धन कहां से खर्च किया, जबकि जनसंपर्क को तो वर्षभर के विज्ञापनों के लिए मात्र रुपए 252 करोड़ का ही बजट था। फिर जनसंपर्क में बैठाए गए संचालकों जिसमें मंगला मिश्रा, जिसकी डिग्रीयां तक फर्जी है। सूचना के अधिकार में पत्रकारों को जानकारी देने की तो दूर बुलाकर मार-पीट करने के बाद भी झूठी एफआईआर लिखवा दी जाती है।

मार्च-अप्रैल मई में रुपए 3000 करोड़ का धन लुटाया गया। इस धन की व्यवस्था भी अनुपूरक बजट में जनधन से जनता की आंखों से बचाने के लिए ही की गई वैचारिक महाकुंभ के नाम पर रुपए 200 करोड़ के जनधन की व्यवस्था केवल साधुसंतों को रिझाने और अपनी वाहवाही करवाने के लिए ही की गई,

(शेष 9 पर)

साप्ताहिक समय माया

संपादकीय

मध्यमवर्गीय

पूरे विश्व के सभी राष्ट्रों पर लोकतांत्रिक सरकारे है। सारी सत्ताएं मध्यमवर्गीय जनता के दम पर ही टिकी है। जो न गरीब है, न अमीर है। परंतु सारे नियम कानूनों को मानते हैं। लोकतांत्रिक सरकारों को चलाने के लिए सारे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर चुकाते हैं। समाज के सारे नियम, कानून, धार्मिक रीति-रिवाजों, पारिवारिक रीति रिवाजों को निभाते हैं। अपने बच्चों को सभ्य सुरक्षित बनाने, परिवार, समाज और राष्ट्र की सेवा में परम्पराएं निभाने में ही इनका जीवन होम हो जाता है।

बड़ा मानता नहीं, छोटा जानता नहीं, बस मरण है तो मध्यमवर्गीय का। जिसके दम पर ही न केवल अमीर-गरीब वरन् सरकारें भी चलती और पलती हैं। यह सर्वमान्य सत्य होने के बाद भी सबसे ज्यादा छल, कपट, करों का बोझ कानूनों की मार उसे ही झेलना पड़ती है। इन्हें कहीं से कोई राहत नहीं मिलती है, जबकि न केवल धूर्त राजनीतिज्ञों, राजनीतिक दलों के साथ ही संयुक्त व्यावसायिक देशी-विदेशी कंपनियों के व्यावसायिक विस्तार के, ठगोरों, जालसाज, कंपनियों के भ्रष्ट सरकारी नौकरशाहों से बाबू कर्मचारियों, भय की दुकानदारी चलाने वाली बीमा कंपनियों, डकैत सरकारी व गैर सरकारी संचार कंपनियों, विद्युत कंपनियों, उपभोक्ता सामग्री बैचने वालों से उत्पादक कं. आदि तक के सबसे बड़े केन्द्र बिंदु होते हैं। इन गिद्धों के लक्ष्य संधान कमाई आदि के लिए।

वर्तमान में चाहे देश का प्रधानमंत्री मोदी जिसने अपनी 32 से ज्यादा विदेश यात्राओं में रुपए 40 लाख करोड़ ट्वीटर, फेसबुब जैसी साइटों पर ही चुनाव पूर्व से लेकर वर्तमान तक खर्च किए गए रुपए 10 लाख करोड़ से ज्यादा का जो खर्च किया गया तो इस मध्यमवर्गीय से ही लूट कर इन साइटों पर प्रशंसकों की खरीद और उन पर अपनी प्रशंसा गाने, सुनाने वाले भांडो पर ही खर्च किया गया। विज्ञापनों, जो दृष्य, श्रव्य और मुद्रित प्रसार माध्यमों पर अपने विज्ञापनों, समाचारपत्रों, के साथ ही अपने विरूद्ध अपने कुकर्मों की व्याख्या प्रदर्शन को रोकने के में भी खर्च किया गया बैंकों में इस मध्यमवर्गीय को उसकी जमाओं पर जो ब्याज मिलता है, उससे कहीं ज्यादा उससे एटीएम क्रेडिट, डेबिट कार्ड, शेष कम होने, एसएमएस भेजने, लेजर का पन्ना खर्च होने धन निकालने और जमा करने के नाम व अन्य सेवा शुल्कों के नाम से लाखों करोड़ लूटा गया, क्योंकि गरीबों के पास बैंकों में जमा करने लायक धन नहीं है। अमीरों को जो करोड़ों रुपए के काले धन के मालिक है जिसमें न केवल देश के बड़े उद्योगपतियों, पूंजीपतियों के साथ केन्द्र व राज्यों के भूतपूर्व वर्तमान मंत्री हैं। वरन राष्ट्र की सबसे बड़ी धूर्त प्रशासनिक बनाम परपीड़न लॉबी या इंडियन एव्यूसिंग सर्विस, इंडियन क्राइम प्रोटेक्शन सर्विस या आईपीएस, इंडियन फॉरेस्ट इटिंग सर्विस, फॉरेन सर्विसेज, इंडियन रेवेन्यु सर्विस के महामक्कार, भ्रष्ट धूर्त डकैतों का काला धन भी देश की बैंकों की अपेक्षा न केवल स्विस वरन् इंग्लैंड, फ्रांस, कनाडा, आस्ट्रेलिया, जर्मनी, जापान से लेकर थाइलैंड मारीशस, बांग्लादेश और चीन की बैंकों तक में भरा पड़ा है। और भारत में ये पूंजीपति, उद्योगपति सेवा प्रदाता भारत की बैंकों से लाखों करोड़ रुपए का कर्ज लेकर व्यवसाय कर रहे है। वरन् इस बहाने आयकर भी नहीं दे रहे, ये सारा धन भी मध्यमवर्गीय लोगों का ही है। अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला, आईटीसी, वीडियोकान के धूत, भारती मित्तल, हिंडालको, जिंदल, रेड्डी जैसे हजारों पूरे देश की मध्यमवर्गीय जनता का हजारों करोड़ हर दिन संचार व अन्य उपभोक्ता वस्तुओं के माध्यम से लूटकर विदेशों में जमा कर हर प्रकार की न केवल टैक्स चोरी करते है उनके कर्मचारियों तक को पर्याप्त वेतन नहीं दिया जाता और दूसरी तरफ अपनी संपत्तियों को बैंक में गिरवी रखकर उस पर बैंकों के ऋणों से लंबे मोटे खेल खेला करते है।

कानूनों के पालन में भी मध्यमवर्गीय ही ज्यादा मरता और पिसता है। यातायात के नियमों के पालन से लेकर नगर निगमों, पालिकाओं के जलकर, सफाईकर, संपत्ति आदि का भी वही भुगतान वही समय से पूर्व भुगतान करता है। इसी के दम पर भ्रष्टाचारियों को लूटने के लिए धन मिलता है। और सत्ताभोगी इन्हीं के धन से करोड़पति-अरबपति बनते हैं। इन्हीं का धन सरकार विकास के नाम, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, सड़कों, विद्युत, जल आदि के नाम पर लुटाती और लूटती है। उसका ही इन्हें लाभ नहीं मिल पाता, इन्हें अपना और अपने बच्चों के विकास के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कों, जल, विद्युत, आदि के बिल, किश्तें, शुल्क जमा करते-करते ही इस मध्यमवर्गीय का जीवन दौड़ते भागते समाप्त हो जाता है। लोकतंत्र के लूटेरे सत्ताधीश जिस मध्यमवर्गीय से करों के बहाने 20 से ज्यादा प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष करों से लूटते हैं। जन-धन को अपने बाप की जागीर समझ और अपने आपको खुदा मानने जैसे उस धन का भोग निर्धारित करते हैं उसमें सबसे पहले स्वलाभ और दूसरा वोट बैंक सर्वापरि खर्च के निर्णायक बिंदु होते हैं। स्वलाभ के लिए उद्योगपतियों, पूंजीपतियों, सेवा प्रदाताओं को लाभ पहुंचाकर उनसे अपना हिस्सा बटोर लिया जाता है, वोट बैंक के नाम ग्रामीणों, आदिवासियों, अनुसूचित, पिछड़ा वर्ग, और किसानों गरीबों के नाम पंचायतों में ग्रामीण विकास के नाम पर आदिवासियों अनु. जाति, पिछड़ा वर्ग के नाम पर स्वास्थ्य शिक्षा, छात्रवृत्तियां मध्याह्न भोजन, मनरेगा महिला बाल विकास, सस्ता अनाज, कृषकों के नाम कृषि व उद्यानिकी को व अन्य के नाम पर लाखों करोड़ जो मध्यमवर्गीय के खर्च कर अपना वोट बैंक ही सुदृढ किया जाता है। उसकी आड़ में मध्यमवर्गीय और गरीबों को रोटी मिले न मिले, किसानों को बोने के लिए खेत, पशुओं को चरने के लिए चरनोई रहे न रहे, पर अपने उद्योगपति मित्रों के लिए, जिन्होंने इसी मध्यमवर्गीय को लूटकर चुनावी चंदा दिया था, मध्यमवर्गीय से लूटे गए करों से जमीनें छीनकर उपलब्ध करवाई जाती है। ताकि वो अपने उद्योग लगा सके, बुलेट ट्रेन के स्वप्न दिखाए जाते हैं। उस जन-धन को खर्च करने के लिए उससे नहीं पूछा जाता कि तुम्हारी और राष्ट्र की भलाई में क्या सबसे ज्यादा आवश्यक है।

मोदी के बजट में सरकारी बैंकों से प्राप्त लाखों-करोड़ के लाभ की आय पेट्रोल कंपनियों के जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 120 से घटकर 22-24 डॉलर आ जाने के बाद भी पेट्रोल की कीमतें रुपए 80 से कम करके रुपए 68 पर बैचकर चौगुना लाभ कमाया जा रहा है। दूरसंचार कं. की लाभ, बीमा कं. का लाभ व अन्य प्रकार के लाभांश व अंश क्या हमारे धूर्त गुजराती प्रधानमंत्री मोदी की विदेश यात्रा में समाप्त हो गया, जो आयकर सीमा बढ़ाने को तो दूर इस मध्यम वर्गीय पर और करों का बोझ लाद दिया गया, इसके उपरांत भी धन की कमी को पूरा करने जन-धन से खड़े लाभांश देने वाले भारत संचार निगम, राज्यों के विद्युत मंडल, रेलवे सभी तेल कं. सभी राष्ट्रीय कृत व स्टेट बैंक, बीमा कं., सैकड़ों अन्य शास. उपक्रमों का विनिनिवेश या हिस्सेदारी बैचकर अपने देशी-विदेशी मित्रों से मोटा कमीशन डकार ओने-पौने में बैचने की जरूरत आन पड़ी, बात यहीं तक नहीं रूकी है, शास. शिक्षा व संस्थानों, जिसमें प्रबंधन चिकित्सा अभियांत्रिकीय, रक्षा संस्थानों तक को ये भूखेरा जन पार्टी निजीकरण करने पर तुली है। पूर्व में भी भाजपा गठबंधन शासनकाल में भी अरुण शौरी ने अरबों करोड़ का कमीशन डकारकर ओने-पौने दामों में कोरबा का वाल्को जैसे कई उपक्रमों को बड़े-बड़े उद्योगपतियों को बैच खाया, फिर अंबानी बंधुओं को रुपए 2 लाख करोड़ का ऋण, अडानी, को रुपए 80000 करोड़ से ज्यादा का जेपी एसो. को रुपए सवा लाख करोड़ टाटा, बिरला की 4000 से ज्यादा उद्योगों के नाम रुपए 2-2 लाख करोड़ से ज्यादा के ऋण, जूम डेवलपर्स को रुपए 20000 करोड़ का ऋण दाऊद की जेट एयरलाइंस और लोटस की देशभर में फैली इलेक्ट्रानिक्स की स्टोरों को लाखों करोड़ का ऋण आखिर सब है तो मध्यमवर्गीय का ही पैसा, ऊपर से रिजर्व बैंक का प्रशासक राजन कहता है कि सूचना के अधिकार में कोई जानकारी नहीं दी जाएगी, जैसे इस शूकर के बाप की जागीर हो रिर्जव बैंक। सारे बैंकों के अय्याश सुरा सुंदरी और जुए के प्रेमियों को ये उपलब्ध करवाओं और ले जाओ लाखों करोड़ आखिर सरकार इन शूकरों के व्यक्तिगत तौर पर अपना बनाकर प्रकरण दर्ज क्यों, नहीं करती, फिर जब देश का प्रधानमंत्री मोदी राक्षस लाखों करोड़ इसी मध्यमवर्गीय से लूट का धन विदेश यात्राओं पर फूंकने पर तुला हो, तो फिर दूसरों पर अंगुली उठाना औचित्यहीन है, यथार्थ में-

''हाय मध्यमवर्गीय तेरी यही कहानी। दिल में शोषण की कसक, चेहरे पर झूठी ठसक, अकेले में आंख में पानी।''

कृषि कर्मणा पुरस्कार खरीदी और वाहवाही लूटने के पीछे का यथार्थ

50 हजार से ज्यादा कृषि और उद्यानिकी के तालाबों की चोरी

खेत का पानी खेत में, बलराम तालाब, सूक्ष्म सिंचाई, टपक सिंचाई के अनुदान में अरबों का घोटाला एक ही किसानों के नाम से कृषि और उद्यानिकी दोनों में अनुदान के अरबों हजम किये, मंत्री बिसेन और महदेले के साथ दोनों के प्र.स., सचिव और संचालक मोटा धन हजम कर भ्रष्टों को पाल और बचा रहे, इन घोटालों में न केवल तालाब वरन् खेत और खसरा नंबर भी चोरी हुये हर जिले में अनुदान बंटने के बाद

मप्र के महाभ्रष्ट और पाखंडी भुखेरा जन पार्टी का मु.मं. चौहान इस बार भी देश में श्रेष्ठ कृषि उत्पादन का कृषि कर्मणा पुरस्कार मप्र केडर के इंडियन एव्यूसिंग सर्विस अधिकारी जो दिल्ली के मंत्रालयों में पदस्थ है उनके माध्यम से मोटा धन खर्च कर खरीद लाये, जो उपलब्धियां दिखाई गई, जिस झूठे आंकड़ों के दम पर कृषि उत्पादन बढ़ाकर दिखाया गया, 90 प्रश फर्जी थे, मोदी दानव के आने के बाद से न केवल देश की 125 करोड़ जनता वरन् प्रकृति यथा वातावरण, पर्यावरण, ऋतुयें यथा बारिश, शीत, गर्मी भी विचलित हो उठे, उसके 2014-15 की न केवल खरीफ, वरन् रबी, फिर 2015 की खरीफ-रबी दोनों की फसलें भी बिगड़ गई, जिससे सैकड़ों किसानों ने आत्महत्याओं कर ली। फसलें बिगाड़ने के बाद किसानों को 2014 की खरीफ की 2015 की खड़ी दालों, गेहूं आदि की रबी फसलों, पुनः 2015 की खरीफ पहले अल्प और बाद में अतिवृष्टि से फसलों की बर्बादी का ही मुआवजा नहीं मिला और जहां मिला वहां पर खाद बीज की लागत भी नहीं निकली, किसान भारी कर्जे में डूबने के कारण आत्महत्या करने लगा, इस सबके बाद में भी प्रदेश का मु.मं. शिवराज जन-धन का पैसा खर्च करके, रुपए 2000 करोड़ से ज्यादा खर्च मीडिया पर लूटाकर अपनी प्रशंसा करवा, कृषि कर्मणा पुरस्कार लाकर सिद्ध कर दिया जैसे कि प्रदेश की धरती पर बहुत अच्छी फसल हुई और चारों तरफ किसान बहुत खुश है। कृषि विभाग मप्र का बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। जबकि यथार्थ यह है कि केन्द्र व राज्य की कृषि उत्थान मूलक योजनाओं से 20 से 40 प्रश धन कृषि मंत्रालय में बैठे प्रधान सचिव राजौरा से लेकर नीचे ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी राजस्व का पटवारी तक हर कदम-कदम पर फैले भ्रष्टाचार में हजम कर रहे हैं। जिसकी सत्यता पूरे प्रदेश में रंगे हाथों रिश्वत वसूलते पटवारी और कृषि अधिकारियों को लोकायुक्त ने पकड़ा ही है।

दूसरी और उद्यानिकी जो सब्जियों, मसालों, फलों, जड़ी बूटियों, फूलों की खेती आदि के विकास और उत्पादन के लिये किसानों को अल्पकालीन और दीर्घकालीन उत्पादन के लिये न केवल खेतों, उद्यानों के साथ ही नगरी क्षेत्रों में भी घरेलू स्तर पर कागजों पर ही फल, फूल, मसालों और जड़ी बूटियों 50 से 90 प्रश पैसा हजम कर जाता है। कृषि और उद्यानिकी दोनों ने ही खेत का पानी खेत में, बलराम तालाब योजना के अंतर्गत पिछले दस वर्षों में पूरे प्रदेश के 3 लाख से ज्यादा तालाब खुदवाये, जिस पर 33 प्रश से लेकर 100 प्रश तक अनुदान की व्यवस्था थी, कृषि विभाग के ही सूत्रों के अनुसार यदि पूरे तालाब खुद जाते और उनमें वर्षा जल एकत्रित किया जाता तो कृषि भूमि ही नहीं बचना चाहिए थी, अर्थात 50 प्रश से ज्यादा तालाब कृषि और उद्यानिकी के बनाये हुये न केवल चोरी हो गए, वरन् खसरा नंबर और खेत भी तालाबों के साथ चोरी हो गये, अकेले सिहोर जिले में जब उ.सं. नेमा पदस्थ था। 2006 से 8-9 तक में ही 1200 तालाबों में से 830 चोरी हुये थे, देवास में भी उ.सं. के अग्रवाल और मृदा संरक्षण अधिकारी टीसी छावनिया के रहते हुये मात्र टोंक, सोनकच्छ में ही 385 तालाब चोरी हो चुके हैं। जबकि देवास में उ.सं. तोमर के रहते हुए 90 प्रश दोनों योजना के तालाब चोरी हो चुके हैं। उसने कृषि विभाग के तालाबों पर ही अनुदान की बंदरबांट की यही हाल इंदौर, उज्जैन संभाग के 15 जिलों के साथ ही पूरे प्रदेश के 51 जिलों का है। अर्थात केवल तालाबों के नाम से ही पिछले 10 वर्षों में कृषि और उद्यानिकी ने मिलकर रुपए 2000 करोड़ से ज्यादा कागजों पर ही तालाब खोदकर हजम किये, जबकि यही हाल सूक्ष्म सिंचाई, टपक सिंचाई के लिये पाइप, स्प्रिंकलर आदि बांटने में भी एक ही किसान को या तो फर्जी बिलों पर भुगतान कर, या दोनों ने कृषि और उद्यानिकी ने पाइप और कृत्रिम वर्षा के फव्वारे बांटे और इसमें भी रुपए 2000 करोड़ का घोटाला किया, ये मात्र 2 योजनायें ऐसी अनेकों योजनाओं में अरबों रुपए का भ्रष्टाचार किया गया है, परंतु शिकायतों में जांच फिर जांच के बाद कार्यवाही में दोनों विभागों के संचालक, सचिव, प्र.सं. और मंत्री तक करोड़ों रुपए बांटता है, तो ये ही हरामखोर मोटा धन हजम कर न केवल जांच दबा देते हैं, वरन् प्र.सं. राजेश राजौरा उन्हें मनचाही पदस्थापना भी दे देता है। सूचना के अधिकार में जानकारी मांगने पर मंत्रालयों से लेकर जिला, संभाग से तहसीलों तक सारे जालसाज बहाने बताकर खुले में टाल जाते हैं। करते रहिये अपीलें। इंदौर में बैठा उ.सं. मीना ने 4 वर्ष से ज्यादा हो गए, पर वो इंदौर में बैठी कंपनी जो बीज व अन्य कृषि सामग्री बेचती हैं, इनसे उ.सं. मीना सेटिंग कर राजेश राजौरा को सीधा धन भेज पूरे प्रदेश में माल निकालने की व्यवस्था करता है। दूसरी और संचालक मीना धूर्त, संयुक्त संचालक इंदौर-उज्जैन की अपीलें हजम कर लिखता है मुझे अधिकार नहीं है। हरामखोरों पैसा डकारने का अधिकार है। जवाब देने क्या तुम्हारे पुर्खे आयेंगे।

नर्मदा घाटी भ्रष्टाचार विकास प्राधिकरण लूट सके तो लूट

13 वां समय विस्तार, नर्मदा क्षिप्रा में रु. 396 करोड़ में रु. 650 करोड़ का भुगतान

8 वर्ष तक धार में, अ.यं. का और 6 वर्ष मु.अ. अजनारे पर भ्रष्टों की कृपा भ्रष्टाचार से धन हजम करने के लिये ही, प्र.स. और उपाध्यक्ष पर रजनीश वैश्य भी 5 वर्षों से ज्यादा नर्मदा घाटी में क्या केवल लूट के लिये ही

म.प्र. का मुख्यमंत्री शिवराज मिट्ठू मियां जनधन को लूटने और लुटाने के साथ कर्ज लेकर घी पीने का आदी हो चुका है। इसके लिए बड़ी योजनायें बनाना, उनमें जन-धन का अनाप-शनाप पैसा खर्च दिखाकर हपड़ना इन हरामखोर जालसाजों की नियति बन चुकी है। इस संदर्भ में मु.मं. शिवराज की नर्मदा क्षिप्रा सिंहस्थ शेड़ परियोजना जिसका बहुत प्रचार-प्रसार कया गया। इसकी हकीकत यह है कि इसकी लागत प्राधिकरण के भ्रष्ट इंजीनियरों ने रु. 432 करोड़ की बनाई थी। जिसका ठेका दक्षिण की मेघा इंजीनियरिंग हैदराबाद ने रु. 396 करोड़ में लिया था, जिसे 364 दिन में बनकर नव. 13 में पूरा होना था, जिसमें कं. अभी तक इंदौर में डटी रहकर कार्य कर रही है। बेशक वर्तमान में उज्जैन की क्षिप्रा नदी में वही पानी बह रहा है। परन्तु उसमें सूवों के अनुसार रु. 650 करो का भुगतान किया जा चुका है। जबकि पाइप लाइन जो 2 मी. परिधि के स्थान पर 1.80 मी. और 2 से.मी. एमएस स्टील के स्थान पर 1.6 से.मी. मोटी थी, जबकि प्राक्कलन 2 मी. परिधि और 2 से.मी. मोटाई का होने के बाद भी ठेकेदार कं को फायदा पहुंचाकर पैसा हजम किया गया, इस पाइप लाइन को बड़वाह से मूल उद्गम स्थल केवड़ेश्वर महादेव के पास से ले जाकर पिवडाय के आगे सोनवाय में नहर के माध्यम से पानी को क्षिप्रा के दृष्य बहाव स्थल पर छोड़ा गया, जो नहरें बनाई गईं वो खेतों के तल से जानबूझकर आधा फूट नीचे तक कांक्रीट की गई कहीं 18-19 फुट चौड़ी तो अधिकांश जगह तीन कि.मी. तक 15 फुट चौड़ी और बेडलेवल पहले 8 और 500 मी. के बाद 5 तीन कि.मी. तक बनाया गया। कांक्रीटिंग इतनी घटिया सरिये के साथ की गई कि मात्र 2 माह लगातार पानी बहने में तल आजू-बाजू चटक के साथ 1-1 फूट चौड़ी तक टूट चुकी है। पाठकों को बता दें कि इस नहर में फर. 2016 से ही लगातार पानी बह रहा है।

जोंकि 25 मई से अगले 11 वर्षों तक के लिये बंद कर दिया जायेगा और चालू करने के नाम पर हर वर्ष रु. 25-50 करोड़ हजम किये जायेंगे क्योंकि खेतों के तल से आधे फुट नीचे की गई। सीमेंट कांक्रीट का उद्देश्य ही है कि बरसात में खेतों से मिट्टी बहकर नहर में भर जायें, ताकि नहर बंद करने का बहाना मिल जाये और सरकार या नर्मदा घाट विकास प्राधिकरण को रु 24 लाख प्रतिमाह बिल भरने से मुक्ति मिल जाये, दूसरी तरफ चूंकि अब विद्युत कं. है, झूठा बिल बनवाकर आसानी से 70-30% की सौदेबाजी कर पैसा हजम किया जा सके, जिस उज्जैनी में नर्मदा क्षिप्रा मिलन की नौटंकी में लालकृष्ण आडवाणी, सुषमा स्वराज, नितिन गडकरी, शिवराज आदि का गिरोह शामिल होकर फर. 14 में उद्घाटन किया था, वह पाइप लाइन मात्र सवा फुट चौड़ी है, वर्तमान में सप्ताह में मात्र 3-4 दिन 2-2 घंटे चलाई जाती है। ताकि उज्जैनी में यथार्थ में उस गांव का नाम मूंडला दोस्तदार है मैं बने पहाड़ी के नीचे बगीचे के स्नान कुंडों में पानी भरा रहे और पर्यटकों के लिये जलक्रीड़ा में काम आ सके, जबकि उसमें 24 घंटे सातों दिन पानी चलाकर उज्जैन से पिवडाय सोनवाय तक एक कहीं सीसी और कहीं कच्ची खोदकर भी पाइप लाइन के ऊपर भी एक कहीं 1 फुट बेड लेवल की कहीं 2 से 5 बेड लेवल ऊपर कहीं 6 फुट कहीं 8 व कहीं-कहीं 10 चौड़ी तक नहर नहर बनाई गई थी, जिसमें भी लगभग 20 करोड़ से ज्यादा खर्चा किया गया, जिसमें कभी ऊपर से पानी, सोनवाय की मुख्य पाइप लाइन के पानी में मिलाने की योजना पर क्रियान्वयन नहीं हो पाया। उसके मूल कारणों में बीच-बीच में 100-200 मी. तक नहर का कच्चा होना और दूसरे 24 घंटों 7 दिन उज्जैनी में पंप चलाकर पानी न पहुंचाना ही था इसलिये वह रु. 20 करोड़ में रु. 4-5 करो का कार्य कर रु. 15 करोड़ से ज्यादा तत्कालीन कां. यं. जोशी और बाद में धनोरे के माध्यम से अ.यं.ह.रा.चौहान, मुअ. अजनारे, सदस्य इंजीनियरिंग शिवहरे, उपाध्यक्ष रजनीश वैश्य, सीएम चौहान तक बंटा, यथार्थ में रु. 250 करो में से रु. 50 करोड़ का ही कार्य हुआ और रु. 200 करोड़ भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया।

संभाग 32 के का.यं. धनोरे और मंडल क्र. 11 खेड़ीघाट के अ.यं. चौहान को रु. 2 करो के एक फर्जी बिल का भुगतान न करने पर मु.अ.

अजनारे के कहने और लापरवाहीपूर्ण कार्य करने की अनुशंसा पर समय विस्तार पर चल रहे भ्रष्ट और जालसाज सदस्य अभियांत्रिकीय और प्र.स.व उपाध्यक्ष वैश्य ने 19 मार्च को फाइल भेज कर 23 मार्च को मु.मं. चौहान से पुनः सेवायें जल संसाधन विभाग को सौंप दी। 29.30 मार्च को आदेश चला और 4 अप्रैल को बिदाई देकर अपने मनपसंद भ्रष्ट जालसाजों का मंडल 11 का प्रभार 10 मंडल धार के बघेल को सौंप दिया गया जबकि बघेल जैसा अ.यं. को कार्य सौंपने का औचित्य ही यही है कि तो भ्रष्ट हरामखोर चुपचाप कमीशन लेकर आंख मींचकर मंडल क्र. 10 व 11 में बैठकर सदस्य अभि. और ठेकेदार की हां में हां कर हस्ताक्षर करता रहे। उसे न.घा.वि.प्रा. का अ ब स नहीं आता। वह 6 माह पहले ही ज.सं.वि. से आया है। उसके वा.क. व इंजिनियर जैसा नचाते हैं। मूढ़ और जड़ यह वैसे ही नाचता है। 12/5/06 को अपील की सुनवाई में बुलाकर सहा. यंगी के पास बैठाकर का.यं. की सुनवाई करवाई गई और संभाग क्र. 20 के गुप्ता को अतिरिक्त प्रभार सं. 32 का सौंपकर मेघा इंजि. का रु. 2 करोड़ व अन्य बिलों का लाखों में कमीशन ऊपर तक बांटा गया, इसके पूर्व रु. 185 करोड़ का भुगतान नर्मदा गंभीर जोड़ परियोजना में किया गया। इसमें 10% अर्थात रु. 18 करोड़ की बंदरबांट में 1% हिस्सा जाने से पूर्व अ.यं. 11 खेड़ीघाट भी लेकर गया और अ.यं. 10 धार, का.यं. धामनोद, का.यं. 32 ने सं.क्र. 8, 20 के साथ अजनारे, शिवहरे, रजनीश वैश्य से मु.मं. और नर्मदा घाटी राज्यमंत्री लालसिंग आर्य को भी पहुंचा। बस छोटा से भ्रष्टाचार एमएस स्टील पाइप की स्तर से 10% मोटाई और 10 % परिधि घटा दी गई। यही हाल नर्मदा क्षिप्रा में किया गया था, जब तात्कालीन का.यं. से इस संबंध में बात की गई तो हरामखोर जालसाज ने दलील दी कि क्या फर्क पड़ता 1.80 मी. की परिधि और 2 सेमी की मोटाई 1.7 से.मी. है। जब कच्ची-पक्की नहरों के बारे में पूछा तो जवाब मिला कि बिना भूअर्जन किये नहर बनाई गई। जल्दी-जल्दी में, ताकि पानी पहुंचाया जा सके क्षिप्रा तक, जिसने पक्की करने को कहा उसके खेत में पक्का बना दी, जिसने खोदने के लिये कहां उसकी कच्ची खोद कर छोड़ दी, दूसरी इस 16 कि.मी. लगभग लंबी नहर में निरीक्षण की 10 चौड़ी कच्ची सड़क तो दूर कुछ भी नहीं है। दोनों तरफ खेतों के तल से कहीं 8 सेमी मोटी तो कहीं 7 से.मी. मोटी कांक्रीटिंग करने पर पूर्व की स्तर की मोटाई का प्लास्टिक भी नहीं बिछाया गया।

सं.क्र. 32 में पिछले साल मई में जो पैसे जमा किये थे, उसकी जानकारी भी नहीं दी गई और नहीं फर. में जमा किये पैसों की जानकारी मात्र शूकरों ने अपने भ्रष्टाचार के कृत्यों को छिपाने के कारण नहीं दी, लोकायुक्त, मु.तकनीकी परीक्षक बेशक सब भ्रष्ट और वसूलीबाज है द्वारा बारीकी से जांच की जाये तो उपयंत्रीयों सहा.यं., कार्य. यंत्रीयों, अधीक्षण, मुख्य सदस्य, अभियंता और उपाध्यक्ष तक सब लपेटें में आएंगे।

न.घा. भ्रष्टाचार विकास में कदम-कदम भ्रष्टाचार की गाथायें भरी पड़ी हैं। जो नहर नव.08 में ओंकारेश्वर की दायीं-बाईं पूरी होनी थी। उसमें 13 वां समय विस्तार इसी जालसाज अजनारे द्वारा अनुशंसित कर मुख्यमंत्री से स्वीकृत करवाया गया है। मु.अ. अजनारे की मूढ़ता और भ्रष्टाचार से धन इकट्ठा कर यथायोग्य भेंट पूजा सबके पद और गरिमा के अनुकूल बांटने के कारण ही बंदा 8 वर्ष तक एक छत्र अ.यं. धार मंडल में बैठकर डकारने के साथ ही मु.अ. निचली नर्मदा परि. में प्रभारी बन चालबाजी से सौंप दिया गया। ऐसे महान भ्रष्ट की सेवायें बोधि में जल संसाधन विभाग को भी तुरंत सौंपी जानी चाहिये। बेशक दोनों स्थानों पर बैठने की मोटी रायल्टी आकाओं को चुकाने के बाद ही ये सौभाग्य दिया गया।

इंदिरा सागर नहरों में बैठाये गये मु.अभि. रोहित रमेश भी मोटा धन खर्च करके ही वहां बैठाया गया है। स्वाभाविक है, सूचना के अधिकार में जानकारी देना सारा खेल बिगाड़ देगा, इसलिये ये हरामखोर पत्र, अपील सब हजम कर गया कहा वो सज्जन बाबू देखते हैं। जब वहां जाकर सज्जन बाबू जी पूछा तो बोले साहब कुछ कहते ही नहीं, अर्थात सब हजम कर जाओ, आखिर जनधन को ये हरामखोर शूकरों की फौज कैसे अपनी बपौती मानकर भ्रष्टाचार में हजम करती है। इसके उदाहरण पिछले 15 वर्षों से समय माया लगातार छाप कर जनता को दे रहा है। परन्तु गिद्ध सत्ताधीश मुख्यमंत्री शिवराज अपना टुकड़ा नोंचकर हजम करने में लगा रहता है। आखिर वर्षों सेजमे हरामखोर निकम्मे कार्यपालन यंत्रियों टेंटवाल, गुप्ता, मरीना जैसे अन्य कई सहा. यंत्रियों, उपयंत्रियों को वापस क्या जल संसाधन विभाग में भेजा जाता, जिन्होंने इंदिरा सागर को जिसे सन् 2000 में पूरा होना था सन् 2016 में भी, जिस तरह का प्राक्कलन तैयार किया गया, मुख्य, सहायक, छोटी और वितरणी नहरों का निर्माण मात्र इसलिये पूरा नहीं किया जा रहा ताकि मूल्यवृद्धि से सैकड़ों करोड़ हजम किया जा सके, जानबूझकर ऐसे निकम्मे अज्ञानी, भ्रष्टों को बैठाया गया, जिनका मूल काम भोपाल में बैठे मोटे गिद्धों को जनधन से कार्यों को संपन्न करने के नाम पर फर्जी बिल पास करें, समय विस्तार, मूल्यवृद्धि, स्तरहीन कार्य करने पर आंख मींच नाम पुस्तिकाएं भरें और भुगतान बटोरकर ऊपर पहुंचायें।

वर्तमान सदस्य अभियांत्रिकीय शिवहरे जो जबलपुर में ऊपरी नर्मदा परियोजना का मुख्य अभियंता था, ने संभाग क्र. का. यं. विनोदिया के माध्यम से कं. को 5% मशीनरी अग्रिम और 5% कार्य पूंजी का भुगतान करवा दिया था। जबकि कं. पूरा पैसा लेकर हजम कर गई, तो हरामखोर शिवहरे ने विनोदिया को नागौद थाने में एफआईआर लिखवाने भेजा कि वो कं. की मशीनें चोरी होने की झूठी रिपोर्ट लिखवा दें। पर टीआई ने मना कर दिया। रु. 799 करोड़ के इस प्रोजेक्ट में रु. 7.99 का 10 प्रश के हिसाब से हैदराबाद की पटेल और एसईडब्ल्यू को दिए थे। जब इसकी सच्चाई को समयमाया.काम की साइट पर चिपकाया गया तो इन हरामखोर जालसाज उपाध्यक्ष रजनीश वैश्य और स.अ. शिवहरे ने अपने कुकर्मों को छुपाने की कोशिश की, जबकि पुनः मप्र जल संसाधन को सौंपकर अपने पाप धोने की कोशिश की। जबकि रुपए 80 करोड़ में से रुपए 20 करोड़ के कमीशन में से सबसे हिस्सा डकारा था। का.यं. ,अ.यं.,मु.य.,उपाध्यक्ष से मंत्री और मुख्यमंत्री उस रुए 80 करोड़ की वसूली तो दूर उस पर रुपए 14 करोड़ का जुर्माना वसूलने की खबर जरूर पत्रिका में चिपकवाकर अपनी कुकर्मों और भ्रष्टाचार पर लीपापौती करने का प्रयास किया। स्लीमनावाद में खिरहनी के सलैया फाटक की 12 किमी नहर में भूमिगत सुरंग में एक इंच भी काम नहीं हुआ। 2011 से 2014 का समय भी पूरा हो गया, उसे भी समय विस्तार दिया गया।

सन् 2016 तक ताकि पोल न खुले, यही नहीं केवल बरगी, बांध की दायी बाई ओंकारेश्वर की दाई-बाई, इंदिरा सागर की मुख्य नहर में, मान जोबट, नर्मदा नगर, उदवहन कठोरा उदवहन में आदि की नहरों में हर वर्ष विस्तार, मूल्य वृद्धि, आंदोलन व अन्य कारणों की आड़ में अखों रुपए भ्रष्टाचार में सहा. यं., का.यं., आ.य., मुम, सदस्य अभि., उपाध्यक्ष सह प्रधान,सचिव हजम कर जाते है। लोकायुक्त, आर्थिक अन्वेषण को भी महीना पहुंचा दिया जाता है। इसलिए हर वर्ष अखों रुपए जनधन को हजम करने की जालसाजियों में कोई जांच नहीं होती। फिर इस मक्कार और निठल्ले प्र.स. को रजन का क्यों 5 से ज्यादा वर्षों से एक अन्य क्यों समय विस्तार दिया जा रहा है।

पेरिस जलवायु परिवर्तन चिंतन नौटंकी खास मुद्दों पर चुप्पी

पेज 1 का शेष

उसको रोकने तक की तो व्यवस्था नहीं कर पाया,तो परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में दुर्घटना जैसे कि रूस के चरेनोविल, जापान की फुकुशिमा प्लांटों में हुई थी, कैसे रोक पाएंगे, वैसे लूट, डकैती, और कमीशनखोरी में भुखेरा जन पार्टी और उसका प्रधानमंत्री मोदी कांग्रेस के भी बाप सिद्ध हो रहे है। मात्र मोटे कमीशन के लिए समयबाधित परमाणु संयंत्रों को खरीदकर एक तरफ मोटा जनधन तो दूसरी ओर जनता को तिल-तिल कर हिरोशिमा और नागासाकी की तरह मौत का सामान इकट्ठा कर रहे है। आखिर ऊर्जा उत्पादन के लिए पूरे विश्व में क्यों बंद नहीं किया जाता है, दूसरे राष्ट्रों को चमकाने धमकाने में, इसलिए क्यों और कैसे बंद किया जाए। पर्यावरण में प्रदूषण बढ़ाने में औद्योगिकरण के अवशिष्टों के साथ आधुनिकता के नाम पानी की बोतलों से लेकर खाद्य पदार्थों की पेकिंग सामग्री जिसमें मूलतः पॉलीथिन, एल्युमिनियम फाइल्स, पैकिंग का अन्य कचरे के साथ कंडोम्स, महिलाओं के मासिक रजोस्राव में प्रयोग किये जाने वाले रसायन युक्त पेड्स भी प्रदूषण फैलाने के कारकों में शामिल हैं। आखिर से सब भी हैं तो बहुराष्ट्रीय कंपनी की अपनी मोटी कमाई के बड़े स्रोत। क्या 50 वर्ष पूर्व जब सेनेटी नेपकिन्स नहीं थे, तो महिलाएं लाखों वर्षों से सभ्यता के उदय से अभी तक महीने के 4-5 दिन में समाज में निर्वहन नहीं करती थी, फिर वर्तमान में अखों रुपए के इस व्यवसाय से तत्काल नष्ट न होने वाले इन पेड्स को नालियों में शौचालयों में बहाने से भी तो जाम की व गंदगी समस्या उत्पन्न होती है, जबकि कपड़ों का प्रयोग धोकर 5-7 बार करने के बाद जलाकर नष्ट कर दिया जाता था आखिर जीएम ईंधन से उत्पन्न कार्बन के उत्सर्जन के साथ औद्योगिकरण के पेकिंग सामग्री को तैयार करने, उपयोग के बाद वर्षों तक नष्ट न होने वाले और पुर्नउपयोग न किये जा सकने वाले कचरे से उत्पन्न प्रदूषण के बारे में में इन विश्व के नौटंकीबाज दिग्गजों ने चर्चा क्यों नहीं की, क्योंकि इसकी उत्पादक बहुराष्ट्रीय कं. पूरे विश्व में लाखों टन कचरा निकालती हैं से इन सब नेताओं को मोटा कमीशन मिलता है, जिससे ये चुनाव लड़ते हैं, चाहे वो भारत का मोदी हो, अमेरिका का ओबामा, ब्रिटेन का केमरून चीन का शी जिनपिंग, फ्रांस का ओलांद। सभी लोकतांत्रिक राष्ट्रों के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जो चुनकर सत्ता में बैठाये जाते हैं। सभी हैं तो पूंजीपतियों की कठपुतली रखैल, जिनके चंदे से ये चुनाव जीत कर सत्ता संभालते है। किसी को भी यथार्थ जनहितों से पर्यावरण हितों से सरोकार नहीं होता। इस पेरिस सम्मेलन के पीछे भी हो सकता है कि पूरी दुनिया के स्वचलित वाहनों की लॉबी हो जिसके कहने पर ये पर्यावरण के नाम पर अपनी नई कारों की बिक्री बढ़ाने, कार्बन उत्सर्जन के नाम पर 10-15 वर्ष से ज्यादा पुरानी कारों वाहनों को हटाने और अपने वाहन बैचने का षड़यंत्र का हिस्सा ही पेरिस सम्मेलन की नौटंकी। जैसे कंडोम बैचने वाली कंपनी कभी संयमित व एक जीवनसाथी से संबंध रखने की बात नहीं करती, वो तो कहती है सारी मर्यादायें तोड़कर यौनाचार करो बस हमारे कंडोम का उपयोग कर हमारी कमाई अधिकतम कमाई करवाते रहे। 1996 में जबलपुर में शराब निर्माता कं. ने नशा बंदी रैली निकाली। सुनील दत्त को बुलाया तो प्रेस कांफ्रेंस में दत्त ने कहा ज्यादा शराब पीना घातक है, पर थोड़ी-थोड़ी सबको पीना चाहिए अर्थात शराब का बिक्री संबंध वैसे ही था पेरिस का जलवायु परिवर्तन चिंतन सम्मेलन या कारों की बिक्री संवर्धन।

साप्ताहिक समय माया

ऐसी सभी विदेशी कं. को देश से बाहर भगाओ

होडा कंपनी के दो पहिया व 4 पहिया वाहन स्तरहीन, खर्चीले, परेशानीजनक

ज्यादा कीमत, ज्यादा नाजूक, भारी रखरखाव, शीघ्र बिगड़ने, महंगी सुधरवाई, महंगे कलपुर्जे, घोर मक्कार व धूर्त अधिकृत विक्रेता, सरकार को स्वचलित वाहन नियमितीकरण आयोग बनाकर कानून बनाकर ऐसे डकैतों को बाहर करें

विश्व की जानीमानी जो दो पहिया और चार पहिया वाहन निर्माण के साथ अन्य अनेकों उत्पाद भारत में उत्पादित करती है। घोर भ्रष्ट और जालसाज यथार्थ में अपने नाम के कारण देश की जनता को गुमराह कर न केवल लूट रही है। वरन् घोर परेशानी व आर्थिक, सामाजिक व मानसिक पीड़ा भी पहुंचा रही है। जिसके भुक्तभोगी भी लाखों में हैं। भारी विज्ञापनों और ख्याति के नाम पर अत्याधिक नाजुक होने के कारण शीघ्र बिगड़ने वाले, होने में रखरखाव खर्च मांगते है। सुधरवाने के नाम पर महंगे, पुर्जे और महंगी सुधरवाई लगती है।

होंडा शाइन 125, नवम्बर 14 में खरीदा गया, समय-समय पर सर्विसिंग व इंजिन का तेल बदला गया। गाड़ी महीने में 4 बार उज्जैन और देवास गई, 10 माह में भर में गाड़ी 8-9 हजार किमी भी नहीं चल पाई थी कि अक्टूबर 15 में इंजिन में से खड़खड़ाने और लोड न लेने की शिकायत आने पर अधिकृत विक्रेता कांसलीवाल होंडा को शिकायत की गई तो बोले पिस्टन ब्लॉक खत्म हो गया है, बदलना पड़ेगा इसका शुल्क देना पड़ेगा, कहा गया कि अभी तो 365 दिन भी नहीं हुए, गारंटी पीरियड में है। बड़ी हुज्जत के बाद कं. के शिकायती नंबर पर कहा गया तो अक्टूबर 15 को गाड़ी रखी गई और 17/10/15 को देखने के नाम पर फिर वही पुराना ब्लॉक पिस्टन डाल दिया गया, फिर कहा गया कं. को फिर 3 नवम्बर 15 से गाड़ी को रखा गया तो 7 नवम्बर 15 को लौटाई गई। तब उसका कलच अत्याधिक कस दिया गया, शिकायत की गई तो फिर गाड़ी छोड़ने को कहा, सारे दिन गाड़ी रखने के बाद मात्र क्लच ढीला कर दिया गया। परिणाम स्वरूप कुछ ही दिन में उसकी क्लच प्लेट बैठ गई और गाड़ी ने फिर लोड लेना बंद कर दिया, दो महीने अक्टूबर व नवम्बर 15 में परेशान होने के बाद बाहर से गाड़ी सुधरवाई गई और रुपए 1500 का बिल भुगतान किया गया, इसके पूर्व 3 माह में ही उसका एक्सीलेटर का तार टूट गया जिसे भी रुपए 100 खर्च करके बाहर से सुधरवाया गया। गाड़ी के कं. के 80 किमी का औसत देने का विज्ञापन देती थी, परंतु 40-45 किमी से ज्यादा का औसत लंबी दूरी की यात्राओं में भी कभी नहीं दिया, शहरीय क्षेत्रों में 35-40 का ही औसत दिया। और ट्यूबलैस टायर भी 10-12000 किमी की यात्रा पूरी नहीं कर पाया और घीस जाने जाने के बाद उसे भी बदलना पड़ा मिस्त्रीयों से पूछताछ पर पता चला कि 2012 के बाद से सबसे ज्यादा बिकने के बाद से होंडा कं ने कलपुर्जों से और रखरखाव के नाम पर गाड़ी को बहुत कमजोर बनाने के साथ नाजुक भी बना दिया।

होंडा कारों के संबंध में आमजन जो गाड़ी का उपयोग कर रहे थे, उनका स्पष्ट कहना था कि कारें बाहर से ही भर खुबसूरत है। परंतु इंजिन इलेक्ट्रानिक सरकिट्स बहुत कमजोर और महंगे होने से 20000 किमी से ज्यादा चलने पर गाड़ी रखरखाव मांगने लगी है। फिर अधिकृत विक्रेता भी कम मक्कार, जानसाज नहीं होते, सर्विसिंग के बहाने जानबूझकर वाहनों के कलपुर्जे बदलना, जानबूझकर नट बोल्ट ढीले या जरूरत से ज्यादा अनावश्यक कसना आदि करके वाहन मालिकों के वाहनों को बिगाड़कर जमकर वसूली करते हैं। बेशक ये शिकायत हर कं. के अधिकृत विक्रेताओं और सर्विसिंग सेंटरों और गैरेजों की होती है।

जहां तक जापानी कं. का सवाल है, तो उनके खून में मक्कारी कूट-कूट कर भरी है वो कं. चलाए रखने के लिए कोई भी मशीन, इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स व अन्य सामग्री ऐसी बनाना पसंद नहीं करते कि वह जीवन पर्यन्त साथ निभायें, जानबूझकर नाजुक कलपूर्जे बनाए जाते है ताकि वो निश्चित सीमा तक कार्यरत रहे, उस उपयोग की सीमा के बाद वह बिगड़े और आप कं. या उसके अधिकृत विक्रेता की शरण में जाए और उनकी सेवा चाकरी अपना धन और समय खर्च करके भी उनके सामने सिर झुकायें,अर्थात इन हरामखोर जालसाजों, का माल भी खरीदो और तन-मन, धन से उनकी गुलामी भी करो।

इन जापानी खरबूजों को देखकर दूसरे भारतीय खरबूजें जिनमें बजाज, टीवीएस, महिन्द्रा हीरो जैसी कंपनी ने भी न केवल रंग बदला, वरन् ये शूकरों की फौज उनसे भी दो कदम आगे निकलकर बजाज ने तो अपनी सबसे सफलतम सीटी 100 का उत्पादन ही बंद कर दिया, जबकि बजाज, टीवीएस, हीरो, महिन्द्रा जैसे वाहन निर्माता चाहते तो अपनी गाड़ियों को अनुसंधान से ज्यादा मजबूत और किफायती बनाकर इन सबके पैर उखाड़कर होंडा, सुजुकी आदि को बाहर भागने पर मजबूर कर देते, क्योंकि आम भारतीय लाड़ी और गाड़ी को बार-बार बदलना पसंद नहीं करता, विदेशियों की तरह यदि उसे एक बार मजबूत और किफायती गाड़ी मिल गई या खरीद ली तो वह उसे ही चलाना और निभाना चाहता है। लाड़ी की तरह, पर यदि वह गाड़ी बार-बार बिगड़ने, परेशान करने लगती है तो उसे बदलना उसकी मजबूरी बन जाती है।

पर देशी वाहन निर्माताओं ने अपनी मौलिकता, मजबूती और किफायती जो कि भारतीय सड़के के साथ ग्रामीण कच्चे उबड़-खाबड़ सड़कों पर चलने के लिए रांगड़ व मजबूत गाड़िया बनाती थी, विदेशियों के सामने व नतमस्तक होकर उनकी नकल में भी अक्ल का प्रयोग नहीं कर पाई, उनकी हां में हां मिलाकर उनके गिरोह में शामिल हो, ताड़ी के पहिये बिलकुल ही बनाना बंद कर दिए, पिस्टन ब्लॉक हर तरह से हल्के कर दिए, जबकि वे ब्लॉक पिस्टन में हल्के करने के लिए कार्बन स्टील का उपयोग भी कर सकते है, जो बेहद हल्का पर बेहद मजबूत होता है। क्लच एक्सीलेटर के तारों में भी बजाज अपनी पुरानी औकात पर लौटकर सिरों पर घुंडिया लगाने लगा जो नई गाड़ियों में भी 15 दिन में ही मात्र 500-700 किमी चलने में ही टूट गया, जबकि सीटी 100 में उसने सिरों पर फंसाने के लिए तार को ही पिघलाकर मोटाकर फंसाने से लाख दो लाख किमी चलने पर भी नहीं टूटते थे।

भारतीय कं. को चाहिए कि वो सर्वप्रथम परिवहन मंत्रालय के अंतर्गत, वाहनों की एक नियमितीकरण और मानक स्तर आयोग बनाए जिसनें ऑटोमोबाइल इंजिनियर्स और अनुसंधानकर्ता ही हों जो कि सीमाओं को निर्धारित करें, फिर हर कं. के वाहन उनका पेट्रोल औसत, उसके इंजिन कलपूर्जों की मजबूती उनके उपयोग की क्षमता, कं. द्वारा विज्ञापनों में की गई घोषणाओं की सत्यता, प्रदूषण जो ईंधन जलने पर वायुमंडल को बिगाड़ेगा का स्तर आदि को सत्यापित कर प्रमाण पत्र जारी करे। स्तरहीनता पर चेतावनी देकर सुधारने के लिए कहा जाए यदि कं. सुधार नहीं करती है तो वाहनों की बिक्री पर रोक लगा दें, विदेशी होंडा व अन्य कं. जो इस तरह के स्तरहीन वाहन स्वामियों को घोर आर्थिक मानसिक प्रताड़ना कारक, झूठे विज्ञापनों से उपभोक्ताओं को लूटने का धंधा करने वाली कं. को देश से बाहर भगाओ, नहीं चाहिए ऐसा निवेश, उत्पादन जो अपने लाभ के लिए जनता को तन,मन, धन के शोषणकारी और परेशान करने वाले हो, बहुत लूट लिया देश की जनता को वित्त मंत्रालय, उद्योग मंत्रालय को किसी भी विदेश निवेश उद्योग की लगाने से पहले देखना चाहिए कि कं. का इतिहास व वर्तमान का गहन अध्ययन करके ही निवेश की अनुमति दी जानी चाहिए। इस श्रेणी में चीनी कं. व उनके उत्पादन पूरी दुनिया के कुख्यात हो चुके हैं।

बेशक हर विदेशी निवेश और उद्योगपति, यहां अधिकांश लाभ बटोरने या यथार्थ में भ्रष्ट सरकारी अधिकारियों को थोड़ा बहुत टुकड़ा डालकर, स्तरहीन माल बेचकर सुधरवाई के नाम कलपूर्जों से कमाई कर अधिकतम लाभ के लिए सभी हथकंडें अपनाएगा, जनता परेशान होती है तो होती रहे।

मप्र के सभी विभागों में किराए की टैक्सी के भुगतानों में टीडीएस में हो रहा भ्रष्टाचार

10.32% टीडीएस का नहीं होता कटौत्रा टैक्सी भुगतान में

टैक्सी और सर्वे के बिलों के भुगतान में शासन उड़ा रहा आयकर नियमों की धज्जियां

शासन स्वयं कर रहा आयकर चोरी

मप्र शासन के अधिकांश विभागों में विभागीय वाहन खरीदने की व्यवस्था का भारी डीजल-पेट्रोल और मरम्मत में होने वाले भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए शासन ने किराए पर निजी टैक्सियों को रखने की छूट दे दी, इसमें भी संबंधित विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों ने अपने काले धन से रिश्तेदारों, दोस्तों व अन्य विश्वासपात्रों के नाम से अपने निजी वाहनों को ही किराए पर रख लिए, जबकि शासन ने वेतन के स्तर, अधिकारी के स्तर के हिसाब से वाहनों का किराया, मासिक किराये में मुफ्त किमी, वाहन का उत्पादन, टैक्सी कोटे की गाड़ियां आदि सब की सीमाओं का उल्लेख बारीकी से करने के साथ खुले बाजार में निविदा प्रकाशित कर न्यूनतम दर ही वाहनों को किराए पर रखने की व्यवस्था की है। सबके परिपत्र समय-समय पर जारी किए गए, इसके विपरीत हर विभाग में इन परिपत्रों को बताए ताकि धड़ल्ले से मनमाने तरीकों से भुगतान किए जा रहे हैं। यहां तक कि शासन के वाणिज्य कर विभाग में रुपए 18500 के मासिक किराए में 1000 किमी तक, डीजल, पेट्रोल का भुगतान गाड़ी मालिक ही करेगा। वाहन चालक, टूट-फूट, सुधरवाई टायर-ट्यूब, सबकी जिम्मेदारी गाड़ी मालिक को ही भुगतना होगा, 1000 किमी से ऊपर प्रति किमी की दरों में डीजल-पेट्रोल भी मालिक को भुगतना होगा, इसके विपरीत लो.नि.वि., लो.स्वा. यांत्रिकीय, जल संसाधन नघा वि.प्रा., सभी नगर निगमों, निकायों, भ्रष्टाचार प्राधिकरणों,वन, पुलिस, शिक्षा, उच्च शिक्षा, महिला बाल विकास, खनिज, कृषि, उद्यानिकी, स्वास्थ्य, पंजीयन, ग्रामीण यांत्रिकीय, पंचायत, जिलाधीश, संभागीय आयुक्त, ग्राम व गृह निवेश, विद्युत कं., परिवहन, प्रदूषण मंडल, सहकारिता आदि अनेकों शास. विभागों में टैक्सी किराए के रुपए 20000 से लेकर 22500, 25000 से 30000 तक मासिक भुगतान के साथ ही शासन के वाहन चालकों से टैक्सी चलवाई जाकर, पेट्रोल, डीजल का भुगतान भी प्रति किमी के हिसाब से हर किमी का भुगतान किया जाकर मोटी कमाई की जा रही है। साथ ही बिलों के भुगतान कें आयकर के नियमों के विपरीत जाकर 10.32 प्रतिशत की स्रोत पर कर कटौती की अपेक्षा 2.32प्रश ही कर काटकर जमा किया जा रहा है। जबकि आयकर अधिकारी टीडीएस सन् 2009 से लगातार शासन के हर विभाग को पत्र देकर 10.32 प्रश कर काटकर जमा करने के लिए लिख रहा है।

यही हाल निर्माण विभागों में बड़ी परियोजनाओं के पूर्व करवाये गए निजी क्षेत्र के सर्वे के बिलों पर भी 10.32 प्रश कटोत्रा करना है। परंतु शासन के मप्रलोनि.वि., इसका अनुषांगिक संगठन मप्र सड़क डकैती निगम, लो. स्वा. यांत्रिकीय व अनुषांगिक संगठन जल निगम, मप्र जल संसाधन, नघावि प्राधिकरण, सभी शहरीय विकास प्राधिकरण, नगर निगम, पालिकाएं आदि अपनी बड़ी परियोजनाओं व अन्य कार्यों के सर्वे के बिलों के भुगतान में से 2.32 प्रश आयकर कटौती कर रहे है। जबकि 10.32 प्रश होना चाहिए इस प्रकार मप्र शासन ही अरबों रुपए प्रति वर्ष की आयकर की चोरी कर रहा है। आयकर अधिकारी द्वारा लिखे गए पत्र की प्रति संलग्न है

बेशक इस 8 प्रश की सन् 2009 से वसूली हर कार्यालय प्रभारी से रुपए 100 प्रति दिन के दंड के साथ वेतन से की जानी चाहिए। जिसमें प्रदेश के हर विभाग का अधिकारी दंड का पात्र है।

भा.चि.परि., विश्व स्वास्थ्य बिगाड़ो...

(पृष्ठ 6 का शेष)

गुर्दे, हृदय, यकृत, प्लीहा, मस्तिष्क, अमाशय के पूरे देश में 5 करोड़ से ज्यादा स्थाई मरीज है, जो 90 प्रश इन एलोपैथिक औषधियों के सहपरिणामों के साथ ही शीतल पेय, डिब्बा बंद महीनों पुराने खाद्य पदार्थों, नकली दूध, खाद्यान्नों, सब्जियों आदि में बढ़ते कीटनाशकों के प्रयोग के कारण ही है। गरीबों के पास सरकारी चिकित्सालयों के अतिरिक्त विकल्प नहीं है, जबकि अमीरों से कमाई के लिए गुर्दे, हृदय, यकृत, आदि को बदलने के नाम पर लाखों की वसूली की जाती है। इसके लिए भी गरीब घायलों को जो सड़क दुर्घटना आदि में घायल हो जाते हैं, इंदौर का मेदांता में ऐसे केस पहुंचने पर वैसे अरविंदों में भी होने लगा है। जिसका महागिद्ध अपने व्यापम फर्जीवाड़े में दो वर्ष जेल में रहकर आया है, ने भी ऐसे गरीब घायलों को तुरंत चिकित्सा से जीवन देने की अपेक्षा उनके मां-बाप को डरा-धमका और मानवीय संवेदना का हवाला देकर उनके संरक्षकों मां-बापों से कागजों पर हस्ताक्षर करवा और कोमा में बताकर तत्काल ही ये गिद्धों की फौज उसका हृदय, यकृत, प्लीहा, आंखें आदि निकालकर अपने महानगरों स्थित गिरोह के अन्य केन्द्रों जो दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद में है करोड़ों में लगाकर बैच खाते हैं। इसमें से रुपए 5-10 लाख का टुकड़ा, प्रशासन और संयुक्त संचालक महाभ्रष्ट, महाजालसाज, डॉ. शरद पंडित भी पैसे हजमकर ग्रीन कॉरिडोर बनवाने की नौटंकी जिसे मुखेरे श्वानों की फौज भी मीडिया भी बहुत भाव देता है। डॉ. त्रेहन मेंदाता के अस्पताल में जाकर इन हरामखोर शास. डॉक्टरों ने ये जानने की कोशिश नहीं की कि, कौन सा गरीब व घायल, किस अवस्था में पहुंचा थे, जिसे जानबूझकर कोमा में दिखाकर उसके अंगों को निकालकर बैचने के षड़यंत्र की असलियत क्या है। जब मैंने इस संदेश में 8 मार्च को वाट्सएप से डॉक्टरों और डॉ. शरद पंडित को भेजा तब उस हत्यारे डॉ. त्रेहन अपना षड़यंत्र बंद किया उसके पहले तो 8 गरीबों के अंग निकालकर भेज चुका था। वैसे पूर्व में चोइथराम हॉस्पिटल में हो चुका था। जिसके तार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जुड़े पाए गए। आखिर पिछले 20 वर्षों में इन हरामखोर जालसाज डॉक्टरों द्वारा सैकड़ों व्यक्तियों की किडनी निकालकर बैचकर बदलने पर बीमारों से करोड़ों की कमाई की गई। प्रकरण सामने आए स्पष्ट हो गया, परंतु कितनों को सजा होगी। फिर डॉ. पंडित 20 वर्षों से ज्यादा इंदौर में जमा ही लूटों और लुटाओं के दम पर है। अपनी लूट में कमी के कारण ही तो इंदौर के सीएमओ को चैन से नहीं बैठने देता।

साग, सब्जियों, फल, फूलों, खाद्यान्न, दलहन, तिलहन पर भी 2 प्रश मंडी शुल्क

सराफा व्यापारियों की हड़ताल पूर्णतः बकवास, औचित्यहीन

देश के सबसे बड़े ठगोरे, जालसाजों, अरबों के काले धन वालों का गिरोह 1 प्रश एक्साइज का डर नहीं, वरन् लाखों करोड़ के काले धन का डर

मोदी सरकार ने स्वर्ण, रजत, प्लेटिनम, हीरे जवाहरात व्यापारियों पर जो 1 प्रश ड्यूटी लगाई है जिससे पूरे देश के सराफा व्यापारी, दुकानदार, आदि 42 दिन से ज्यादा समय से व्यापार बंद कर हड़ताल पर बैठे हैं। जो पूर्णतः औचित्यहीन और निरर्थक थी जब गरीबों की रोटी पर 2 प्रश मंडी शुल्क लगता है अर्थात साग, सब्जियों, फल, फूलों खाद्यान्न अर्थात गेहूं, चावल, दालों, तेल बीजों अर्थात सोयाबीन, मूंगफली, सरसों, अलसी आदि पर 2 प्रश मंडी शुल्क का भुगतान व्यापारियों को करना पड़ता है। जिसका सीधा असर 125 करोड़। जनता के हर गरीब अमीर के भोजन पर गए तो देश के 40 करोड़ गरीब खायेंगे क्या?

बेशक देश का प्रधानमंत्री महाधूर्त, रक्त पिपासु दानव है और जन धन से लाखों करोड़ अपनी विदेश यात्राओं पर बर्बाद कर देश की आम जनता को अकेले पेट्रोल, डीजल, ईंधन गैस की चारगुनी कीमत वसूलकर तलने पर तुला है। देश के हवा, पानी, खेतों से लेकर पूरे व्यापार को विदेशियों के हाथ बैचकर जनता को लूटवा रहा है। पूंजीपति दानवों की कठपुतली बन उनके हितों के लिए जनता को लुटवाकर अकेले गुजरात में रुपए 1100 करोड़ से ज्यादा के करों की छूट उस अंबानी बंधुओं को दिलवा दी, पर स्वर्ण पर 1 प्रश ड्यूटी लगाकर गलत कुछ नहीं किया है।

विदेशों में पड़ा न केवल रुपए 70 लाख करोड़ से ज्यादा की नगदी मुद्रा वरन् स्व. इंदिरा गांधी ने जो जयपुर के खजाने से 700 ट्रक माल 75-76 आपातकाल में लूटकर स्वीटजरलैंड पहुंचाया था, जिसमें 700 ट्रकों में विशुद्ध हीरे जवाहरात और स्वर्ण ही था। लाने की भी अभी तक कोई पहल नहीं की, फिर सबसे ज्यादा काला धन पूंजीपतियों उद्योगपतियों के साथ ही कांग्रेसियों, भाजपाइयों, बसपा, सपा, दक्षिण भारत की क्षेत्रीय राजनैतिक पार्टीयों उनके मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों से लेकर पूरे देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मुख्यमंत्रियों सभी मंत्रालयों से लेकर जिलों के जिलाधीश और जिला पंचायतों के नगर निगमों तक के आयुक्तों के रूप में बैठे महाधूर्त इंडियन, एव्यूसिंग सर्विस के 10 हजार से ज्यादा बैठे अधिकारियों का भी लाखों करोड़ विश्व के अनेक देशों की बैंकों में कालाधन भरा पड़ा है। इसलिए ही ये हरामखोर जालसाजों की फौज उस कालेधन को देश में लाने में नए-नए बहाने बनाती रहती है। इन भारतीय प्रशासनिक सेवा के शूकरों का काला धन तो आतंकी दाउद के निशाने पर नाच रही पूरी फिल्म इंडस्ट्री से लेकर इन सराफा व्यापारियों और टाटा, बिरला, मित्तल के हजारों उद्योगों से लेकर इन सराफा व्यापारियों और जमीनों, कॉलोनाइजरों जैसे भूमाफियाओं के पास भी विनियोजित है।

सराफा व्यापारियों की हड़ताल को भी पूरे देश में शह इन्हीं लोगों को मिली दूसरी और इन सराफा व्यापारियों को महीनेभर तो क्या 6 महीने में हड़ताल करें तो भी क्या फर्क पड़ने वाला है। स्वर्ण रजत, आभूषणों के होने न होने खरीद-बिक्री न होने से आमजन में कोई भुखमरी फैलने वाली तो नहीं।

सराफा व्यवसाय, दुकानदार, आमजन को जो स्वर्ण रजत आभूषण की 100 प्रश बिक्री में 1 प्रश से लेकर 99.9 प्रश तक की मिलावट अर्थात स्वर्ण-रजत का पानी चढ़ाकर भी माल बैचता है। ये ही सबसे बड़े ठगोरे और जालसाज होते हैं, जो सबसे ज्यादा जनता से ठगी व लूट करते हैं। इन्हें सरकार की 1 प्रश ड्यूटी से नहीं वरन् रु. लाखों करोड़ की जो स्वर्ण रजत धातुओं का भंडार, उसकी खरीद-बिक्री में मिलावट और उससे भी गई ठगी और लूट का यथार्थ सामने आने से भयभीत है। ये सब अपनी जालसाजी ठगी से की गई कमाई को छुपाने के साथ ही काले को सफेद और सफेद को काला करने वाले धातुओं के व्यापार में लगे अरबों करोड़ के लेन-देन को छुपाने के लिए ही सरकार पर हड़ताल के माध्यम से दबाव बनाने में लगे थे, ताकि भविष्य में दो नंबर के धन से इस व्यापार पर पड़ने वाले असर को रोका जा सके, क्योंकि ड्यूटी लगी तो बिल काटना पड़ेगा जिससे काले धनवाले स्वर्णाभूषणों में धन निवेश करने से बचेंगे अन्यथा पकड़े जाने और धन का स्त्रोत बताने के लिए भी बाध्य किया जा सकता है। आयकर, सीबीआई व राज्यों के लोकायुक्त के छापों के समय भी ये सौदे एक ठोस सबूत बन कर क्रेता विक्रेता दोनों को परेशान करेंगे और न्यायालयों में अपराध सिद्ध करने में काम आएंगे।

इस ड्यूटी का दूसरा पहलू यह भी है कि ये दोनों कीमती धातुयें यथार्थ में नगदी धातुयें है। जिन्हें कहीं भी कभी भी किसी भी राष्ट्र की मुद्रा में तत्काल बदला जा सकता है। साथ ही न केवल भारतीय परिवारों में वरन् विश्व के अनेकों देशों में इन धातुओं में निवेश करना घरेलू व सामाजिक रूप से आर्थिक रूप से भविष्य की आवश्यकताओं के लिए बचत के रूप में अनादिकाल से अनादि तक सर्वमान्य रहा है। रहेगा। इसलिए स्वर्ण, रजत न केवल सामाजिक व आर्थिक रूप से संपन्नता का प्रदर्शन करता है, वरन् भविष्य की आर्थिक सुरक्षा करता है, इससे निवेश आकर्षित करता है।

बेशक मोदी सरकार महाधूर्त और डकैतों का गिरोह हैं, जो पूंजीपतियों के इशारे पर नाचकर जनता को लूटने और लुटाने पर तुला है। 1 प्रश ड्यूटी लगाने के बहाने यथार्थ में स्वर्ण की क्रय-विक्रय की जानकारी प्राप्त करना व्यापारियों के पास जमा स्वर्ण रजत के भंडारों का पता लगाना, काले धन का निवेश जानना, सामाजिक व्यक्ति की क्रय बिक्री के माध्यम से आर्थिक स्थिति की जानकारी संग्रहित करना भी मूल में है। स्वर्ण की वास्तविक स्थिति जानने के लिए स्वर्ण बांड योजना लागू की गई है। ताकि ब्याज का यथार्थ मालूम पड़ने के साथ ही बैंकों में रखे जनता के स्वर्ण को ही हजम कर जायेंगे, स्वयं बैंकों को डकैती का निशाना बनायेंगे, या कानून बनाकर ही हजम कर लेंगे। जब तक सरकारी बैंके अलग-अलग है, तब तक फिर भी जनता का सावधि आवर्ती बचत जमायें सुरक्षित हैं। इसलिए सरकारी षड़यंत्र है कि सभी बैंकों को संविलयन कर एक कर दिया जाए ताकि आसानी से जनता के हर लेन-देन पर नजर रखकर, उस पर करा रोपण कर आयकर बिक्री कर आदि की वसूली की जा सके।

42 दिन की लंबी हड़ताल के बाद सराफा व्यवसाइयों ने दुकानें खोली है। वैसे भी सराफा व्यवसायियों की हड़ताल से सरकार को तो कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि उसे तो पहले से ही कोई राजस्व प्राप्त नहीं हो रही थी। न राज्यों को, न केंद्र को। अब 1 प्रश ड्यूटी लगाने से बेशक थोड़ा सा भार अवश्य जनता पर आयेगा जबकि ग्राहक बिल लेगा, खरीद बिक्री का, पर बिल के आने से आभूषणों, सिक्कों की शुद्धता के संबंध में ग्राहक अवश्य दिए गए कर के हिसाब से उपभोक्ता फोरम में जाकर ठगी होने पर न्यायालय में क्षतिपूर्ति का आवेदन कर सकेगा।

भ्रष्टाचार के पैसे से पदोन्नति अ.यं. बीएल जायसवाल को

भारतीय सड़क कांग्रेस 76 वें अधि. में रुपए 5 करोड़ हजम

18 से 22 दिस के अधि. में टैक्सी, होटल, बुकिंग, भोजन, भेंट वस्तुओं में धूर्त सचिव बीएल जायसवाल, अध्यक्ष मु.अ. श्रीवास्तव, अध्यक्ष व अन्य ने ठेकेदारों का चंदा हजम सूचना के अधिकार में जानकारी मांगने पर टालमटोल

मप्र लोक भ्रष्टाचार निर्माण विभाग में चारों तरफ धूर्त, भ्रष्ट, जालसाज प्रधान सचिव प्रमोद अग्रवाल, सचिव चं.प्र. अग्रवाल, प्रमुख अभियंता अखिलेश अग्रवाल से लेकर रा.रा. इंदौर संभाग के उपयंत्री शर्मा जी तत्काल में करोड़ों की संपत्ति के मामले में लोकायुक्त न दबोचा है। सैकड़ों उपयंत्री, सैकड़ों सहा.यंत्री 90 से ज्यादा का व्यंत्री, 25 से अ.यं., 10 से ज्यादा मु.अभियंता करोड़ों के मालिक हैं 100 से ज्यादा इंजिनियर अरबों के मालिक है।

17.05.16 को उपरान्ह कार्यमुक्त हुए अ.यं. बीएल जायसवाल रुपए 25 लाख से ज्यादा खर्च कर मुख्य अभियंता पदोन्नत होकर यथार्थ में 15 दिन के लिए मप्र सड़क डकैती निगम में गए हैं। जिसकी सेवानिवृत्त 31.05.16 को है। परन्तु वहां वो इस लिए गया है ताकि उसे करोड़ रुपए खर्च करके साल दो साल की सेवा वृद्धि मिल सके, जिसकी उसने सारी गोटियां प्र.सं. सचिव, मंत्री और मुख्यमंत्री कार्यालय में जमा ली है। और बदले पूरे प्रदेश की बीओटी सड़कों पर लूट का तांडव करके महीना डकार सके।

2010 तक वैसे जायसवाल मात्र एसडीओ था, परंतु सहा. यंत्री रहते हुए लो.नि.वि. में हर संभाग में लूट का तांडव किया जब भ्रष्टाचारों की पर्ते खुलने लगी तो पहले औ.के.वि.नि. इंदौर में जाकर वहां भी भारी लूट पाट मचाई, जब वहां अंगुलियां उठने लगी तो 2-3 वर्ष सेवा देने के बाद लौटकर पुनः अहिल्या वि.वि. में वहां के आ.अ.वन प्रति नियुक्ति पर चला गया, जब वहां भी चारों तरफ भ्रष्टाचार के कारण गालियां और जांच शुरू होने की स्थिति बनी तो पुनः लो.नि.वि. में लौट आया बाद में 6 माह तक पदोन्नति पाकर संभाग क्रमांक-1 इंदौर में पदस्थ हो गए, तब तक सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आ चुका था और सन् 2012 से अधीक्षण यंत्री इंदौर मंडल रहकर निविदा स्वीकृति, समय वृद्धि, महंगा वृद्धि ठेका, निलंबन, समाप्ति, पुनः बहाली में इंदौर के सं.क्रं.1, 2, वि.यां., धार, झाबुआ, आलीराजपुर में जमकर का.यं. से महीना वसूली रुपए 50000 से रुपए 1 लाख कार्य के हिसाब से और पद के हिसाब से 2 से 10 प्रश तक वसूली की इस हरामखोर ने।

गत दिसम्बर-15 में इंदौर में हुई भारतीय सड़क कांग्रेस के 76 वें अधिवेशन में बंदे ने जो कि क्षेत्रीय संगठन समिति का सचिवे था और मुख्य अभियंता प्रभात श्रीवास्तव इसका अध्यक्ष था, कोषाध्यक्ष का.यं. निर्मल श्रीवास्तव, सं.लेखाकार मनीष त्रिवेदी इसका लेखाकार था, रुपए 8 करोड़ की शासन से राशि मिली थी और लगभग रुपए 10 से 12 करोड़ ठेकेदारों, निर्माणी कं. और सदस्यों से वसूली की गई थी, जिसमें विज्ञापन के नाम, भोजन, नास्ता, टैक्सी सभा स्थल का किराया, होटलों की बुकिंग, कार्यक्रम आयोजन में नौटंकीबाजी आदि में इस धूर्तों के टोले जिसमें जायसवाल, श्रीवास्तव द्वय और डीए मनीष त्रिवेदी ने मिलकर रुपए 5 करोड़ से ज्यादा हजम किए, कार्यक्रम में नौटंकीबाज कं. 7 वंडर्स ने मंच सज्जा कार्यक्रम की फोटोग्राफी, नृत्य नाटिका जो हुई ही नहीं। अपने गिरोह को लाने ले जाने का विमान किराया वसूला, करीब पौने दो करोड़ का बिल दिया जबकि कार्य की वास्तविक रुपए 40-50 लाख से ज्यादा नहीं थी, पर मोटा कमीशन लेकर उसे रुपए 1 करोड़ 20 लाख से ज्यादा का भुगतान दिया, ब्रिलियंट कंवेंशन सेंटर का किराया जहां कांस अधिवेशन में व अन्य ने रुपए 25 लाख दिया वही इन धूर्तों ने रुपए 40 लाख प्रतिदिन औसत दिया कुल चेकों से भुगतान रुपए 1 करोड़ 77 लाख दिया। रुपए 1 करोड़ 53 लाख रुपए भोजन का भुगतान किया, जिसमें साधारण भोजन प्रति थाली रुपए 650 और चाय स्टेशन से थोड़ी बेहतर पकोड़े बिस्कुट के साथ रुपए 250 प्रति व्यक्ति एक दिन की चाहे 1 कप पिए या 4 कप या न पिये, होटल बुकिंग कर प्रति कमरे रुपए 7000 प्रति कमरे की बुकिंग के लिए रुपए कुल से भुगतान रु. 1 करोड़ 2 लाख 38 हजार का भुगतान किया, होटलों में बुकिंग के नाम से क्रं. 2 का उस समय का प्रभारी का.यं. बीके माथुर ने हर होटल से 20 प्रश की सेटिंग के साथ सुरा सुंदरी और भोजन का भी दो महीने तक हर होटल में मुफ्त में भोग किया। मेहमानों की पत्नियों जो संख्या में 300 से ज्यादा नहीं थी रुपए 25,14 लाख की साड़ियां खरीदी गई, जिसमें से महेश्वरी साड़ियों में रुपए 800 से 1800 की साड़ियां को रुपए 1500 से 2500 में खरीदा गया जिसमें से 100 साड़िया अपनी बेटी की शादी में इस धूर्त, भ्रष्ट, हरामखोर जायसवाल ने जनधन से बांटी, जब पूछताछ की तो श्रीवास्तव द्वय ने पहले टालमटोल की बाद में उसके पैसे हजम करवा लिए। कहा गया भोपाल की टैक्सी फर्म से 500 टैक्सियां और 50बसों को जिनका भुगतान रुपए 55.06 लाख किया गया चेक से, सूत्रों के अनुसार कुल 200 टैक्सीयां और 25 बसों ने ही इंदौर में उपस्थिति दर्ज करवाई जिसके प्रभारी कां.यं. अजीत चटर्जी थे। जो मेहनामों को मात्र होटलों से ब्रिलियंट सेंटर तक लाने ले जाने के लिए थी।

दूसरी ओर बड़े-बड़े ठेकदारों से निमार्णी कं., से रुपए 15 से 25 लाख तक वसूले गए, रुपए 2 लाख ए- क्लास ठेकेदारों से जो संख्या में लगभग 200 से ज्यादा थे। प्रदेशभर के छोटे ठेकदारों से रुपए 25 हजार से 2 लाख रुपए तक जो जैसा काटा जा सके इस प्रकार करीब 8 करोड़ रुपए नगद व चेक से वसूले गए, सारा पैसा नीचे से ऊपर तक इस चांडाल चौकड़ी ने स्वयं भी हजम किया और प्रमुख अभियंता से लेकर प्रधान सचिव तक करोड़ों में बांटा गया, दो खाते बैंकों में खोले गए सरकारी व निजी।

सूचना के अधिकार में जानकारी मांगने पर दिस. की जानकारी मार्च में मार्च की जानकारी का अभी तक पता नहीं है। ऊपर से मुख्य अभियंता दबाव बनाते हैं कि तुम मुझे परेशान कर रहे हो, यदि आप सब ईमानदार हैं तो फिर तो जानकारी देकर खुश होना चाहिए कि इनकी पारदर्शिता दूसरों के सामने भी आएगी तो दूसरे भी इन्हें इतिहास पुरुष मान आदर्श बनाकर काम करेंगे। लोकायुक्त संगठन को इस कांड की जांच करनी चाहिए। ऐसे कार्यक्रम वैसे मोटी कमाई का जरिया होते है। फिर जायसवाल जैसे धूर्तों को जिनके हर काम में, हर कदम भ्रष्टाचार लूट और जालसाजियां भरी हैं। 6 वर्ष में ही तिकड़मी चाले से सहा. यंत्री से मुख्य अभियंता बन समय विस्तार लेकर सड़क डकैत कार्प में पहुंच गया, मु.मं, मु.स., मंत्री सरताज, प्र.स. और सचिव सब मोटा धन लेकर आसानी से इसे समय विस्तार देंगे। फिर जहां तक सवाल मप्र रोड डकैत कार्प का तो यहां तो भ्रष्ट, निकम्मों, मूढ़ों और जालसाजों का ही बोलबाला है। जो करोड़ों में बीओटी ठेकेदारों से महीना हजमकर, खराब और स्तरहीन 4 लेन के कानून को बलाए ताक रख दो लेन और सिंगल लेन सड़कों पर वसूली करते हैं। वरन् शूकरों का गिरोह उन्हें तीन वर्ष के स्थान पर हर वर्ष 7 प्रश चूंगी की दरें वृद्धिकर देता है। फिर जायसवाल का उद्देश्य तो लूटना ही है। बेशक भारी दबाव रहेगा, क्योंकि बीओटी के अधिकांश ठेकेदारों के मंत्रियों-संत्रियों से संबंधों के चलते तो खराब सड़कों पर भी निरीक्षण की अच्छी रिपोर्ट मांग कर दरें बढ़वा लेते है। लेबड़, रतलाम, नीमच, खंडवा, बेतुल जैसे 50 सड़कों की हालत बेहद खराब होने परये मुख्य अभियंता जायसवाल भी लूट का तांडव ही करेगा।

साप्ताहिक समय माया

7वां वेतनमान-नियमित को 25 प्रश से 50 प्रश बढ़ोत्री, ठेका व अनियमित का दैनिक मजदूरी से कम...

जनता से करों से लूट, शास कर्म. अधिकारियों पर लुटाई

निजी क्षेत्र में जनता करती है 365 दिन काम उससे करो में वसूली और सरकारी राज भोगी को 180 दिन कार्य पर 365 दिन का वेतन व अन्य सुविधायें

केंद्र सरकार 31 जन. 2016 से केन्द्र सरकार के सभी विभागों यथा पोस्ट ऑफिस कस्टम, एक्साइज, आयकर, पीआईबी, सीपीडब्ल्यूडी, रेलवे व सभी केंद्रीय मंत्रालयों आदि में 7 वां वेतनमान जिसमें 25 प्रश से 50 प्रश की बढ़ौत्री होगी, बेशक उसमें महंगाई शामिल करके वेतनमान निश्चित किया गया है

केंद्रीय कर्मचारियों के वेतनमान की घोषणा होते ही मप्र की व अन्य राज्यों की सरकारें भी अपने वेतनमान घोषित करेंगी, जिससे सभी सरकारी राजभोगियों की और सेवानिवृत्ति पाने वाले को भी स्वाभाविक तौर पर लाभ प्राप्त होगा, आखिर एक तरफ केन्द्र व राज्य सरकारें नियमित कर्मचारियों को जो कि वर्ष में मात्र 180 से 200 दिन काम के बदले 365 दिन का वेतन मकान किराया भत्ता, यात्रा व वाहन व्यय, संगठनों के शिक्षण चिकित्सा, यात्रा में जाने पर दैनिक भत्ता, होटल का रूम किराया, आदि के साथ हर दो वर्ष में अपने निवास स्थान की यात्रा और हर चार वर्ष में छुट्टी यात्रा रियायत के नाम पर पदस्थापना के अनुसार रेलवे, टैक्सी, विमान यात्रा का भुगतान करती है। दूसरी तरफ अधिकांश विभागों में डॉक्टर, इंजीनियर, स्टेनो ग्राफर, कम्प्यूटर ऑपरेटर से लेकर वैज्ञानिक शिक्षक, प्राध्यापकों तक को संविदा नियुक्ति देकर न्यूनतम यहां तक कि इंजिनियरों, शिक्षकों तक दैनिक वेतनभोगियों की न्यूनतम मजदूरी अकुशल के लिये मप्र में रु. 251 और कुशल के लिये रु. 350 प्रतिदिन के हिसाब से रुपए 10500 से भी कम रुपए 8000 प्रति माह देती है। वह भी ठेकेदारों के अंतर्गत नियुक्ति दी जाती है। जो शासन द्वारा दिये जा रहे वास्तविक वेतन में से 10 प्रश से लेकर 50 प्रश हिस्सा हजम कर जाने के साथ नियुक्ति देते समय भी मोटी रकम हड़पने जमा करने ग्यारंटी धन जमा करने के नाम पर ले लेता है। उनसे 8 से 10 व 12 घंटे तक का यह लेकर रु. 5000 से 7000 प्रति माह तक भुगतान कर शोषण करता है, जिसमें इंदौर के म.गा. चिकित्सा महाविद्यालय मप्र लोक निर्माण की परि.कि. ईकाई, जालसाज व धूर्त संचालकों जिसमें मप्र शासन का उपजिलाधीश संदीप सोनी, उसका प्रबंध निर्देशक, एसपी, महापौर, जिलाधीश, क्षे. यातायात अधिकारी, संभागायुक्त, संचालकगणों के रूप में अटल इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट कं. लि. चलाई जा रही है रु. 5000 से 7000, 8000 रुपए तक मात्र कुशल श्रमिकों जिसमें चालक, परिचालक हैं और अपने आप को अर्द्धशासकीय मानते व बताते है। स्वयं भुगतान कर रहे हैं। जबकि शासन से अरबों रुपए जेएनआरयूएन के डकारने और हेरा-फेरी करने वाले समानांतर यातायात के माध्यम से अलग कं. बनाकर लूट रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ कर्मचारियों का घोर-शोषण किया जा रहा है। तकनीकी शिक्षा प्राप्त कुशल ठेका कर्मचारियों को केन्द्र व राज्य सरकारों के कार्यालयों में व संविदा कर्मियों की जीवन यापन से भी कम वेतन प्राप्त हो रहा है।

जबकि अधिकांश विभागों में 90 के बाद भर्ती किए हुये अधिकांश सरकारी कर्मचारी अधिकारियों को न केवल भरपूर वरन् कार्य की तुलना में कहीं ज्यादा वेतन के साथ भ्रष्टाचार से भी यथा योग्य अवसर और रिश्वत से कई गुना ज्यादा कमाई कर रहा है। फिर सरकार में नियमित रूप से कार्यरत, सरकारी सुविधायें को भोगने के बाद भी 365 दिन का वेतन लेकर कार्य तो 180 से 200 दिन ही करते हैं। साथ ही कामचोरी, मक्कारी, भ्रष्टाचार और जालसाजियां, जन-धन, जनहितों के साथ वह अलग।

वर्तमान में आवश्यकता इस बात की थी, कि धूर्त अमेरिकी और युरोपीय कं. के घोर जालसाज और धूर्त विश्व व्यापार संगठन के दबावों के चलते 1990 से न केवल केन्द्र सरकार वरन् राज्य सरकारों के हर विभाग में लिपिक वर्ग से लेकर निरीक्षकों, सहा. अधिकारियों, कर्मचारियों की भर्तीया नहीं हुई है। जबकि 35 वर्ष में सैकड़ों नई योजनायें नई तकनीकी, नये कानूनों, नई जिम्मेदारियों से हर विभाग में काम तीन गुना और स्वीकृत व आवश्यक संख्या में कर्मी आधे रह गये हैं। जिससे हर विभाग के कर्मचारी व अधिकारी अत्याधिक तनाव और काम के दबाव से न केवल परेशान वरन् मधुमेह, उच्च निम्न रक्त चाप, यकृत रीढ़ारिथ की विकृतियों से लेकर हृदयाघात तक का शिकार हो कर भागने की तैयारी में है। जबकि कर्मचारी, अधिकारी, सेवानिवृत्त होने से लेकर मृत्यु के शिकार होने से स्टाफ में भारी कमी है। इस कमी को पूरा करने स्वयं केन्द्र व राज्य सरकारें दैनिक मजदूरी के बराबर वेतन देकर ठेकेदारों से ठेका श्रमिकों के रूप में अस्थाई कर्मचारियों, पर्यवेक्षकों से लेकर निरीक्षक, लिपिक, भृत्य, चौकीदार, इंजिनियर और डॉक्टरों तक की संविदा नियुक्तियों से काम चला रही है। जबकि संविदा नियुक्तियां हर कर्मचारी, अधिकारी, डॉक्टर, इंजिनियर, शिक्षक, कम्प्यूटर ऑपरेटर्स, व्याख्याता व अन्य सभी जानते हैं कि नौकरी की कोई निश्चितता हो है नहीं इसलिये कोई भी पूर्ण जिम्मेदारी से कार्य करने की अपेक्षा काम चलाऊ काम करने में विश्वास रखता है और जहां से भी मौका मिलता हैं वसूली और भ्रष्टाचार करता है क्योंकि उसकी मानसिकता होती हैं कि ज्यादा से ज्यादा उसे नौकरी से हटाया जा सकता है। इसलिये वो कार्य की ज्यादा चिंता भी नहीं पालता।

आवश्यकता इस बात की है कि राज्य सरकारों में पूरे देश, हर राज्य सरकार को लाखों कर्मचारियों की आवश्यकता है, अकेले मप्र सरकार को 1 लाख से ज्यादा निचले स्तर के कर्मचारी यथा बाबुओं, शिक्षकों, सिपाहियों की तत्काल भर्ती करना चाहिये, केन्द्र सरकार को भी पूरे देश में फैले 25 से ज्यादा विभागों, संस्थानों में हर स्तर के कर्मचारी अधिकारियों की आवश्यकता है, जिन्हें तत्काल भरा जाना चाहिये, दूसरा सीधे अधिकारियों की अपेक्षा निचले स्तर पर भर्तीयों की जानी चाहिये और हर वर्ष विभागीय परीक्षाओं से ही पदोन्नतियां दी जानी चाहिये, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के अनुकूल किसी प्रकार का आरक्षण न हो, जो सक्षम होगा, मेहनतकश और होशियार होगा, पदोन्नति प्राप्त कर विभाग की और देश की सेवा मेहनत और लगन से करना हेगा, उसमें किसी प्रकार की न कोई वरिष्ठता का मानदंड हो, न जातिगत आरक्षण, इससे कर्मचारियों अधिकारियों में किसी प्रकार की एक-दूसरे के प्रति दुर्भावना नहीं होगी, जब परीक्षाओं से पदोन्नतियां होगी तो कर्मचारी, अधिकारी अपनी कार्यक्षमतायें दिखायेगा, भ्रष्टाचार नहीं करेगा, चापलूसी, नेता, अधिकारियों के पीछे चक्कर लगाने, में वक्त बर्बाद करने की अपेक्षा वो मेहनत और नियमानुसार काम करेगा, उसका ध्यान आगे बढ़ने और कमा करने पर होगा, भ्रष्टाचार के मूल में एक कारण यह भी है कि उसे आगे बढ़ने के लिये गोपनीय चरित्रावली लिखवाने से लेकर, पदोन्नति पाने तक उसको हर जगह पैसा बांटना हैं, तो पहले उसे स्वयं भ्रष्टाचार से कमाई करनी होगी।

बेशक सरकार कर्मचारियों, अधिकारियों को 7वां वेतनमान देने के पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि इन्हीं कर्मचारियों, अधिकारियों के भ्रष्टाचार, जालसाजियों से न केवल चुनाव जीतकर सत्ता में आये हैं। इन्हीं के दम पर वो सारे भ्रष्टाचार और जालसाजियां कर, जनता को हर कदम, नोंच-खसोंट कर जनता की मेहनत की कमाई को दुनिया में सबसे ज्यादा करों से वसूल कर वह जन-धन 40 लाख करोड़ से ज्यादा वो गुजराती धूर्त रक्त पिपासु दानव विदेश यात्राओं में खर्चकर आया, इसलिये ऐसे जनता के मुंह से निवाला छीनने वालों को तो सिर तक तर रहना चाहिये। बाकी करोड़ों बेरोजगार भूखे मर जायें। इनबी बला से। कोई भी कर्मचारी-अधिकारी संगठन ने कभी इस बात की मांग नहीं की कि शासकीय केन्द्र व राज्य सरकारों के हर विभाग में हजारों पद खाली पड़े हैं। 10 करोड़ से ज्यादा उन्हीं के बेटे-बेटियों व अन्य बेरोजगार हैं। उन्हें रोजगार दिया जाये, जबकि हमारी सेना को तत्काल 20 लाख से अधिक 50 लाख करने की जरूरत है। देश के सरकारी स्कूलों में 10 लाख से ज्यादा शिक्षकों की कमी है। उनमें भर्तीयां पहले की जायें तो गरीब, मजदूर, किसानों की वार्षिक आय की अपेक्षा जो कि 10 से 12 घंटे काम करके भी दो वक्त की रोटी को तरस जाते हैं। कई गुना ज्यादा वेतन मिल रहा है। मप्र सरकार ने भी विधायकों का वेतन 75 हजार मासिक से बढ़ाकर सवा लाख रुपए करने की तैयारी कर ली है। भले ही सरकार को कर्ज लेकर सरकार चलानी पड़ रही है। ये है धूर्त दानवों की करतूत जिन्हें जनता ने चुनकर उनके कल्याण के लिये भेजा था, स्वकल्याण में जुटे हैं। राजभोगीयों को नया वेतनमान देने को तैयार है। परंतु बेरोजगारों को रोजगार देने तैयार नहीं।

भा.चि.परि., विश्व स्वास्थ्य बिगाड़ो संगठन की कठपुतली

घातक दवाओं से घातक बीमारियों बांटो फिर नियमित करो वसूली

एप्रिन के गिद्धों अपनी कमाई के लिए पहले घातक दवाओं से घातक बीमारियां यथा हृदयाघात, यकृत, मस्तिष्क स्त्राव बांटते हैं, फिर अध घायलों को बेहोशी में कोमा में बताकर हृदय, यकृत, गुर्दे, आंखें व शरीर के अन्य हिस्से करोड़ों में प्रत्यारोपित कर लूटते हैं सगे संबंधियों को संवेदनात्मक तरीके से बरगलाकर कागजात पर हस्ताक्षर करवा

भारत के आयुर्वेद ने विश्व में न केवल मनुष्यों वरन् जानवरों पशु, पक्षियों, वृक्षों, फसलों की भी स्वास्थ्य और दीर्घायु जीवन के लिए औषधियां, जिसमें वनस्पतियों से धातुओं से, खनिजों से, मंत्रों से, सुगंध, धूम, तरंगों, किरणों के साथ जैविक पदार्थों जिसमें स्वमूत्र, गौमूत्र, गोबर आदि तक से चिकित्सा पद्धतियां का वृहत वर्णन लिया है। साथ ही आहार, विहार, योग परहेज आदि की भी वृहद की। जो युनान से जाकर यूनानी और चीन में जाकर चीनी चिकित्सा पद्धति हो गई, हालात यहां तक हो गए कि भारत के वनों में उत्पन्न होने वाली जड़ी-बूटियों, वनस्पतियों का सबसे ज्यादा आयात और उपयोग चीन करते है।

अंग्रेजों भारत को कब्जे में करते ही सबसे पहले लंबे समय तक राज करने के लिए यहां की संस्कृत भाषा शिक्षा की गुरूकुल प्रणाली को समाप्त कर उसने चिकित्सा की आयुर्वेद पद्धति को समाप्त किया, जिस आयुर्वेद से मानव सभ्यता से वर्तमान तक भारत ही नहीं विश्वभर के लोगों ने स्वास्थ्य दिर्घायु जीवन व्यतीत किया। अर्थात पहले अंग्रेजों ने फिर धूर्त अमेरिकी औषधि और चिकित्सा उपकरण बनाने वाले गिरोह ने जिसमें बाद में ब्रिटेन, फ्रांस व अन्य देश शामिल हो गए, अमेरिकी संयुक्त राष्ट्र संघ बनाम संयुक्त शैतान संघ के अंतर्गत एक विश्व स्वास्थ्य संगठन या वर्ल्ड हेल्थ आर्गेनाइजेशन बनाम वर्ल्ड हर्जा इस आर्गेनाइजेशन बनाया, जिसका काम 1910 से लेकर 2016 तक अपनी दवायें बैचने के लिए नई-नई बीमारियों की जबरदस्ती अफवाह फैलाना और उनके दम पर दुनिया के देशों में फैले एलोपैथिक चिकित्सा संघों के माध्यम से सरकार पर दबाव बनाकर पूर्णतः औचित्यहीन दवाओं की हजारों करोड़ की औषधियां खरीद करवाकर सैकड़ों करोड़ कमीशन हजम करना हाता है। भारत में उसके एजेन्ट के रूप में भारतीय चिकित्सा संघ या इंडियन मेडिकल एसोसिएएशन काम कर रहा है। जिसने अपने इरे पैसे के कंडोम का 5 से 10 रुपए में बैचने के लिए एड्स और एचआईवी जैसी बीमारी फैलाकर प्रति दिन रुपए 10-20 करोड़ के कंडोम बैचकर प्रतिवर्ष 3000 से 5000 करोड़ कर व्यवस्था कर रहा है। बेशक वो एसटीडी व गर्भधान को रोकने का माध्यम है, तो दूसरी तरफ भारतीय संस्कृति को नष्ट कर स्वच्छंद यौनाचार का माध्यम बन गया है। फिर हेपेटाइटिस के ए से जेड तक के टीके जिसकी कीमत रुपए 2 से 25 के बीच थी रुपए 4500 से 6-7 हजार तक में बैचा गया। फिर स्वाइन फ्लू का वायरस फैलने की खबरें उड़ाकर हजारों करोड़ की कमाई करवाई जा रही है। पूरी दुनिया में एंटी बायोटिक्स की खतरनाक दवायें बिकवा और खिलाकर तात्कालिक लाभ देने वाली के सह परिणाम स्वरूप दुनिया में दिल, यकृत, प्लीहा, गुर्दे मस्तिष्क स्राव के मामले पिछले 20 वर्षों में बड़े तेजी से सामने आए, अकेले इंदौर में ही 5000 से ज्यादा दिल के मरीज 25000 से ज्यादा गुर्दे के मरीज है। इनकी एलोपैथी में जो इलाज है। सीधा बदल दो बदले में लाखों रुपए की कमाई सीएचएल, मेदांता, सुयश, बॉम्बे हास्पिटल, टी चेइयराम जैसे अनेकों करते है। ये धूर्त शूकरों की फौज तो मुर्दों से भी लाखों रुपए के बिल वसूलने में सिद्धहस्त है। फिर भले ही छापने के बाद सीएचएल को एक बार तीस और दूसरी बार 300 करोड़ आयकर की शरण में डालने पड़े हो वो चलेगा, पर बीमारों से लेकर मुर्दों के परिजनों से लूटने से नहीं चुकेंगे। आखिर भारतीय चिकित्सालय संघ इस लूट पाट को रोकने की कोशिश क्यों नहीं करता? यदि इनका उद्देश्य लूटना और लुटाना ही है, तो इन सफेद एप्रिन के गिद्धों को सारा तांडव करने दो, जहां तक भारत के और प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्रालयों का सवाल है, तो वहां इंडियन एब्युसिंग सर्विस के गिद्धों की इनसे बड़ी फौज है। उसे नैतिकता और जनता के स्वास्थ्य से नहीं वरन् स्वास्थ्य के नाम पर उन्हें अपनी मोटी कमाई से मतलब होता है। इन हरामखोर टुकड़ाखोरों को टुकड़े डालो और कुछ भी करवा लो उसी का परिणाम था कि सन् 2004 में कांग्रेस के आते ही इन धूर्त शूकरों की फौज ने विश्व स्वास्थ्य बिगाड़ों संगठन बनाम वर्ल्ड हैल्थ डिस्ट्राय आर्गेनाइजेशन के इशारे और उनके भारतीय एजेन्ट इंडियन मेडिकल एसोसिएएशन के माध्यम से अरबों रुपए का टुकड़ा डाल पूरे देश में औषधि परीक्षण की किसी पर भी कभी भी, कैसे भी खुली छूट देकर लाखों बीमारों को इन डॉक्टरों के माध्यम से बदले में हर परीक्षण की कीमत में हजारों रुपएए और साथ में मोटी भेंट स्वरूप विदेश यात्रायें आदि की सुविधा देकर इस देश के बीमारों को जानवर की भांति व्यवहार कर औषधि परिक्षण के चक्कर में लाखों लोगों के कुलों को, घर के कमाऊ सदस्यों को खुले में मौत का शिकार बनाया, जिसका सीधा कांडों का विवरण वर्षों तक समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाकर सरकार की जांच की नौटंकी पर अटका हुआ है। जबकि भाजपा की मोदी सरकार के अस्तित्व में आने के दो वर्ष बाद भी भारत में युरोप की औषधि कं. का सीधा मानव बीमारों पर औषधि परीक्षण की नौटंकी बंद की गई, न ही इस भा.चि. संघ ने स्वयं ही इस पर तो कार्रवाई की गई जिन पीड़ितों पर परीक्षण किया उसके स्वरूप हुई मौतों पर राष्ट्रीय व प्रादेशिक सरकारों ने उनके परिजनों को कोई क्षतिपूर्ति ही दी गई, यह सब वर्ल्ड आर्गनाइजेशन और इंडियन मेडिकल एसोसिएएशन का ही षड्यंत्र था, जिसमें 12 वर्ष में पूरे देश के हर सरकारी और निजी चिकित्सालयों में औषधि परीक्षण के चक्कर में लाखों बीमारों का चुपचाप मौत की नींद सला दिया गया और कांग्रेस और भाजपा की सरकारें मोटा कमीशन हजम कर सोती रही और ये एलोपैथिक डॉक्टर्स मौत का तांडव करके कमाई करते रहे।

(शेष पृष्ठ 4 पर)

मप्र लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग- हत्या के अपराधी को बोलबाला

भ्रष्ट मंत्री, प्र.स. अभि. ने वसूली के लिए विभाग किया बर्बाद

हरामखोरों से जानकारी मांगने पर, जालसाज प्रधान सचिव अश्विनी राय तक पत्र अंतरित करने की अपेक्षा, साफ मना कर देते हैं

पूरा मुख्यालय पर आपराधिक जालसाज प्र.अ. डामोर का कब्जा, नीचे बैठे अधिकारी परेशान सारे विरोधियों को आरोप पत्र

मप्र लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग में बैठी मंत्री कुसुम महदेले को बच्चे को लात मारने के अपराध से सरकारी भ्रष्ट अधिकारियों ने यथार्थ पर लीपापोती कर भले ही साफ पाक बरी कर देने से वो भ्रष्ट साफ पाक नहीं हो जाती। दूसरी ओर इस घटना से इस मंत्री की मानसिकता और इसके अंतर्गत कार्यरत मंत्रालयों, यथा लो.स्वा.यांत्रिकीय, उद्यानिकी एवं वानिकी, पशुपालन विभागों को भ्रष्टाचार का बोलबाला है ही, परंतु इस मंत्री के अंतर्गत कार्य करने वाले सभी विभागों में निष्क्रियता और निकम्मेपन के कारण ऊपर बैठे संचालकों, सचिवों, प्रधान सचिवों के भ्रष्टाचार का नेत्रहीन कानून चल रहा है। मंत्री को मात्र अपने मोटे कमीशन से मतलब है। विभाग में क्या हो रहा है, कैसे चल रहा है, क्या परेशानियां है। आवश्यक कार्य के लिए धन का पर्याप्त आवंटन हो रहा है या नहीं, आवंटन के उपरांत उस धन का क्या उपयोग, सदुपयोग, दुरुपयोग हो रहा है या अनुपयोग होकर आवंटन की निरस्त हो रहा है। इससे मंत्री को कोई लेना-देना नहीं, पशुपालन उद्यानिकी एवं वानिकी में तो अधिकांश खरीदी, कार्य, कागजों पर दिखाकर 60 प्रश धन विशुद्ध भ्रष्टाचार में ही समाप्त हो जाता है। इसका सीधा संबंध जनता से नहीं होता। इसके विपरीत मप्र लोक स्वा. यांत्रिकीय का सीधा संबंध पूरे प्रदेश के नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों की पेयजल व्यवस्था से होता है। इस तकनीकी कार्य विभाग में जिस अपराधिक प्रवृत्ति का जिसके ऊपर अनेकों हत्याओं के आरोप थे, अपनी अपराधिक मानसिकता के चलते पूरा विभाग में उसी शैली में कार्य कर रहा है। जो उसके इशारों पर नाचते हैं। उनको मनचाही पदस्थापना, कमीशन पर आवंटन उनके सभी भ्रष्टाचारों पर अनेकों शिकायतों के बाद भी जांच तो दूर पूछताछ भी नहीं की जाती, जो इसके इशारों पर नहीं नाचते,या उसकी कार्य शैली का विरोध करते हैं। उनको भारी प्रताड़ना, जांच, वेतन न देना तक के साथ उनकी जांच, अधिकारी विहीन करना, अखबारों में बदनामी करना, आदि जो अधिकतम किया जा सकता है किया जाता है, जैसा कि यांत्रिकी खंड इंदौर के का.यं. चैतन्य रघुवंशी के साथ इस जालसाज ने पिछले वर्ष किया, जिसके विरोध में का.यं. की न्यायालय की शरण लेना पड़ती है। उच्च न्यायालय इंदौर हस्तक्षेप के बाद पुनः पदभार दिया गया।

इस डामोर की अपराधिक मानसिकता से प्र.स. अश्विनी राय भी डरता है। इस कारण सूचना के अधिकार में जानकारी मांगने पर जानकारी देने की अपेक्षा यहां वहां अंतरित कर बचने की कोशिश करता है। अन्यथा यह शूकर स्पष्ट लिखकर कि हमसे संबंधित नहीं। आखिर जनधन से लाखों रुपए प्रतिमाह का वेतन व अन्य सुविधाओं के साथ करोड़ों रुपए की रिश्वत डकारने वाला सत्ता तुम्हारी जागीर नहीं, अपनी जिम्मेदारी से कब तक बचोगो। सूचना अधिकार अधि. का उद्देश्य था। पारदर्शिता लाना, पर जहां तरफ हर शाख पर गिद्धों का बसेरा हो, वो सूचना के अधिकार अधि. 05 की मूल धाराओं का उल्लंघन कर उस भ्रष्ट, जालसाज इकबाल अहमद के दिये निर्णयों को देलीले देने में, प्र.स. अश्विनी राय, कार्यवाहक प्र.अ. डामोर, इंदौर परिक्षेत्र का प्रभारी मुअ सोनगरा, इंदौर वृत्त का अं.यं. मिश्रा तक बैठा जालसाजों का गिरोह आवेदन तक अपने अधीनस्थों को नहीं भेजता, जबकि वसूली में सारे हरामखोर भारी विशेषज्ञ हैं। फाइलें अटकाना, आवंटन बिना कमीशन जारी न करना, स्वीकृति, आदेश, स्नानांतरण, स्थाईकरण, पदस्थापना, सब में बिना वसूली कोई काम नहीं होता, जनता को पेयजल मिले न मिले, इनको पर्याप्त भ्रष्टाचार का धन अवश्य मिलना चाहिए, स्वाभाविक है मंत्री को भी पाइप लाइन का पैसा अवश्य पहुंचता है। इसलिए मंत्री को यथार्थ में विभागों से नहीं उनके धन से मतलब है। फिर 2 वर्ष से ज्यादा समय से मंत्री रहने के बाद भी, उसे अभी भी यह नहीं मालूम होगा कि किस विभाग में कौन सा काम होता है। उसमें कौन-कौन सी योजनाएं है किसमें कितना धन केंद्र और राज्य से आता है। क्या लक्ष्य हैं, क्योंकि इन सबका का लक्ष्य जनहितों की आड़ में, जनधन से येन-केन प्रकरेण अपना, अपनी भावी पीढ़ियों के लिए जन-धन बटोरना है।

बजट 16-17 जनता से लूट-पूंजीपतियों पर मत लुटाओ जन-धन

रक्त पिपासु दानव मोदी-सत्ता बाप की जागीर नहीं, चारों तरफ बर्बादी

पेज 1 का शेष

यथार्थ में बजट आंकड़ों की बाजीगरी होती है। इस बजट में भी केवल करों से जिसमें आयकर, सेवाकर, एक्साइज, केन्द्रीय विक्रय कर, संपत्तिकर, निगम कर आदि से ही आय को आय माना गया, जबकि पेट्रोलियम पदार्थों पर जो 400 प्रश वसूली की जा रही है। जो लाखों करोड़ प्रति वर्ष होती हैं उस आय को इस बजट में नहीं दिखाया गया जबकि इंडियन आइल, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, सब भारत सरकार की कंपनियां है। वास्तविक कीमत से 4 गुना महंगा पेट्रोल, डीजल और सीएनजी, पीएनजी गैस बेचकर कमा रही है। शायद पूरा अंबानी की बपौती है।

इसी प्रकार 27 राष्ट्रीयकृत और भारतीय स्टेट बैंक व उसकी 5 अन्य बैंक जो लाखो करोड़ लाभ जनता को लूटकर कमा रही है। उसका भी हिसाब किताब और आय के आंकड़े बजट में नहीं है। क्या वित्त मंत्री अरुण जेटली जिन्हें भीषण मंत्री, दानव मोदी, तीसरा सत्ता का दलाल अमित शाह ने मिलकर नए विदेशों में बैंक खाते खोलकर सारी बैंको का लाभांस वहां सटकाना शुरू कर दिया, इसलिए अब पूंजीपतियों, सत्ता में बैठे महाधूर्त, मक्कार, चालाक इंडियन एव्यूसिंग, सर्विस के अधिकारियों का पूर्व के मंत्रियों, नेताओं का विदेशों में पड़े कालेधन का राग ही अलापना बंद कर दिया, फिर बैंकों को इसके बाद भी हजारों करोड़ का घाटे से उबारने के लिए जन-धन से पैकेज क्यों दिए जाते हैं। जबकि सारी सेवाओं पर कई गुना शुल्क के साथ, नोट गिनने तक का शुल्क, ब्याज की मन मानी दरें जबकि जमाओं पर मात्र 0.5 प्रश वार्षिक से अधिकतम 8.5 प्रश ही ब्याज दिया जाता है। जबकि ब्याज की वसूली न्यूनतम 12 प्रश से अधिकतम 24 प्रश तक की जाती है। जिन ऋणों पर शासकीय योजनाओं के अंतर्गत कम दरों पर ऋण दिया जाता है उसके ब्याज का अंतर स्वयं केन्द्र व राज्य सरकारें चुकाती है।

बीमा कं. यथा भारतीय जीवन बीमा निगम, न्यू इंडिया नेशनल यूनाइटेड आदि के भा. संचार निगम, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम राष्ट्रीय जल विद्युत निगम का जो कि 60-70 पै. की बिजली राज्य सरकारों और उद्योगों को बेचकर हर घंटे सैकड़ों करोड़ रुपए कमाते है। उस लाखों करोड़ के लाभांश का भी बजट में नामो निशान नहीं है। भारतीय स्टील प्राधिकरण लि. भारतीय खनिज विकास निगम, प्राकृतिक गैस व तेल आयोग भारतीय गैस प्राधिकरण आदि का लाखों करोड़ का लाभांस क्या ये दानवों का गिरोह भाजपाई मोदी, जेटली, शाह व अन्य हड़पकर विदेशों में ही सीधा भेज रहे हैं। आखिर ये विशुद्ध मुनाफा देने वाले नवरत्न उपक्रमों की राष्ट्र के बजट में कोई भागीदारी नहीं।

जबकि भारत संचार निगम लि. अरबों रुपए प्रतिदिन की धोखाधड़ी जिसमें काल ड्रापिंग, मोबाइल पर नेट शुल्क, अपने मोबाइल के 30 करोड़ ग्राहकों से कालर टोन विशेष छूट योजना आदि के माध्यम से हजम करने के साथ ही सभी मोबाइल सेवा प्रदाताओं को भी अपने ही तंत्र के माध्यम से ही उनको सेवाएं देकर लाखों करोड़ की कमाई कर रहा है क्या रविशंकर प्रसाद सीधे ही उनको सेवाएं देकर लाखों करोड़ की कमाई कर रहा है। सारे डाकुओं ने सत्ता को अपनी जागीर समझकर कमीशन के अतिरिक्त भी हड़प रहे है। सरकारी कोयला कं. उत्तरी कोयला क्षेत्र क्रं. पश्चिम कोलक्षेत्र कं. व अन्य कोल कं. खनिज कं. जो उत्खनन से हजारों करोड़ का लाभार्जन करती है। हर वर्ष क्या पूर्व की सरकारों और उनके मंत्रियों की तरह ये गिद्धों की फौज सीधा अपने स्त्रोतों से प्राप्त आय क्या इन शूकरों आईएएस व उनके मंत्रियों का गिरोह सब ऊपर ही डकार रहा है।

वही हाल रेल बजट में किया: हर सुविधा यात्रा की दरें बढ़ाई, यहां तक कि रेलवे की डकैती का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल की कीमतें एक चौथाई रह गई। तो रेल किराया आधा ही कर देते, इसके विपरीत न केवल किराया बढ़ाया, हर सेवा की कीमतें बढ़ा दी, प्लेटफार्म टिकिट 10 रुपए कर दिया। सुरक्षा के नाम पर केवल हल्ला होता है। रोज रेलों में लूट, चोरी, डकैती, यहां तक कि लूट के लिए हत्या तक होती है। इससे बच भी जाओ तो दूर्घटनाओं का कोई हल नहीं, कभी ट्रेने पटरी से उतरती है। फिर रेलवे प्लेटफार्म पर और चलती ट्रेनों में सुविधाओं की तो दूर साफ शीतल जल भी मुफ्त में नहीं मिलता।

जो मिलता है रुपए 15 से 20 लीटर वह भी स्तरहीन,फिर रेलवे में भी भर्तीयों के अभाव में जबकि तत्काल में 1 लाख से ज्यादा हर स्तर के कर्मचारियों की आवश्यकता है। सफाई से लेकर, रखरखाव तक हर काम अपने चहेतों को ठेकों पर दिया जा रहा है। फिर इस पूंजीपतियों का रखैला प्र.मं. मोदी तो अपने आकाओं अंबानी,अडानी, टाटा आदि को रेलवे सौंपने की तैयारी में है, वह तो रेलवे के श्रमिक संघों ने हड़ताल की धमकी न दी होती तो एक दो मंडल सौंप ही दिए होते।

अपनी मोटी कमाई और गरीबों व मध्यमवर्गीय के मुंह से निवाला छीनने के लिए हर सेवा पर सर्विस टैक्स को 14.5 प्रश से बढ़ाकर 15 प्रश कर दिया गया। जिससे ब्रांडेड वस्त्रों से लेकर आभूषण, सौंदर्य प्रसाधन, सौंदर्य सेवाएं तक सब महंगी कर दी गई।

किसानों के नाम पर रुपए 9 लाख करोड़ के कर्ज की घोषणा

अर्थात भारतीय कृषि का अटल सत्य भारतीय किसान कर्ज में जन्म लेता है, जीता है और कर्ज में ही मर जाता है। जबकि यथार्थ में कर्ज की अपेक्षा उसे ठोस फसल बीमा योजना को लाभ देकर, जिसमें न केवल फसल बिगड़ने वरन फसल अच्छी होने पर भी उसकी फसल के लागत मूल के समक्ष 25 प्रश उसकी मेहनत का भी भुगतान किया जाना चाहिए।

जैसे की तत्काल में देखें तो उसने खरीफ रबी की फसल बिगड़ने की भारी हानि भुगतने के बाद भी प्याज बोया तो इतनी फसल पैदा कर ली कि उसे खेत में से निकालना भारी पड़ गया और 5 रुपए किलो में बेचना पड़ गई। पर सरकार ने कोई मदद नहीं की। जबकि वह रुपए 4 प्रति किलो में खरीदकर रख सकती थी। न ही बहुराष्ट्रीय क्षेत्र ने खरीदा और उसे फसल का प्याज जलाना पड़ा। इसके विपरीत पिछले ही वर्ष सरकार ने रुपए 25 प्रति किलो का लाखों क्विंटल आयात कर रुपए 40 से 50 रुपए किलो बिकवाया था। वैसे भी मोदी के सत्ता को जालसाजी से हथियाने के बाद सबसे ज्यादा प्राकृतिक कहर किसानों पर ही बरपाये हैं। अच्छे बुरे की पहचान वैसे तो किसानों की बर्बादी और पूंजीपतियों की नोंच खसोंट ने आम आदमी को महंगाई बुरी तरह से आंतरिक रूप से प्रताड़ित कर रही है। तो त्राहि-त्राहि कर रहा है।

भू-तल परिवहन मंत्री महाधूर्त: पूंजीपति, उद्योगपति, महाजालसाज नितिन गडकरी जिसके देश में अनेकों बीओटी सड़कों का मालिक है। पेट्रोल-डीजल पर 400 प्रश से ज्यादा कीमत वसूलने के बाद भी सड़कों पर टोल टैक्स को तो हटा नहीं पाया है। उल्टे ही बजट में एक तरह जन-धन से रुपए 50000 करोड़ से व्यवस्था की गई तो दूसरी तरफ 90 प्रश राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल टैक्स की दरें भी 10 से 20 प्रतिशत बढ़ा दी गई, जबकि जालसाज केन्द्रीय एक्साइज जो 50 से 80 प्रश तक केन्द्रीय विक्रय कर 6 से 10 प्रश और राज्य का विक्रय कर 12.5 प्रश वसूलने के बाद भी मार्ग कर 7 प्रश और पंजीयन शुल्क भी वसूलते है। अर्थात सरकारी डकैती मोटी होने के बाद भी सड़कों का उपयोग भी हर किमी पर रुपए 2 से बड़े वाहनों के लिए रुपए 20 प्रति किमी तक मोदी के अच्छे दिन वाहनों के मालिकों पर शासकीय डकैती से।

स्टार्ट अप का राग तो बड़ा अलापा जा रहा है। परंतु शासकीय तंत्रों में बैठे गिद्धों की फौज, स्टार्ट करने से पहले ही लूटने को तैयार खड़ी देखकर, इरादा ही बदल देती है। खाद्य इकाई लगाने को तैयार मेरे अपने मौसेरे भाई ने बताया कि खाद्य का पंजीयन कराते ही रु.10000 महीना खाद्य निरीक्षक को देना पड़ता है। उद्योग में पंजीयन पर रु. 25000 अर्थात रुपए 1 लाख की भेंट स्टार्ट पर चढ़ाने, जबकि जमीन शेड, मशीनों,आदि के लिए कुल कर्ज का 10 से 20 प्रश बैंकों के गिद्धों को भी चाहिए हो गया स्टार्ट डाउन।

हर शासकीय अस्पतालों में डायलेसिस की व्यवस्था की जाएगी अर्थात देश की आधी आबादी को बहुराष्ट्रीय कं. के प्रोसेस फूड और जहरीली खतरनाक औषधियां खिलाकर पहले उसके शरीर को कमजोर और बीमार बनाओ फिर जन-धन खर्च कर चिकित्सा कर तो कर एहसान बताओ, इसके विपरीत इन सब तथ्यों से दूर, उल्टे ही परिष्कृत खाद्य में 100 प्रश विदेशी निवेश का निमंत्रण देकर देश लुटवाने और बीमार करने की व्यवस्था कर दी जाती है।

बैंकों के लिए रुपए 25000 करोड़ से पुनः पूंजीकरण

अपने आकाओं को लाखों करोड़ रुपए जन-धन से ऋण बांटों, बाद में किसी भी बहाने माफ कर दो। फिर जन-धन से घाटे की भरपाई के लिए पुनः पूंजीकरण के नाम पर लुटा दो।

परमाणु ऊर्जा के नाम पर केवल मोटा कमीशन हड़पने

टाटा, अंबानी, जैसों को लाभ पहुंचाने के षड़यंत्रों के अतिरिक्त कुछ नहीं। अकेले मप्र में 15500 मेंवा का उपयोग हो नहीं पा रहा। ऊपर से मंडला में परमाणु बिजली घर लगाया जा रहा है। इन जालसाजों को देश के भविष्य से मतलब नहीं चाहे, फिर सहस्त्रों वर्षों तक जनता उसका अभिशाप भोगती रहे। बजट में जन-धन के लूट की व्यवस्था का बड़ा हिस्सा है। परमाणु ऊर्जा है।

श्रमिकों के संबंध में

ये सरकार कांग्रेस से ज्यादा बत्तमीज और शोषण कारी है। यहां तक की उसकी जीपीएफ और ईपीएफ एक तक पर डकैती डालने की ताक में है।

साप्ताहिक समय माया

सिंहस्थ आयोजन के नाम भ्रष्टाचार और लूटपाट का तांडव

जनधन के रुपए 10000 करोड़ में से रुपए 5000 करोड़ हजम

पेज 1 का शेष

स्वाभाविक है सब मौके का फायदा उठाएंगे और फायदा सब ने ही उठाया है। कार्यों को शीघ्र पूरा करने के लिए 5 प्रधान सचिवों को वहां पदस्थ पदस्थ किया गया है। ये वरिष्ठ आईएएस अर्थात वरिष्ठ इंडियन एव्यूसिंग सर्विस अधिकारी जिन्हें किसी भी विषय की न तो विशेषज्ञता है न ये स्वयं कुछ कर सकने में सक्षम है। जिनमें पद, प्रतिष्ठा का दम कूट-कूट कर भरा होता है हर जगह हर कार्य में इन हरामखोर, जालसाजों को अपना शेरू हिस्सा डकारने शाम ढलते ही मुफ्त की सुरा सुंदरी का और श्वान कबाब का भोग मिल जाए तो परम संतुष्टि होती है। जिसकी व्यवस्था जन-धन से हो ही जाती है। निःसंदेह वह खर्च होने वाला धन कागजों में कहीं नहीं आता परंतु जन-धन में हुए भ्रष्टाचार का धन तो अवश्य होता है। अब ये 5.7 प्रस कुछ करें या नहीं परंतु पद और प्रतिष्ठा के अनुरूप उन विभागों के दो वरिष्ठ इंजीनियरों, डॉक्टरों, अधिकारियों को अपनी आगे-पीछे चलने के लिए जरूर रखते थे। जो साहब की बोतल, नाश्ता, पानी, भोजन आदि की व्यवस्था कर सके और साहब के पद और प्रतिष्ठा का ब्यान कर साधु-संतों से लेकर जनता को हड़का सके।

मप्र लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय

सिंहस्थ की व्यवस्थाओं ने इस विभाग का कार्य यात्रियों और साधु-संतों को स्वच्छ पेयजल और जल-मल निकासी की व्यवस्था मेला परिक्रमा क्षेत्र और साधु-संतों के निवास क्षेत्र में करना थी, जिसमें पेयजल के लिए 50 किमी से ज्यादा 2 से लेकर 12'', 15'', 18'', 21'', 24'' पाइप लाइन बिछाना, पानी की टंकिया रखना, हैड पंप खुदवाकर जल आपूर्ति करना, इसके साथ ही इतनी ही लंबी पाइप लाइने डालकर जल-मलि निकासी की व्यवस्था करना जो 50000 शौचालय, मूत्रालयों के साथ ही स्नानागरों की व्यवस्था करना, जो कि अभी तक पूरी होना तो दूर, जो आधी अधूरी व्यवस्थाएं की गई थी, वो भी 21 अप्रैल 15 के प्रथम स्नान से पूर्व ही बुरी तरह ध्वस्त हो चुकी थी। जिसके मूल में वृहद स्तर पर भारी भ्रष्टाचार और जन धन में डकैती डालने की नियत ही सामने आई है। 50000 शौचालयों में से मात्र 10000 से 15000 शौचालयों का निर्माण जिसमें प्रत्येक शौचालय पर रुपए 28 हजार खर्च किए गए मे कार्य भी मात्र रुपए 6 से 8 हजार का ही किया गया जो पाइप लाइन पेयजल और जल-मल निकासी के लिए बिछाई गई थी वो पूर्णतः स्तरहीन और घटिया होने के कारण सिंहस्थ की शुरूआत से पूर्व ही फटने और फूटने लगी थी, पाइप लाइनों में पानी के ढाल के ओर बहने तक पर ध्यान न देने के कारण, लाइनें ऊपर-नीचे ऊबड़-खाबड़ तरीके से बिछाने से जगह-जगह पानी और गंदगी के रूकने से लाइनें फूटना-फटना शुरू हो गई, जिससे 5000 से ज्यादा प्लाटों पर पेयजल व जल-मल निकासी की घोर समस्या से साधु-संतों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जिससे उनमें घोर आक्रोश व्याप्त है। कई स्थानों पेयजल और जल-मल निकासी की लाइनें फूटकर पेयजल में मिल जाने, शौचालयों के नीचे गड्ढे खोदकर वहीं निस्तारण के कारण वही दूषित जल हैडपंपों के पानी में मिलकर भी आश्रमों में साधु-संतों को समस्या पैदाकर आक्रोश का कारण बना जिसके पीछे घोर भ्रष्टाचार से धन हड़पने के लिए अपने चहेते, नवसिखिए ठेकेदार और अनुभवहीन व घोर भ्रष्ट व निकम्मा स्टाफ है। अनुभवी, कर्मशील, सहा. यंत्रियों, अधीक्षण यंत्रियों को भोपाल, मुख्यालय व अन्य मुख्य अभियंता, अधीक्षण यंत्री कार्यालयों में बैठाकर मुफ्त वेतन बांटा जा रहा है। मात्र इसलिए कि वो उस हत्यारे प्र.अ. डामोर को मनचाहा भ्रष्टाचार कर धन नहीं दे सकते, ऐसे दो अ.मंत्रियों सीक्रे सिंग, जाधव, का.यं. व अन्य भोपाल में बैठा है।

इस विभाग की घोर बत्तमीजी और भ्रष्ट मंत्री कुसुम महदेले जिसे विभागों से बिलकुल मतलब नहीं उसे केवल धन और रुतबा चाहिए, इस मंत्री के अंतर्गत न केवल लो.स्वा.यां. वरन् उद्यानिकी, पशुपालन, मत्स्य विधि और विधायी कार्य के भी ये ही हाल है। कोई भी फाइल बिना भेंट पूजा के आगे नहीं बढ़ती, स्वाभाविक भ्रष्टाचार अपने चरम पर है, जिसका सीधा असर सिंहस्थ की व्यवस्थाओं पर पढ़ रहा है। रुपए 800 करोड़ से ज्यादा खर्च करने के उपरांत भी साधु-संतों के डेरों पर पेयजल और जलनिकासी की उचित व्यवस्था नहीं कर पाए हैं।

शायद ये भ्रष्ट शूकरों और निकम्मों की फौज पूरा सिंहस्थ गुजर जाने के बाद भी कार्य पूरा नहीं कर पाएगी। ये हरामखोर और जालसाजों की फौज येन-केन प्रकरेण समय गुजरने का इंतजार कर रही है। ताकि आसानी से आवंटित धन से कागजी कार्यवाही कर हजम कर सके। यहां बैठा प्रमुख अभियंता जीएस डामोर जो छः हत्याएं कर के भी न्यायालयों में धन, बल, जालसाजियों के दम पर बरी होकर लूट और भ्रष्टाचार के दम पर प्रमुख अभियंता कन प्रभार संभाले हुए है। जबकि इसके विरुद्ध अनेकों विभागीय और लोकायुक्त जांचे लंबित है। पर ये आपराधिक प्रवृत्ति का प्रमुख अभियंता की कमान संभाले है। स्वाभाविक है, उज्जैन में लो.स्वा.यां. के कार्यो में लूट पाट का तांडव मचाकर साधु-संतों को तकलीफ देगा, जिसका सीधा परिणाम शिव चौहान का भोगना पड़ेगा। दूसरी तरफ हाल ही में बैठाए गए प्र.स. पंकज अग्रवाल जिसे इंजीनियरिंग की एबीसीडी नहीं आती को भी यहां पेयजल और जल निकासी की व्यवस्था के लिए भेजा गया है। स्वभाविक है, भ्रष्ट मुख्य अभियंता सोनगरिया के भ्रष्टाचार और लूट की गाथाएं पूर्व में समयमाया के पाठक पढ़ ही चुके है। उज्जैन में पदस्थ अंधीक्षण यंत्री दीपक रलावत, का.यं. धर्मेन्द्र वर्मा सिंहस्थ, का.यं. सुनील उइया उज्जैन संभाग, यांत्रिकीय खंड उज्जैन के का.यं. अहिरवार व अन्य कायं. सहा. यंत्री और उपयंत्रियों की वही गिरोह चुन-चुनकर यहां कार्य संपन्न करने के लिए लाया गया है। जो काम न्यूनतम और भ्रष्टाचार से लूटपाट कर स्वयं भी अपनी जेबें भर सकें और अपने वरिष्ठों को भी शक्कर के बोरे भर के दे सके, ये सभी वो हरामखोर जालसाजों की फौज है, जो सूचना अधिकार का आवेदन देखते ही जानकारी न देने के बहाने ढूंढती है, इस सिंहस्थ के 25 से 40 प्रश बिल फर्जी बनाए जाकर कार्यों को कागजों पर ही संपन्न कर दिया जाकर पैसा हजम कर लिया गया है कोई भी कार्य नियम कानून की तो दूर, सारे कार्यों में क्रय की सामग्री 50 से 200 प्रश ज्यादा कीमतों में खरीदी गई जिसमें पाइप लाइन, पानी की टंकिया, हैंड पंप, विद्युत मोटरें, विद्युत सामग्री, शौचालयों की सामग्री, शेड्स, प्लास्टिक शीट्स आदि, ठेकेदार जो काम कर रहे है। चुन-चुन कर ऐसों को काम दिया गया है जिन्हें काम का अनुभव ही नहीं है। इसके विपरीत उन्हें काम दिया ताकि उनसे दोगुने-चौगुने बिल बनवाकर, भुगतान में से 25 से 80 प्रश तक वसूली की जा सके, स्वाभाविक है जल प्रदाय पर्याप्त और समय पर नहीं मिलेगा और जल निकासी की लाइनें फटेंगी और फूटेगी, साधु-संत इन परेशानियों के चलते तांडव करेंगे व इस गिरोह को अभिशापित भी करेंगे, जिनकी शक्ति का प्रदर्शन और सत्यापन इस कलियुग में भी हो सकेगा, शेष अगले अंकों में...

उज्जैन नगर निगम

उज्जैन नगर निगम को लगभग रुपए 1500 करोड़ से ज्यादा का बजट पिछले 5 वर्षों में केवल सिंहस्थ के नाम से आवंटित हुआ जिसमें आयुक्तों से लेकर महापौरों, दोनों सत्रों के पार्षदों, वहां बैठे भ्रष्ट धूर्त इंजिनियरों, उपायुक्तों, अधिकारियों, सफाई शाखा, विकास शाखा ने लगभग रुपए 500 करोड़ सड़कों, नालियों, शौचालयों, स्नानागर, मूत्रालयों के निर्माण टेंटों तंबुओं की व्यवस्था निगम के जलापूर्ति के पीएचई के इंजिनियरिंग शाखा नालियों के निर्माण आदि में भी रुपए 2 अरब हजम किए गए। सारे पार्षद, कर्मचारी, लिपिक, लेखा शाखा के सब ही हरामखोर जालसाजों ने अरबों रुपए के कार्यों को कागजों पर ही दिखाकर हजम कर लिया, अकेले शौचालय रुपए 25000 प्रति शौचालय के हिसाब से बनाए गए मात्र 20000, वही हाल स्नानागर में हुआ रुपए 20000 प्रति के हिसाब से बनाए गए 8000 वास्तविक कीमत रुपए

5-6000 बनने थे। 16000 वही हाल मूत्रालयों के निर्माण में हुआ। 7000 मूत्रालयों में से बनाए गए मात्र 4000 प्रति 15000 कार्य हुआ मात्र रुपए 3000 का, अर्थात लगभग रुपए 2000 करोड़ में कार्य हुआ मात्र रुपए 500 करोड़ का।

निगम के पार्षद अधिकारी-कर्मचारी, इंजिनियर्स से लेकर आयुक्त और महापौर हजम कर गए, फिर साफ-सफाई के ठेके में मामला सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंच गया, वहां से भी कं. के पक्ष में फैसला आ गया, स्वाभाविक निजी कं. ने 50000 सफाईकर्मियों को लगाने की बात कही 3 शिफ्टों काम करने के स्थान पर कं. ने मात्र 25000 कर्मचारियों से दो शिफ्ट में काम करवाया पुलिस वालों की तरह 6-6 घंटे की पाली में कार्य करवाया, ठेकों में जमकर 20 से 50 और 60 प्रश तक की कमीशनबाजी हुई। सैकड़ों करोड़ के कार्यों को कागजों पर ही संपन्न करके हजम कर लिया गया फिर 5 विभागों के प्रधान सचिव, जिसमें शहरीय विकास के सचिव निगमायुक्त, संभागायुक्त, कलेक्टर के साथ नागरिक आपूर्ति, लोक निर्माण, लो.स्वा.सां, जल संसाधन ने भी दोनों हाथों से धन बटोरा, बेशक कमीशन, मु.मं., मु.स. से लेकर संबंधित विभागों के मंत्रियों, विभागीय संचालकों, आयुक्तों तक भी पहुंचा, यही हाल स्वास्थ्य विभाग में भी हुआ। स्वास्थ्य सेवाओं के नाम पर अरबों रुपए की दवाएं व अन्य सामग्री खरीदी गई जिसमें हर खरीद में खुले में 25 से 50 प्रश कमीशन डकारा गया कुछ सामग्री केवल कागजों पर ही खरीदी व सेवायें दिखाकर हजम कर ली गई, स्वास्थ्य विभाग के अंतगर्त कार्यरत खाद्य एवं औषधि विभाग के अंतर्गत कार्यरत खाद्य निरीक्षकों को भी जिसमें वहां पूर्व से बैठे महाजालसाज, हरामखोरों की गिरोह जिसमें अमित गुप्ता, वर्षा व्यास और 3-4 नए भर्ती के साथ ही इंदौर के खाद्य निरीक्षकों सह खाद्य सुरक्षा अधिकारियों जिसमें मनीष स्वामी, खेड़कर व अन्य महिला खाद्य निरीक्षक देवास का गिरोह व अन्य जिलों से बुलाये गए निरीक्षकों का गिरोह भी खुलकर वसूली में जुटा है। सूत्रों के अनुसार 10000 से ज्यादा खाद्य लाइसेंस जारी किए गए हैं। जिसमें हर लायसेंस पर रुपए 2000 से 4000 की वसूली की गई है। किसी को भी खाद्य सुरक्षित हो इसकी चिंता नहीं है। इनकी चिंता केवल लूट और वसूली से है।

05/05/16 को 4.25 पर आए तूफान में सभी सरकारी कर्मचारियों अधिकारियों की किस्मत खोल दी, तूफान में हुए नुकसान, जिसमें सरकार मीडिया कह रहा है। 7 लोग मरे और 85 घायल हुए वहां 30-40 से ज्यादा लोग मरे, लगभग 500 से ज्यादा घायल हुए, मरने वाले में जो अकेले आए थे यथार्थ में उनकी न तो गिनती होती है या जो पूरा परिवार ही मर गया, उनका भी कोई हल्ला-गुल्ला नहीं होता, 7 जो प्रशासन ने स्वीकार किए थे वही थे जिनके रिश्तेदार या संगी-साथियों ने हल्ला मचाया पर मुआवजा मौता का 50 से ज्यादा को बांटा गया वही हाल घायलों का भी हुआ, प्रशासन ने बैठे लोगों ने घायलों को दिया नही नहीं दिया परंतु घायलों के नाम पर अपने लोगों के नाम लिखवाकर सैकड़ों का रुपए 25000 से 50000 रुपए हड़पे, फिर तूफान आने से उज्जैन नगर निगम, लो.नि.वि., लोक स्वा. यां. उज्जैन डकैत प्राधिकरण के भ्रष्टाचारों, स्तरहीन कार्यों, कागजी कार्यों जो अरबों रुपए के थे, साथ ही स्वास्थ्य विभाग, खाद्य व नागरिक आपूर्ति, सुरक्षा आदि के भ्रष्टाचारों पर लीपापोती का मौका मिल गया।

अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 500, 700, 1000 अधिकतम स्ट्रेचर रु. 57,500 में खरीदा गया जबकि एक 100 सीसी की मोटर साइकिल रु. 50,000 होती है तो रु. 500-700 का स्ट्रेचर रु. 57500 क्यों और कैसे खरीदा गया।

साधु-संतों को अपनी वाहवाही करवाने के लिए संत महात्माओं के स्तर के और लाब-लश्कर के हिसाब से रुपए 5 लाख से रुपए 5 करोड़ तक बांटे गए, रुपए 3000 करोड़ केवल अप्रेल और मई जून में ही जनधन के अनाप-शनाप कर लादकर वसूले गए थे, वैचारिक मंथन के नाम पर प्र.मं. मोदी को बुलाकर अपनी वाहवाही और कुर्सी बचाने के लिए विदेशी मेहमानों को हवाई यात्रा के टिकट, 5 स्टार होटलों में ठहरने की व्यवस्था के साथ अन्य जिलों के अधिकारी कर्मचारी पुलिस भी सिंहस्थ के साथ वैचारिक मंथन में भी झोंक दी गई जिससे अन्य जिलों का प्रशासनिक कार्य भी ठप हो गया है।

यदि सभी विभागों के विभागीय खर्च की सन् 2010 से वर्तमान सिंहस्थ तक कुल खर्च को देखा जाए तो रुपए 12000 करोड़ से ज्यादा खर्च कर दिया गया जबकि दृष्य व श्रृव्य दूर दर्शनी समाचार श्रृंखलायें, पत्र-पत्रिकाओं में मुद्रित व विदेशों में सिंहस्थ के प्रचार-प्रसार पर जन-धन के ही रुपए 1200 करोड़ से ज्यादा प्रादेशिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खर्च कर दिए, जिसमें इस धूर्त शिवराज के फोटो लगे विज्ञापन भी थे, जैसे जन-धन इसके बाप की जागीर हो, इसके पहले जनहित याचिका पर कानून बनाकर प्रतिबंध लगवा दिया गया, 3 वर्ष से ज्यादा का रिकार्ड नष्ट करने का कानून बनाकर न केवल अपने पापों को वरन हर सत्ताधीश को बचाने का रास्ता साफ कर दिया। वल्लभ भवन के मंत्रालयों को आग लगवाकर नष्ट कर दिया गया, कब तक मुख्यमंत्री शिवराज अपने भ्रष्टाचारों और चापलूसी को बचाओगे, जन-धन की लूट-पाट का तांडव करोगे? बस! बहुत हुआ।

जन मानस उबल चुका है। प्रभु बुलाओ इन राक्षसों को जनधन से तांडव कर अपनी पैठ जमाने में लगे है।दूसरी तरफ अपनी पोल न खुले इसलिए इन सब संस्थानों के अंकेक्षणों के लिए सीए अर्थात करप्ट अकाउंटेंट को अधिकृत कर अंकेक्षण करने की व्यवस्था कर दी गई है, ताकि वो मोटा टुकड़ा पाकर चबाता बैठे और इनके विरूद्ध सच न बतलाए, आखिर शासकीय फर्मों संस्थाओं से या एजी से अंकेक्षण करवाने में डर क्यों लगा हरामखोरों क्योंकि उनका 10-20 प्रश सच भी अरबों रुपए में होगा, जनता को इतना उत्पीड़न न दो कि वो धरती से बिदाई की कामना करने लगे। ये न्यायालय ये कानून कुछ नहीं कर लेता प्रकृति के तांडव के सामने।

चेतक चेम्बर के किराए से मोटा कमीशन पाने

अफीम गोदाम में नहीं बना रहे वा.कर कार्यालय

भूमाफिया के साथ मिल मोटा कमीशन हजम करने की ताक में मंत्री, संत्री, जिलाधीश

इंदौर-वाणिज्य कर का मुख्यालय होने के साथ ही प्रदेश की 40 से 50 प्रश वाणिज्यकर की आय देने वाला मप्र शासन का राजस्व प्राप्ति का मुख्य स्रोत होने के बाद भी, इस विभाग के इंदौर में ही अधिकांश कार्यालय मात्र कमीशनखोरी के निम्न मानसिकता के चलते किराए के भवनों में चल रहे हैं। जबकि शहर के मध्यस्थल र.ना. टै. मार्ग पर अफीम गोदाम है लाखों वर्ग फुट जमीन विभाग के पास स्वयं की होने के बाद भी वहां कार्यालय बनाने को तैयार नहीं क्योंकि उस जमीन को कानूनी दांव पेंचों में उलझाकर भूमाफियाओं के हवाले कर मंत्री, प्र.स. सचिव आयुक्त तब सब करोड़ों रुपए डकारने की जुगत में बैठे हैं। अन्यथा अंग्रेजों के समय के साथ ही होल्कर राज्य में भी वहां अफीम गोदाम था, वर्तमान में भी आजादी के बाद से अर्थात 69 वर्षों से शासन के कब्जे में है, वह बेशकीमती भू-भाग इतना सबकुछ स्पष्ट और कब्जा होने के बाद भी इन हरामखोर जालसाज सत्ताधीशों इंडियन एव्यूसिंग सर्विस के धूर्त मक्कार जिलाधीशों, वा. कर आयुक्तों की इच्छा नहीं की वहां 5-6 मंजिल का कार्यालय निर्माण किया जाये, क्योंकि किराए के भवनों में लाखों रुपए महीना कमीशन डकारने का मुफ्त का धन मिलना बंद हो जाएगा।

जबकि चेतक चेम्बर की तीसरी मंजिल से 10वीं मंजिल तक 14 वृत्तों के 2 एंटी इवेजन ब्यूरो, उपायुक्तों, नियमित, तीन अपीलीय उपायुक्त, एक अपर उपायुक्त आदि के कार्यालय पिछले 15 वर्षों से ज्यादा समय से चलाए जा रहे है। जिसमें एक बार लिफ्ट टूटने से एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है। दो-तीन बार शार्ट सर्किट्स से 6वी, 7वीं, मंजिल में आग लग चुकी है। साथ ही जब मध्यभारत को भूकंप के झटके आते हैं जिससे इंदौर भी प्रभावित होता है ऐसे समय 3री मंजिल जहां पहली मंजिल गिनी जाती है, यहां की गिनती के अनुसार 5वीं 6ठी, 7वीं, 8वी मंजिल पर बैठने वालों को ये कंपन 3 गुना ज्यादा डराता है। जहां मेज, कुर्सियों से लेकर दूसरा सामान हिलने व सरकने लगता है। पिछली बार सन् 2015 में एक झटका दोपहर 12.30 से 1 के बीच आया था, तब भी सारे कर्मचारी उतरकर नीचे की ओर भागे थे और सबने बाद में दहशत में काम नहीं किया और छुट्टी मनाने घर चले गए थे। जबकि ये भूकंप का बहुत हल्का झटका था, जबकि इंदौर संभाग में दो बड़े बांध जिसमें एक पुनासा बांध मात्र इंदौर से 90 किमी की दूरी पर नर्मदा का इंदिरा सागर बांध और दूसरा औंकारेश्वर मात्र 45 किमी दूर ही स्थित है। भूकंप के संवेदनशील क्षेत्रों में गिना जाने के बाद भी 10वीं मंजिल वाणिज्यकर के कार्यालय चल रहे है।

नए कार्यालय बाई पास के पास बनाने की तैयारी में जमीन भी देखी जा चुकी है। महिलाओं को आने-जाने में कितनी परेशानी उठानी पड़ेगी, साथ ही अभी मार्ग पर 15 वृत्त कार्यालय है, न केवल महिलाएं वरन् व्यापारी और कर सलाहकार सभी आसानी से आते चले जाते हैं। यदि नगर के बाहर इतनी दूरी पर कार्यालय खोलने से न केवल छोटे महिला पुरुष कर्मचारियों को वरन् व्यापारियों और कर सलाहकारों का भी पूरा दिन बर्बाद हो जाएगा।

शासन-प्रशासन, नगर निगम जब विकास के नाम वैध-अवैध कॉलोनियां तोड़ने और मकान तोड़कर उजाड़कर सड़के, बगीचे बनाने की मंशा पूरी करता है तो फिर 69 वर्ष से अफीम मैदान की जमीन की बाधाएं दूर कर अपना कार्यालय बनाने मेंन नकुर क्यों कर रहा है। जबकि पिछले पंद्रह वर्षों में रुपए 300 करोड़ से ज्यादा का किराए का भुगतान रुपए 30 करोड़ से ज्यादा के कमीशन पर कर चुका है। जबकि सरकारी कार्यालय में इस लूट के तांडव में सब ही हिस्सेदार है। इसलिए सब चुप हैं। इन्हीं हरामखोर जालसाजों ने जानबूझकर ये घोषणा करवाई कि वाणिज्य कर कार्यालय को वर्तमान कार्यालय से 10 किमी दूर भूमि मिल गई है, ताकि कर्मचारी, कर सलाहकार व्यापारी सब हल्ला, हड़ताल कर कार्यालय को वहां बनने से रोके और विकल्प की तलाश में 10-20 वर्ष तक और वे भ्रष्ट शूकरों की फौज मोटा कमीशन हजम करती रह सके। सूचना के अधिकार में वा.कर. उपायुक्त 3 से कई वर्षों से जानकारी मांगी जा रही है। पर ये भ्रष्ट हरामखोर उपायुक्त मजीद जानकारी में स्पष्ट लिख देता है कि यह जानकारी उपलब्ध नहीं, जैसे सरकारी दस्तावेज इनकी जागीर हो। बेशक कर्मचारी संगठन बाकी दूसरी नौटंकी को बहुत करते हैं, परंतु इस कार्य में पिछले 15 वर्षों में आयुक्त से मंत्री, मु.मं. से अपनी ये छोटी सी मांग पूरी नहीं करवा पा रहे हैं।

बजट के माध्यम से लूट और अपनों की कमाई व्यवस्था जनता के आंसू

पेज 1 का शेष

प्रधानमंत्री को बार-बार प्रदेश में बुलाकर अपनी गद्दी बचाने के लिए सैकड़ों करोड़ जनधन की ही बर्बादी की जाती है। बदले में भारी भरकम कर 32 प्रश पेट्रोल डीजल व गैस पर लगाकर की जाती है। प्रदेश में सबसे ज्यादा करारोपण की दरे हैं। इसलिए देश भर में सबसे ज्यादा महंगा बिकता है पेट्रोल, डीजल और गैस।

गृह रुपए 5623.38 करोड़ - पुलिस व्यवस्था के नाम पर किए गए इस बजट का 25 प्रश कागजों पर ही हजम कर लिया जाएगा। 25 प्रश बजट विशिष्ट, अति विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा पर खर्च होगा, 50 प्रश आधुनिकीकरण, रखरखाव के नाम पर खर्च किया जाएगा जिसका आधा भ्रष्टाचार की भेंट-चढ़ जाएगा, इस आंकड़े में केंद्र से प्राप्त धन भी है।

लोक स्वा. यांत्रिकीय रु. 2600 करोड़- जनता को पानी पिलाने के नाम पर इसका अधिकांश धन मंत्री, प्रधान सचिव, प्रमुख अभियंता, मुख्य अभियंता, से लेकर अधीक्षण, कार्यपालन, सहा. उपयंत्रियों तक कैसे पी जा जाते हैं वर्षों से समय माया के पाठकों को अच्छी तरह से ज्ञात होगा, वर्षभर शहरीय और ग्रामीण जनता को पानी पिलाने के नाम से प्रदेश के हर संभागीय कार्यालयों में छोटे नदी-नालों पर बांध बनाकर रोकने के लिए आवंटित सैकड़ों करोड़ रुपए अधिकांश का.यं. कागजों पर ही कार्य दिखाकर हर कार्यवाही नहीं की जाती। फ्लोराइड युक्त पानी की योजनाएं भी वर्षों से झाबुआ-धार, रायसेन विदिशा में व अन्य जिलों में वर्षों से चल रही है। बजट आवंटन होता है और हजमकर लिया जाता है। अकेले इंदौर में ही रुपए 50 करोड़ प्रति वर्ष, अं.यं., जानबूझकर व्यवस्थाएं बिगाड़ और सुधार के नाम पर भी पी जाते हैं। फिर टैंकरों से पानी आपूर्ति के बहाने डीजल हड़पने से लेकर पानी बेचने के खेल में भी रुपए 50 से 100 करोड़ की कमाई की जाती है, तो बाकी प्रदेश के निगमों नगर पालिकाओं, जनपदों, पंचायतों, गांवों का खेल भी हैडपंपों और टंकीयों पाइप लाइनों में होता ही है।

जल संसाधन रुपए 6775.65 करोड़- इस विभाग में भी भारी भ्रष्टाचार है। फिर अर्थशोषण मंत्री जयंत मलैया और प्र.स.रा.श. जुलानिया दिखनेभर के ईमानदार हैं। चारों तरफ भ्रष्टों की फौज बैठी है। यहां तक कि कुछ इंजिनियरों ने सहा.यं, का.यं. और अं.यं. पद पर अपनी जालसाजियों और भ्रष्टाचारों को दबाने 20-20 वर्ष पूरे कर लिए जैसे बागोरा जो सहा. यंत्री भी का.यं. और अब अ.य. बनकर खरगोन जिले में ही बैठा है। सूत्रों के अनुसार ऐसे यंत्री है जो सहा.यं. कार्यपालन यंत्री के साथ अधीक्षण यंत्री का भी पदभार एक ही स्थान पर बैठकर अपने पापों और भ्रष्टाचारों, जालसाजियों पर धन लूट कर और बांटकर कुंडली मारे बैठे है। जयंत मलैया बुंदेलीखंडी बनिया केवल भारी भ्रष्ट और जालसाज है वरन् भ्रष्टों को संरक्षण देने और पालने में लगा है। अपने बेटे बेटियों, बहुओं के नाम से देश विदेश में संपत्ति ऐसे ही तो नहीं आई, दोनों ही हजारों करोड़ की योजनाओं में विश्वास रखते हैं। 40 है. से कम के तालाब बनाते नहीं और 40 से 100-200 है. जमीन का मुआवजा संबंधित जिले की बाजार दर पर बांटना नहीं चाहते तो इंदौर जैसे जिले के लिए तालाबों और बांध बनाने की कोई योजना नहीं चाहे किसान और जनता पानी के अभाव में आत्महत्या ही क्यों न कर ले। जबकि इंदौर से प्रदेश को 50 प्रश से ज्यादा राजस्व की प्राप्ति पूरे प्रदेश को होती है। 40 से ज्यादा तालाबों की मंजूरी पिछले 10 वर्षों से इसलिए ही नहीं दी गई, इंदौर जिले को, क्योंकि ये रुपए 20 लाख प्रति है. का मुआवजा ही देना चाहते हैं। जबकि पंजीयन में स्टॉम्प ड्यूटी रुपए 2 से 5 करोड़ के आधार पर वसूलते हैं। फिर बड़ी योजनाओं में मोटी कमाई होती है। जिसका 40% हजम होता है।

ऊर्जा के लिए 19965.65 करोड़- शायद ये पूरा बजट हजम करने के लिए ही है। जबकि 15500 मेंवा बिजली का उत्पादन प्रदेश में हो ही रहा है। फिर 10 से 12 गुना बिजली की कीमत वसूली जाने के बाद पैसा कहां जा रहा है। विद्युत वितरण की तीनों, पारेषण और उत्पादन की दोनों कं. में बैठे गिद्ध धूर्तों इंडियन एव्यूसिंग सर्विस के अधिकारी हर वर्ष कं. की लूट-पाट फर्जी, बिलिंग, फर्जी रखरखाव के नाम पर ही हजारों करोड़ हजम कर रहे हैं। जबरदस्ती खंभे, लाइनें, मीटर जो कि स्तरहीन और घटिया होते हैं लगाए जा रहे हैं। निकला हुआ एल्यूमिनियम का तार जो हजारों करोड़ का था, खंभे बेचकर, बाले-बाले ही हजम कर दिए गए बदलें में नए कमजोर, खंभे, घटिया केवल लाइनें बिछाई गई। पुराने ट्रांसफार्मर ही मरम्मत करके लगा दिए जाते हैं और बिलिंग के नए की करके हजम कर लिए जाते हैं।

प्रदेश की जनता को रुपए 6.50 की ग्रामीणों को रुपए 5.50 की शहरीयों को व्यावसायिक रुपए 11 प्रति युनिट में बैचकर भी उस पर ऊर्जा कर, विद्युत शुल्क, ड्यूटी और शेष मिलाकर 20 प्रश से ज्यादा की ड्यूटी लगाई जाती है। 5 से 500 गुना ज्यादा के बिल बनवाये जाते हैं। बिल बनाने का ठेका लोकसभा की वक्ता सुमित्रा महाजन ने जालसाज सपूतों के पास है। जिन्हें प्रति बिल नहीं वरन बिल की राशि कमीशन देकर हर महीने करोड़ों का लाभ पहुंचाया जाता है। जनता से अनाप-शनाप बिलिंग कर लूटे जाते हैं। उद्योगपतियों को मोटे कमीशन पर लुटाई जाती है। फिर प्रदेश में न्यूनतम रुपए 5.50 की प्रति यूनिट की बिजली रुपए 2 से 2.50 प्रति यूनिट की राजस्थान, उत्तरप्रदेश, दिल्ली की प्रतिदिन 6000 से 8000 मेंवा बैचकर मुमं., ऊर्जा मंत्री, प्रदेश का प्रधान सचिव, सचिव हजम कर जाते हैं। तो फिर रुपए 20000 करोड़ ऊर्जा में धन क्यों आवंटित किया, जबकि केन्द्र सरकार भी हजारों करोड़ ग्रामीण विद्युतीकरण आदि के लिए देती है।

स्कूली शिक्षा रुपए 20939.54- शहरीय क्षेत्रों के 80 प्रश बच्चे ग्रामीण क्षेत्रों के 30 प्रश बच्चे निजी संस्थानों में पढ़ते हैं। सरकारी स्कूलों में 9वीं तक स्कूल मे बिना परीक्षण पास करके आगे बढ़ाने से 10वीं तक के सरकारी स्कूलों व निजी स्कूलों में भी भारी भरकम फीस खर्च में बाद भी न तो ढंग से हिंदी इंग्लिश पढ़ सकते हैं। बाकी गणित, विज्ञान में तो भगवान ही मालिक है। बेशक इस बजट का भी वेतन के अतिरिक्त 50 प्रश पैसा स्कूली प्रधानचार्यों, जिला शिक्षा अधिकारी से लेकर मंत्री सचिवों तक में हजम कर लिया जाता है।

लोक निर्माण विभाग रुपए 7124.58 करोड़- मप्र के बजट आवंटित यह राशि अनियोजित कार्यों यथा सड़क, भवन, पुल आदि की मरम्मत व रखरखाव कार्यों के लिए है। वैसे केन्द्रीय सड़क निधि, मंडी निधि, नाबार्ड व नियोजित कार्य या प्लान व अन्य योजनाओं में भरपूर पैसा मिलता है। अर्थात यह राशि 16-17 में लगभग रुपए 30000 करोड़ होगी जिसका रुपए 10000 करोड़ भ्रष्टाचार में हजम किया जाएगा, इस विभाग के भ्रष्टाचार के संबंध में समय माया के पाठक पिछले 17 वर्षों से लगातार पढ़ रहे हैं।

सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि मप्र सरकार ने 16-17 के बजट में जिस बजट आवंटन की विभागीय समंक श्रृंखला जारी की है, यथार्थ में तो उसका दिखावा और छलावा स्वयं वित्त शोषण मंत्री जयंत मलैया को नहीं मालूम होगा, इसके विपरीत ये मप्र सरकार का बजट जनता को यह प्रदर्शित करता है, कि जन-धन से लूटे गए करों का हम जनहित के नाम स्वहित में कैसे प्रयोग करेंगे ताकि बुद्धिजीवी वर्ग को मानसिक संतुष्टि दी जा सके, बेशक इस बजट में भी आय के रूप में खनिजों से प्राप्त आय जिसमें रायल्टी, छापेमारी से प्राप्त आय मंडी शुल्क आय, जबकि प्रतिदिन अकेले ऊर्जा में ही 5000-7000 मेवा विद्युत दूसरे प्रदेशों को बैची जाती हैं। इसकी रुपए 500 से 700 करोड़ की आय जबकि 1 मेवा में 10 लाख युनिट विद्युत होती है, जिसकी रुपए 6.50 प्रति युनिट के हिसाब से बैची जाती है। आखिर जन-धन से बने ये विद्युत मंडल की बनाई गई कं. क्या सरकार के बाप की जागीर है। आखिर उस पैसे को सस्ती बिजली बैचकर लाभ क्यों नहीं दिया जाता। ऊपर से रुपए 20000 करोड़ का आवंटन क्या जन हजम करने के लिए।

ऐसे सैकड़ों तथ्य है। जहां से लोकतांत्रिक सरकारें यथार्थ में लूटतांत्रिक बन हजारों करोड़ हजम कर जाती है। फिर पनामा लीक तो दुनिया के एक छोटेसे देश की कहानी है। मॉरीशस, थाइलैंड, मलाया, एशिया के साथ यूरोप के अफ्रीका के अनेकों देशों में इन हरामखोरों, जालसाजों का हजारों करोड़ रुपए जमा है, विदेशी सीधा निवेश कांड में भी भारत का ही पैसा लगवाया और उपयोग किया जा रहा है। विदेशी नामों और फर्मों से, इंवेस्टर मीट के पीछे का सच यही है। राजनेता, मंत्री, आईएएसआई, पीएस, आईएफएम, आईआरएस लाखों करोड़ ऐसे ही कमा कर एकडीआई, इंवेस्टर्स मीट के बहाने निवेशित करने के बहाने हैं।

बजट में दिए गए आवंटन में जिन विभागों के नाम हैं। उनमें केन्द्रीय योजनाएं में प्राप्त आवंटन व निधि का उल्लेख कहीं नहीं हो व जबकि अधिकांश विभागों में राज्य बजट के आवंटन से कई गुना ज्यादा धन केन्द्र से आता है, चाहे वह पशुपालन, उद्यानिकी, रेशम जैसे विभाग ही क्यों न हो जिनका 80-90 प्रश धन कागजों पर ही कार्य दिखाकर ही हजम कर लिया जाता है।

इतना सारी बजट की नौटंकी करने के बाद अनुपूरक बजट हर माह दो-माह में मंत्रियों की बैठक में गुपचुप तरीके से पास करवा, इतना पैसा जनता से लूटने के बाद भी अर्थशोषण मंत्री द्वारा बाजार से हजारों करोड़ का ऋण मंत्री राघव जी को सत्ता से षड़यंत्रपूर्वक इसलिए जेल भेजा गया क्योंकि वो मुख्यमंत्री की कुर्सी का प्रबल दावेदार बन गया था। जबकि उसके ही वित्त मंत्री बनते ही जयंत मलैया के कार्यकाल में यथार्थ में वित्त संकट सितंबर से ही शुरू हो जाता है। फिर वित्त मंत्री बनने के बाद अपनी दमोह की सीमेंट फैक्ट्री को फायदा पहुंचाने सीमेंट से वेट 12.5 प्रश से कम कर 5 प्रश किया और वह लाभ जनता को मिला ही नहीं और पूल बनाकर, प्रदेश में उत्पादित और प्रदेश के बाहर से आयातित सीमेंट का वेट कर मार्जिन का पैसा हजारों करोड़ प्रतिवर्ष कीमतें बढ़ाकर हड़प गया।

अस्तु विश्लेषण और व्याख्या कथा अनंता, बस पाठक, पत्रकारगण इतना समझ लें कि जन-धन का बजट, जन को भ्रमित कर स्वकमाई की व्यवस्था करना है।

साप्ताहिक समय माया

गरीबों की चिकित्सा के नाम लुटाया जा रहा निजी अस्पतालों को

पेज 12 का शेष

ऐसे ही एक कांड में डॉ. शरद पंडित के मुख्यमंत्री ने निलंबित कर दिया, उसके जवाब में महाधूर्त, मक्कार, भ्रष्टाचार शिरोमणि डॉ. शरद पंडित जो पिछले 20 वर्षों से इंदौर में कुंडली मारे बैठा है, जिसने वर्षों से स्टेथोस्कोप को हाथ नहीं लगाया, लगायेगा भी कैसे? उसे सरकारी पैसे में, कानूनों के नाम पर निजी चिकित्सालयों से, विभिन्न भ्रष्टाचार, जालसाजी के कांडों में वसूली से फुर्सत मिले तो नेत्र चिकित्सा का कार्य करें, इस सबके बाद में जीवन पर्यंत नेत्र चिकित्सा सेवा का जालसाजी के माध्यम से पुरस्कार खरीद लाया, इसकी बीबी डॉ. आशा पंडित भी भारी भ्रष्ट और जालसाज है, दोनों ही निजी चिकित्सा भत्ता लेने के बाद भी स्वयं का 74 नं. स्कीम में आशा नर्सिंग होम चलाते हैं, जिसमें सारे सरकारी कर्मचारी जिन्हें सरकारी वेतन मिलता है अपनी सेवायें देते हैं। सारी सामग्री, फर्नीचर, दवायें, पलंग, चादरें, मशीने सब सरकारी धन से खरीदी गई है। जिसे समयमाया 12 वर्ष पूर्व भी छाप चुका है। इस जालसाज ने कर्मचारियों की भविष्य निधि भी हड़प ली थी, जिस पर लोकायुक्त प्रकरण भी चला, इसके भ्रष्टाचारों, जालसाजियों के साथ चोइथराम का किडनी कांड, जैसे आठों जिलों में चल रहे सरकारी व निजी चिकित्सालयों में लूट, भ्रष्टाचार, जालसाजियों में फंसे डॉक्टरों को बचाने, प्रकरण में लीपापोती करने, सूचना के अधिकार में, अपील में जानकारी देने, में भी ये करोड़ों का सौदाकर हर वर्ष रुपए 200 करोड़ से ज्यादा हजम करता है, तो स्वाभाविक है मंत्री, मुख्यमंत्री, प्र.स., सचिव को भी करोड़ों रुपए में लुटाकर सारे कांडों के बाद भी वर्षों से कुंडली मारे बैठा है। यही कारण था कि डॉ. पोरवाल मु.चि.अ. इंदौर के विरूद्ध श्री अजमेरा की अपील दो माह से लंबित है। इंदौर के इस मु.चि.अ. ने भी राज्य, केंद्र शासन की अलग-अलग 20 से ज्यादा योजनाओं में मोटा धन हड़पने के साथ वह जिले में चल रहे 400 से ज्यादा नर्सिंग होम्स, चिकित्सालयों से भी मोटी वसूली करता है। के कारण न केवल शासन का योजनाओं से वरन् शासकीय चिकित्सालयों के डॉक्टरों द्वारा अधिकांश जांचे, यथा सोनोग्राफी, एक्स-रे से लेकर मल, मूत्र आदि की जांचों को भेजकर भी मोटा कमीशन में से भी यह कमीशन हड़पता है। शासकीय चिकित्सालयों में बैठे चिकित्सक का अपने पेशे से ज्यादा कमीशनखोरी में, विश्वास रहता है। जिस विश्वास से मरीज और उसके परिजन शासकीय चिकित्सालयों में ईमानदारी से इलाज की आस में जाते है। वहां डॉक्टरों से लेकर हर कर्मचारी वार्ड बाय तक शासकीय धन व चिकित्सालय सामग्री यथा औषधियां, चादरें, कंबल, पलंग जैसी सैकड़ों संपत्तियों में सेंध लगाने से लेकर मरीजों को लूटने, मरीजों के साथ आए महिला परिजनों के साथ छेड़खानी और अश्लील हरकतों तक बाज नहीं आते। जिसकी सैकड़ों खबरें आए दिन समाचार पत्रों में छपती रहती है। इन सबके विपरीत इन शासकीय चिकित्सकों से लेकर 90 प्रश तकनीकी कर्मचारी यथा पेथॉलाजी लैब के कर्मचारी यथा एक्स रे, सोनेग्राफी, रक्त, मल, मूत्र आदि की जांच करने वाले नर्सेज आदि तक अत्याधिक अनुभवी होने के कारण निजी चिकित्सालयों, वलीनिक्स, पैथो लेब में भी काम करता है। यहां तक कि 90 प्रश निजी चिकित्सालयों में ह्दय,किडनी, लीवर ट्रांसप्लांट जैसी बड़ी शय चिकित्सालयों में चिकित्साक ही अहम भूमिका निभाते है और मोटी कमाई करते हैं। फिर भी इन लालची गिद्धों का कभी पेट नहीं भरता।

एक जिले के मु. चि.स्वा. अधिकारी के पास 12 से 15 कार्यक्रमों में केन्द्र व राज्य सरकार का हजारों करोड़ की निधि आती है। जिसमें अंधत्व, टीवी, एड्स, मलेरिया, कुष्ठ आदि का अधिकांश पैसा कागजों पर ही खर्च कर हजम कर लिया जाता है। डीपीएस, आरसीएच और एनआरएचएम में केन्द्र से मिलने वाले धन का भी 90 प्रश कागजी जमा खर्च कर हजम कर लिया जाता है। जैसा कि मप्र सरकार के शिवराज मुमं ने अपनी उपलब्धियों में बताया कि वह रुपए 4.32 लाख करोड़ का धन प्रदेश की जनता के स्वास्थ्य पर खर्च करता है यदि सचमुच में इस धन का 50 प्रश भी ईमानदारी से खर्च किया जाता तो प्रदेश में एक भी निजी चिकित्सालय नहीं चल सकता,जबकि यथार्थ यह है कि शासकीय चिकित्सालयों में मात्र 30 प्रश गरीब, ग्रामीण मरीज ही जाते है। 70 प्रश मध्यम व उच्चवर्गीय निजी में इलाज करवाते है। इन तथ्यों के सारांश से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जन स्वास्थ्य के नाम पर जन धन का स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय से लेकर प्राथ. स्वा. केन्द्रों में कैसे सदुपयोग किया जा रहा है।

सूचना अधिकार में मंत्रालय से लेकर उज्जैन, देवास, इंदौर के मु.चि. व स्वा. अधिकारी से हाल ही में जानकारी मांगी गई थी, इन धूर्त मक्कारों जिसमें उज्जैन का सीएमओ कार्यालय के जालसाज हरामखोर तो कभी जवाब ही नहीं देता पिछले 5-6 वर्षों से इंदौर के डॉ. पोरवाल ने भी जवाब नहीं दिया, देवास के वर्तमान मु.चि.व स्वा. अधि. दीक्षित के आवेदानुसार जवाब न देकर जिसमें 4 बिंदु और उनके 4 कार्यकालों की जानकारी बिंदू और समयावधि अनुसार न दी जाकर बिना पन्ने गिने रुपए 10500 मांग लिए गए, यहां वर्षों से कुंडली मारे बैठा मीडिया प्रभारी सिसौदिया, रा.ग्रा.स्वा. मिशन में बैठी संविदा प्रबंधक परविंदर जो न केवल जालसाज है वरन् अरबों रुपए की इस निधि को मोटा हाथ साफ करने वाली ये जानती है कि यदि वास्तविक पैसे मांग गए जो कुछ ही सैकड़ों में होंगे पैसे जमाकर दस्तावेज लेकर, लोकायुक्त, आर्थिक अन्वेशषण ब्यूरो से लेकर न्यायालय में आपराधिक प्रकरण भी दर्ज करवाया जा सकता है। यदि सचमुच स्वा. मंत्रालय से लेकर मु.का.अ. से नीचे तक सब ईमानदार हैं, तो धारा 4 के 17 बिंदूओं की जानकारी जिसमें कुल धनराशि प्राप्ति व उसके व्यय की जानकारी 11 वर्षों से अभी तक स्वा. मंत्रालय की साइट पर धूर्त मु.मं. शिवराज, स्वा. मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा, प्र.स. सचिव से लेकर जिलों के मु.चि.अ. तक क्यों नहीं डाली जाती, क्योंकि सबके सामने जनधन की डकैती की पोल खुल जाने का डर है।

जिलों के सीएमओ बनाने से लेकर मासिक वसूली के आधार पर ही 31 जिलों में प्रभार पर सौंप रखा है। क्या कारण है कि डॉक्टरों का स्थाई सीएमओ पर पदोन्नत नहीं किया जा रहा वर्षों से, स्वाभाविक है, जब धन लेकर देकर ही सारे कार्य होने है। तो भ्रष्टाचार से मोटी कमाई करना आवश्यकता है। स्वास्थ्य के नाम पर जन धन से कैसे मु.मं., मंत्री प्रधान सचिव, सचिव, आयुक्त से लेकर डॉक्टरों, नर्सों, बाबुओं और वार्ड बॉय तक कैसे जन और जनधन से जैसे अपना स्वास्थ्य सुधार रही है, इससे पूरे प्रदेश के दैनिक समाचार पत्रों में छपने से समाचारों से स्पष्ट हो जाता है। 95 प्रश डॉक्टर्स वर्तमान में न तो मानव सेवा का पूर्ण ईमानदारी से धर्म निभाते हैं। न वो पेशे के प्रति, न तो स्वयं के प्रति ईमानदार है। मरीज इनके लिए कमाई के साधन है। स्वास्थ्य के नाम जन-धन में डकैती गलकर हजम करना इनका शगल है।

मप्र वाणिज्यकर घटता स्टॉफ बढ़ता काम का बोझ

अनुभवहीन व भ्रष्ट अधिकारी पहुंचा रहे हजारों करोड़ की क्षति शासन को...

भ्रष्ट मंत्री, प्र.स., सचिव सबको वसूली चाहिए, राजस्व हानि गई भाड़ में

मप्र के वाणिज्यकर विभाग में चारों तरफ मप्र के हर जिले में हर वृत्तों में दिनों दिन बाबुओं से लेकर हर स्तर के अधिकारियों तक का स्टाफ समय पर के कारण व लगातार सेवानिवृत्ति, ऐच्छिक सेवानिवृत्तियां लेने, मृत्यु आदि के कारण जरूरत का भी 60 प्रश से कम हो गया हैं। दूसरी तरफ कम्प्यूटराइजेशन हो जाने से कुछ काम हल्का हुआ तो कुछ कई गुना ज्यादा हुआ, साथ ही पंजीकृत व्यवसाइयों की संख्या भी 90 की तुलना में 3 गुना ज्यादा हो गई, जिससे कर्मचारी व अधिकारी मानसिक व शारीरिक स्तर पर बीमार रहने लगे, इसका सीधा असर कार्यक्षमताओं पर पड़ने से और दूसरी और प्रदेश के इंदौर के बड़े-बड़े वृत्तों जिसमें 8,9,10,11,12,13,14 आदि वृत्त है। नए और अनुभव व ज्ञानहीन सन् 2005 के बाद भर्ती हुए अधिकारियों के हाथों में सौंपने से भ्रष्टाचार के चलते यथार्थ में भारी राजस्व की हानि हो रही है। कर सलाहकार आसानी से इन अनुभवहीन और तकनीकी कानूनी दांव-पेंचों में उलझाकर व थोड़ा सा आर्थिक सहयोग का लालच देकर राजस्व को भारी क्षति पहुंचा रहे हैं। महिला अधिकारियों का तो हाल ये है कि 11.30 बजे से 12 बजे के बीच आती है। 4.30 बजे से 5 तक अपने हिस्से के कार्यों को यहां वहां छोटे अधिकारी और कर्मचारी पर डालकर खिसक लेती है।

स्वाभाविक है शासन के राजस्व की हानि होगी, वृत्त 11 की सुश्री रूबी रघुवंशी जिसके पास प्रदेश के बड़ी कं.के खाते हैं ने एक बड़ी कं. प्राक्टर गैबल से भर से मोटी वसूली कर ली जबकि सैकड़ों ऐसे बड़े करदाताओं जो संयुक्त उपक्रम की बड़ी कंपनी है हजारों करोड़ रुपए का राजस्व वर्षों से अटका है। उनमें मोटी वसूली कर क्यों चुप हैं। यही हाल 10 व 13 का भी है। सूचना के अधिकार में जानकारी मांगने पर जालसाज की ये फौज अपने भ्रष्टाचारों, अज्ञानता, अनुभवहीनता के साथ जालसाजियां छुपाने के लिए मांगे दस्तावेजों की बिना गिनती किए भारी मोटी राशि बिना बिंदुवार और समयावधि बार आवेदन के अनुसार शुल्क का वितरण, मांग करते है। इसमें वृत्त 9 का सहा. आयुक्त दीपक श्रीवास्तव, 10 की श्रीमती विनीता बैस, 13 की श्रीमती चौरसिया है। 13 में तो निःशुल्क जानकारी देने का आदेश देने के बाद भी भ्रष्ट और जालसाजों ने अभी तक जानकारी नहीं दी है। पूरे वाणिज्यकर विभाग में, पदस्थापना व पदोन्नतियां, नाकों पर एंटी इवेजन ब्यूरो आदि केवल धन के दम पर होती है। यहां अधिकारी की कार्यक्षमता, लगन, और ईमानदारी अच्छी पदस्थापना का पात्र नहीं वरन् कौन कितना चापलूस, भ्रष्ट और बदले में कितना धन खर्च करने में सक्षम है। यही कारण है कि एंटी इवेजन ए में सहा. आयुक्त पिछले 7-8 साल से, वा.क.अ. की नियुक्ति 1 फरवरी 16 से अभी तक नहीं की गई है। क्योंकि एक तरफ उस पद को पाने के लिए मोटा धन खर्च नहीं करना, चाहता तो दूसरी और दोनों पदों का हिस्सा भी उपायुक्त, अपर आयुक्त, आयुक्त से लेकर मंत्री तक पहुंच रहा है।

फिर जब वा.क.अ. और सहा. आयुक्त की आवश्यकता होती है, तो संबंधित वृत्त के सहा. आयुक्त, कराधिकारी को बुलाकर छापों, जब्ती आदि की कार्रवाई को संपन्न करवाने में एंटी इवेजन ब्यूरो के अधिकारियों जो नियमित रूप से परस्थ है, सबसे ज्यादा आनंद प्राप्त होता है क्योंकि उसे केवल रबर स्टॉम्प की तरह हस्ताक्षर और औपचारिकताएं पूर्ण करने में उपयोग किया जाता है। उसे उसके बदले 1-2 प्रश का हिस्सा देकर वापिस भेज दिया जाता है। जबकि नियमित सहा. आयुक्त व कराधिकारी 15 से 25 प्रश हिस्सा तक हथियाते है।

फिर 95 प्रश लंबे मार्गों और अंतरराज्य बसों जो लगभग 2000 से ज्यादा है। 400 ट्रांसपोर्टर्स जो पूरे देश में माल लाते ले जाते हैं। उन सबसे मिलने वाली महीना वसूली में भी ये तात्कालिक बुलाए गए सहा. आयुक्तों व कराधिकारियों को महीना नहीं देना पड़ता। इसलिए ये सौदा कहीं से भी महंगा नहीं पड़ता।

वर्तमान में भोपाल में बैठा महाधूर्त और जालसाज उपायुक्त ओपी पांडेय जो भोपाल एंटी इवेजन संभाल रहा है। पूरे प्रदेश के अधिकारी और कर्मचारियों की पदस्थापना नाकों, बड़ी कमाई वाले वृत्तों, एंटी इवेजन ब्यूरो आदि में मंत्री जयंत मलैया, प्र.स. मनोज श्रीवास्तव, सचिव और आयुक्त के बीच दलाली और सेटिंग कार्य कर रहा है। स्वाभाविक है, चापलूसों, भ्रष्टों को अपनी मोटी कमाई से मतलब है, शासन की क्षति से मंत्री, संत्री से लेकर नीचे तक किसी को मतलब नहीं।

स्वच्छंदता और आधुनिकता से युवा पीढ़ी में बढ़ता बांझपन

पेज 12 का शेष

युवा पीढ़ी में नपुंसकता और बांझपन के चलते न केवल बहुराष्ट्रीय दवा कंपनियों से लेकर चौराहे-चौराहे पर खुली बच्चा पैदा करवाने के लिए टेस्ट ट्यूब बेबी, सरोगेट मदर, इंफर्टीलिटी सेंटरों की बहुत उचटकर लगी है। जिनके यहां 25-30 वर्ष के युवा जोड़ों से लेकर 45-50 वर्ष के बच्चे पैदा करने वाले जोड़ों की भीड़ लगी रहती है। ये एक-एक जोड़े से रुपए 5 लाख तक का सौदा कर सीधे ही किसी भी युवा का वीर्य और स्त्री के अंडाणु लेकर परख नली में इकट्ठा कर स्त्री के गर्भाशय में प्रविष्टकरवा कर जिस स्त्री का गर्भाशय कार्यशील है, पर अंडाणुओं के बनने की प्रक्रिया धीमी या समाप्त हो चुकी है। बच्चा पैदा करवा रहे है। पर ऐसे भी प्रकरण सामने आए है जिसमें जोड़ों ने लाखों रुपए बर्बाद भर कर दिए और वर्षों बाद भी चक्कर लगा रहे हैं। और परिणाम शून्य रहे हैं। अकेले इंदौर में ही ऐसे 10 से ज्यादा केन्द्र खुल चुके हैं। भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर में भी ऐसे ठगोरे डॉक्टरों और क्लीनिकों की कमी नहीं है। जबकि पूरे देश में ऐसे कम से कम 5000 से ज्यादा क्लीनिक काम कर हरे हैं। कुछ समय समाचार पत्रों में एक समाचार बड़े शीर्षक के साथ छपा था कि ऐसे बांझ दंपत्ति ब्राह्मणों के वीर्य की ज्यादा मांग करते है बच्चे पैदा करने के लिए, इस पर भारत में विकी डोनर नाम की फिल्म भी बन चुकी है।

फिर सरोगेट मदर का व्यवसाय भी भारत में वर्तमान में खूब फल-फूल रहा है। अर्थात इन हरामखोर जालसाज कं. के पेक्ड फूड ने पूरे विश्व में नपुसंकता और बांझपन की आधुनिकता भी फैलाई है। जो गंभीरता की इंगित करता है। अभी भी वक्त है संभलने के लिए कि हम प्राकृतिक रूप से प्रकृति के निकट रहकर अपने जीवन में भी शुद्धता लायें। आधुनिकता कैसा अभिशाप बन रही है। इसको गंभीरता से समझें, हमारे प्राचीन ऋषि-मुनियों ने हमारे लिए बहुत सी धरोहर छोड़ी है। उसे अपनाएं। स्वच्छंद यौनाचार की अपेक्षा शीघ्र विवाह हों युवा पीढ़ी के 30-35 वर्ष की उम्र तक पहुंचते जीवन नीरस, मस्तिष्क कुंठित और शरीर निस्तेज होने लगता है। अत्याधिक शिक्षा अच्छी मोटी कमाई, ऐश्वर्य पूर्ण जीवन की लालसा आखिर किसके लिए जब घर में बच्चे ही न हों, आखिर ऐसी महत्वकांक्षाएं पूर्ण करते-करते जिंदगी समाप्त होने के कगार पर आ जाए या पुरुषों में नपुंसकता और स्त्रियों में बांझपन आ जाए, फिर शादी भी कर लें, तो स्त्रियों को गर्भित करने के लिए शुक्राणुयुक्त वीर्य खरीदना पड़ जाए, या गर्भ निरोधक गोलियों का उपयोग करते-करते सदा के लिए गर्भ निरोधित हो जाए और घर में किलकारी सुनने के लिए कोख और वीर्य किराए पर लेकर, खरीदकर बच्चे पैदा किए जाए, सबकुछ होने के बाद भी यह दुख जीवनभर सताता रहे कि न जाने किसके वीर्य से पैदा हुआ बच्चा हम पाल रहे है। आखिर क्यों नशैला जीवन, स्वच्छंद यौनाचार का कैसा आधुनिक जीवन जी रहे है। हमारे युवा, माता-पिता, दादा-दादी, नाना-नानी के अतिरिक्त कौन युवाओं के सिर पर हाथ रखकर पूछेगा और समझाएगा।

बैंकें बन चुकी है घोर जालसाजियों और भ्रष्टाचार का अड्डा

पेज 12 का शेष

ताकि उन पर आंच न आए, क्योंकि ऐसे ऋणों जो शासकीय योजनान्तर्गत दिए जाने से हर बैंक और उसकी शाखा को लक्ष्य पूरा करने की व्यवस्था में कुछ विक्शतायें तो समझ में आती है। परंतु वहां पर भी कमीशनखोरी का बोलबाला है। न केवल कमीशनखोरी वरन महिलाओं को ऋण देने में खुलकर यौन शोषण भी किया जाता है। श्री अजमेरा स्वयं बैंक आफ इंडिया की बलड़ी, हरसूद, जबलपुर की मदन, महल, जबलपुर मुख्य शाखा में पदस्थ रहे उन्होंने देखा किए शासकीय योजनाओं के 1980 से लेकर अभी तक हर बैंक का अधिकारी महिला हितग्राहियों का बिना यौन शोषण किए ऋण वितरण में कैसे अड़ंगा लगाकर इच्छापूर्ति तक कैसे परेशान करता था। स्वाभाविक ऐसा सारा ऋण डूबना ही था छोटे ऋणों में तो बैंक अधिकारी, राजस्व के तहसीलदारों के कमीशन बांटकर

ऋण वसूली में सख्ती दिखाते है। इसके विपरीत बड़े ऋणों में बैंकों के अग्रिम ऋण अधिकारी से लेकर शाखा प्रबंधक, वरिष्ठ प्रबंधक, क्षेत्रीय आंचलिक और मुख्य प्रबंधक तक सब कमीशन खोरी कर फर्जी स्टॉक, संपत्ति मूल्यांकनों, लाभ-हानि, चिट्ठों आदि और फर्जी ऋण लौटाने आदि की क्षमताओं के आधार पर जो कि करप्ट अकाउंटेंट द्वारा बनाई जाती है। बैंक अधिकारी सुरा सुंदरी और कमीशन का भोग और सेवन कर आंख भींचकर बड़े-बड़े करोड़पतियों और अरबपतियों को नगद साख, कार्यवाही पूंजी, समान मूल्य संपत्ति रहन के रहने के लिए प्लॉट, मशीनरी, औद्योगिक भूमि की बाजार मूल्य के आधार पर ऋण वितरण कर देते है। जो बाद में संदिग्ध और अशोध्य में परिवर्तित हो जाता है।

मलैया की जिस किंग फिशर एयर लाइंस के रुपए 9000 करोड़ का ऋण की चर्चा भारतीय समाचार पत्रों में और दृष्य चलित समाचार श्रृंखलाओं में पिछले कई महीनों से अनवरत चल रही है। उसके पीछे का यथार्थ यह है कि बैंकों के धन और सुरा-सुंदरी लोलुप अधिकारियों ने मलैया के सारे जहाज जो कि विदेशी कं. के उपयोग करने के बाद समयबाधित हो कबाड़ अवस्था में खड़े थे। संचालन योग्य बनाकर बैंक ऋण चौगुनी कीमत दिखाकर खरीदे गए थे, कमाई के चौगुने आंकड़े, चूंकि समयबाधित कबाड़ विमानों में रखरखाव उड़ान योग्य बनाए रखने के लिए दोगुना लगता है, को सामान्य दिखाया गया, फिर ईंधन, भू-स्पर्श, उड़ान का नियमित खर्च अत्याधिक होने के साथ ही व्योम बालाएं, स्टॉफ विमान चालाकों आदि का वेतन भत्तों के खर्चों से जो बैंक खातों में 25 से 40 प्रश कम दिखाए ताकि लाभ अधिक दिखाकर बैंक किश्ते लौटाने का फर्जी व्यावसायिक संचालन पत्र बनाकर करप्ट अकाउंटेंट से प्रमाणित कर पेश किया जाकर जिन अधिकारियों ने ऋण वितरण अनुमति दी थी। आखिर वे भी तो उतने ही दोषी थे जितना विजय माल्या, यदि हर ऐसे करोड़ों के अशोध्य और संदिग्ध ऋणों की वास्तविकता की जांच की जाए तो 70 प्रश बैंक अधिकारी भादस की धारा 119, 120 बी, 420, 216, 217 में कारागृहों में निवास योग्य है। वो तो अच्छा था कि विजय माल्या था, मुझ जैसा तो न केवल बैंकों का अरबों रुपए का ऋण भी हजम करता और बैंके के अनेकों अधिकारियों को उनके यथार्थ और कानूनी जाल में फंसा कर जेल भी पहुंचाता। बदले में बैंकों की संपत्ति रहन के बदले समय बाधित विमानों का कबाड़ा जिसे बैंक बैचकर 10 प्रश पैसा भी वसूल नहीं कर सकते थे। रहन में सौंप देता, वसूली। विजय माल्या तो बहुत छोटा खिलाड़ी था। 90 प्रश बैंक में भारत में कार्यरत विदेशी कं. जिसमें इंडियन टोबेको, हिंदुस्तान लीवर, केडबरीज, पारले जैसी सैकड़ों हजारों-करोड़ों का ऋण लेकर प्लांट, मशीनरी, स्टॉक, उद्योग भवन और भूमि पर सममूल्य रहन ऋण, नगद साख, बैंक गारंटी चलपूंजी, बैंकों से लेकर व्यापार करती है। हमारा पानी, खाद्य वस्तुएं हमारे देश से लेकर हमारे देश में बेंचकर हमारा हजारों करोड़ का लाभ कमाकर ले जाती है। बदले में सरकार एक्साइज ड्यूटी, विक्रय कर, आयकर में ही खुश हो जाती है। यथार्थ में सीधा विदेशी निवेश केवल इन हरामखोर सरकारों के वित्त मंत्री, कृषि मंत्री, उद्योग मंत्री आदि को मोटा कमीशन हजम करने का जरिया होता है। जबकि वास्तविक क्रियाशील पूंजी बैंकों में जमा जन-धन ही होता है। दूसरी तरफ माल्या से कई गुना ज्यादा लगभग रुपए डेढ़ लाख करोड़ अंबानी बंधुओं ने सवा लाख करोड़ से ज्यादा टाटा ने रुपए 80000 करोड़, अडानी ने रुपए 1,15000 करोड़ जेपी ग्रुप ने भी ले रखा है। जबकि ये सारे आंकड़े फर्जी है। या केवल एक उद्योग को दिए गए किसी एक प्रकार के ऋण के हैं। जबकि बिरला समूह की कंपनियों में जो 400 से ज्यादा हैं।

टाटा के पास भी एक ट्रक-कार बनाने से लेकर स्टील बनाने कपड़ा, चाय आदि की 500 से ज्यादा कंपनियां हैं। अंबानी के पास भी 200 से ज्यादा कंपनियां रुपए डेढ़ लाख करोड़ तो उसकी जामनगर रिफायनरी में जो एक लाख 20 हजार से डेढ़ लाख बैरल तेल उत्पादन करती है। अर्थात इतना पैसा तो उसका स्टॉफ और रेलवे यार्ड में ही बैंक ऋण का लगा होगा, तो वास्तविकता में कितना ऋण उसने हर कं. के लिए बैंकों से लिया होगा।

प्रश्न यहां यह भी है कि जब रिजर्व बैंक से लेकर हर सरकारी, सहकारी निजी और विदेशी बैंकर्स जन-धन का उपयोग जन के लिए करते हैं तो सूचना के अधिकार में जानकारी देने से मना कैसे कर सकते हैं। जानकारी न देने के पीछे उनके अपने कुकर्मों का यथार्थ सामने आने का डर ज्यादा होता है। भारत की हर बैंक में बैठा 90 प्रश कर्मचारी अधिकारी न केवन भ्रष्ट, जालसाज वरन घोर बत्तमीज भी है जिसमें सबसे ज्यादा स्टेट बैंक की शिकायतें होती हैं। जिसमें जमा किए चैकों का पैसा हजम कर जाना, खातों से पैसा निकालना एटीएम, क्रेडिट कार्ड से जालसाजियां करना, शिकायत करने पर शिकायत दूर करने, ग्राहकों के धन लौटाने की अपेक्षा ये हरामखोर जालसाज ग्राहकों से मारापीटी करना, जिसकी शिकायत रिजर्व बैंक के राज्यों की राजधानी में बैठाए गए लोकायुक्त भी नहीं सुनते, उनके पोर्टल पर स्पष्ट लिखा है कि ग्राहकों के साथ की गई बत्तमीजी और मारापीट की शिकायतें द.र्ज नहीं होगी आखिर जिस आम आदमी की बचतों से इन हरामखोर जालसाजों को वेतन मिलता है, बैंकें चलती है, उसके धन के साथ लूट-खसोंट, जालसाजियों से धन हजम करने और शिकायत करने पर वहां बैठे शूकरों की फौज उस ग्राहक के साथ मारापीटी नोंच खसोट करे उसकी शिकायत न पुलिस लेती है, क्योंकि वहां बैठे गिद्ध थोड़ा सा टुकड़ा डालकर उन्हें भी खरीद लेते हैं। तो कहां जाएगा आम आदमी इसके विपरीत वो रक्त पिपासु दानव मोदी और उसका वित्त मंत्री देश के हर व्यक्ति के साथ तीन वर्ष के स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे का भी खाता खोलने के लिए विवश कर रहे है, अन्यथा स्कूल वाले उन्हें कक्ष में प्रवेश नहीं करने देते है। चाहे गरीब माता-पिता के साथ दो वक्त की रोटी की व्यवस्था हो न हो पर रुपए 500-1000 से खाता अवश्य खुलवाओ, अन्यथा हर स्कूल माता-पिता और पालकों को भारी प्रताड़ना देता है। बेशक बैंकों की 50000 से ज्यादा शाखाओं और कार्यालयों में लगभग 10 लाख से ज्यादा कर्मियों की तत्काल जरूरत है।

सरकार विश्व व्यापार संगठन बनाम विश्व व्यवसायिक आतंकी संगठन की गुलाम है और वह सभी सरकारी बैंकों को निजी देशी विदेशी पूंजीपतियों को विनिवेश राग के अंतर्गत बैचकर लाखों करोड़ रुपए इकट्ठा कर हजम करना चाहती है। इन वित्तीय संस्थानों को बैच देश और देश की जनता को पुनः गुलाम बनाने में अग्रसर हैं। वो तो बैंकों के श्रमिक संघ इसका विरोध न करते तो विनिवेश राग में अभी तक सभी सरकारी बैंक निजी क्षेत्रों में जा चुके होते।

केंद्र व राज्य सरकारें यथार्थ की प्रस्तुति से भयाक्रांत

समयमाया.कॉम की साइट मूल हिस्सा उड़ा, सच छुपाने की कोशिश

समय माया की साइट, वाट्सएप, संदेशों पर सतत निगाहें, भेजने से पूर्व ही संदेशे हो जाते हैं गायब या गंतव्य तक नहीं पहुंचते। सरकार आइने फोड़ने से बदसूरती, भ्रष्टाचार समाप्त नहीं हो जाता, शुतुरमुर्ग की तरह गर्दन रेत में घुसड़ने से तुफान नहीं रूक जाते, झूठे वादे कर चुनाव जीतना, जन-धन, जन संपत्तियों को अपने बाप की जागीर समझ पूंजीपतियों यथा अंबानी, अडानी, टाटा जैसे सफेदपोश डकैतों को सौंपना और स्वयं भी दुरुपयोग करना जैसे मोदी न अपनी विदेश यात्राओं में रुपए 40000 लाख करोड़ से ज्यादा जनता के बर्बाद किए आदि का यथार्थ पढ़कर साइट हेंक करने से, यथार्थ, आभास में नहीं बदल जाएगा।

सरकारें चाहे वो केंद्र की हो या राज्य सरकारें उनके मंत्री, उनके महामंत्री धूर्त इंडियन एव्यूसिंग सर्विस के सबसे बड़े डकैत, जालसाज, अधिकारी जो राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री के सचिवालयों से लेकर, मुख्यमंत्रियों के सचिवालयों में, संभागों, जिलों के, आयुक्तों से लेकर जिलाधीश तक सब उच्च पदों पर, इन्हीं की नियुक्तियां और बोलबाला रहता है। यथार्थ में भारत की सत्ता को चलाते हैं। इनके सामने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्रियों, सांसदों, विधायकों, महापौरों की जो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि होते है। कोई बख्त नहीं, ये सब कठपुतलियां है, जिनको नचाने के सूत्रधार यही है। ये सफेदपोश कानूनी डकैत है, जो कानूनों की आड़ में, राष्ट्र की जनता और राष्ट्र के संसाधनों का स्वहित में सबसे ज्यादा दुरुपयोग करते हैं। जिनके विरूद्ध समयमाया समाचार पत्र और इसकी साइट समयमाया डॉट कॉम से सबसे संक्षिप्त, सटीक, यथार्थ से अपने सम्मानीय पाठकों को पिछले 17 वर्षों से अंतर्गत करवा रहे है। समय माया डॉट कॉम व समाचार पत्र अपनी आर्थिक स्थिति और साधनों के घोर अभावों के विपरीत विश्व के, राष्ट्र की जनता के कल्याणकारी समृद्ध-सुखद भविष्य की जंग लड़ रहा है। स्वाभाविक है, धूर्त मक्कार, सत्ताधीशों, मंत्रियों, राजसुखभोगी सफेदपोश अधिकारियों, रक्त पिपासु दानव पूंजीपतियों को ये कभी हजम नहीं होता और किसी न किसी बहाने साइट हेक करवाई जाती रहती है। जो कि सिद्ध करती है कि इन धूर्त सत्ताधीशों को यथार्थ की प्रस्तुतियों से भारी डर लगता है, इसलिए सबसे आसान तरीका है कि साइट को ही उड़ा दिया जाये। समयमाया का फेसबुक से भी फर. 14 से मोदी और भाजपा के यथार्थ की प्रस्तुति को भी कभी भी फेसबुक के मुख्य समाचारों पर नहीं चलने दिया गया, समाचार पत्रों के जेपीजी फोटो को भी नहीं चढ़ाने दिया गया, जबकि जो समाचार पत्रों में मोदी के बारे में लिखा गया था, वर्तमान में उसकी भविष्य परख प्रस्तुति कटुसत्य बनकर सामने आ चुकी है। बेशक मोदी ने पूंजीपतियों से चंदा वसूल कर फेसबुक के जुकरबुर्ग को चुनाव से पूर्व ही लगभग 50 लाख अमेरिकी डॉलर देकर खरीद केवल अपनी प्रशंसा जिसे मोदी के धूर्त प्रशंसक जिसमें सबसे बड़ा भांड था। अरूण गर्ग जो बनिए के कुल में पैदा होकर भी धन की खातिर मोदी की झूठी रामायण पाठ का लगातार 4 माह तक करोड़ों खातों में वाचन करता रहा। फेसबुक के जुबरबुर्ग जो मानसिक रूप से दुनिया के मुस्लिम आतंकवादियों का न केवल हमदर्द है वरन् करोड़ों मुस्लिमों को गैर मुस्लिम लड़कियों को फेसबुक के माध्यम से न केवल भारत वरन् , कनाडा, फ्रांस, अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, जापान, रूस जैसे राष्ट्रों में भी फंसानें में मदद करता रहा है। फिर मोदी के चुनाव प्रचार में 50 लाख अमेरिकी डॉलर जो रुपए 65 प्रति डॉलर के मान से 65×50 (3250 करोड़) रुपए की रकम पाकर तो निहाल हो उठा, स्वाभाविक था, कि समयमाया के मोदी के विरूद्ध कथनों, लेखन को अपनी फेसबुक पर कैसे प्रस्तुत करता। उसके वहीं रोक दिया जाता था, बेशक हर मोदी के विरोध में लिखे यथार्थ को रोकने प्रकाशित न करने के बदले में भी 1000-2000 अमेरिकी डॉलर वसूलता ही होगा फेसबुक। यही ट्वीटर का भी था कि उस पर भी फर-14 से दो लाइन की मोदी के विरूद्ध टिप्पणी को वह भी सैकड़ों और मिनटों की तो छोड़िए घंटों तक प्रकाशित किये जाने योग्य न समझकर कभी फीड नहीं होने दी, जबकि यह स्थिति देख और समझ अप्रेल-मई-2014 से इन खातों पर अपनी टिप्पणियां डालना ही बंद कर दी गई। अब यही हाल वाट्सएप का भी है, इसमें भी सरकार विरोधी समाचारों, टिप्पणियां को अब मप्र सरकार ही उड़वा देती है। जिसका प्यारा सा उदाहरण देखिये, 9 नवम्बर 15 की दीपावली के चलते अधिकांश कार्यालय खाली पड़े थे। जब एक दो कार्यालयों को 10 नवम्बर 15 को कार्यालयों के दरवाजों पर पड़े तालों की फोटो उतार चिपकाकर उस पर टिप्पणी डाली गई हो। वह फोटो पहले एक समूह में टिप्पणी के साथ अपने मोबाइल पर जाना तो दिखा दिया गया परंतु वह संदेश आगे ही नहीं बढ़ने दिया गया। दूसरे समूह के प्रेषण में फोटो तो जाना दिखा दिया गया परंतु टिप्पणी गायब थी, अब मजेदार बात देखिये कि 16 नवम्बर 15 को वह टिप्पणी अपने आप लौट आई परंतु वह संदेश नहीं पहुंचा। सभी समूहों में, चूंकि वह टिप्पणी मप्र राज्य की थी, जिसमें दीपावली के 11 नवंबर 15 के अवकाश पर पूरे प्रदेश के चार लाख में से 3 लाख सरकारी कर्मचारियों अधिकारियों ने 4 दिन अवकाश मनाया। ऐसे अनेकों समाचारों को जो कि सरकार विरोधी और जनहितैषी होने के बाद भी रोके जाते है। इसके विपरीत अश्लील समाचारों और फोटों को जो पूर्णतः औचित्यहीन और गैरकानूनी होने के बाद भी यातायात व विनिमय धडल्ले से चलता रहा है। अर्थात समयमाया की साइट, फेसबुक, ट्वीटर, वाट्सएप पर तो सरकारी शकूरों की सतत निगाह होती है, जबकि वो पूर्णतः राष्ट्रहित में होते हैं। 8 दिस. 15 को पूरे देश में हिंदु महासभा के कार्यकारी अध्यक्ष कमलेश तिवारी के विरूद्ध प्रदर्शन की तैयारी 1 दिस से ही शुरू हो गई थी, जिसे इंदौर के हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं द्वारा सप्रमाण 3 दिसम्बर से ही लगातार पुलिस व प्रशासन को प्रस्तुत किया जा रहा था। तब प्रशासन और पुलिस के उच्चाधिकारी उल्टे ही उचित व त्वरित कार्रवाई करने की अपेक्षा हिंदू कार्यकर्ताओं को ही परेशान करने में लगे थे, जब 8 दिसम्बर 15 का प्रदर्शन हो गया, तोड़-फोड़ कर दी गई। 8 दिसम्बर 15 को जानबूझकर भी प्रस्तुत नहीं कर सका, नहीं मिट्ठू मियां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह और उनका वह गृहमंत्री बाबूलाल गौर ने इसे केवल इंदौर,भोपाल व अन्य शहरों के हरामखोर जालसाज जिलाधीशों, आयुक्तों, पुलिस अधीक्षकों पर महीनेभर बाद भी कोई कार्यवाही नहीं की। जब समाचार पत्रों और प्रसार माध्यमों में पुलिस प्रशासन की धज्जियां बिखेरनी शुरू कर दी। प्रदर्शनकारियों, तोड़फोड़ करने वालों पर कार्रवाई की मांग के लिए हिंदू महासभा मात्र 200 कार्यकर्ता पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे। बाकी सारी राजनैतिक पार्टियां तथा कांग्रेस व भाजपा गायब थी।

साप्ताहिक समय माया

बहुराष्ट्रीय कंपनियों के विषैले रसायन युक्त पैक्ड फूड के परिणाम

स्वच्छंदता और आधुनिकता से युवा पीढ़ी में बढ़ता बांझपन

सत्ताधीशों का लालच करेगा भविष्य की पीढ़ी बर्बाद

भारत में, भारतीय संस्कृति के मूल्यों के ह्रास के परिणाम अब सामने आने लगे हैं। प्रसार माध्यमों यथा टीवी, इंटरनेट,मोबाइल, जैसे आधुनिक साधनों ने भौतिकवादी आधुनिकता का भ्रम पैदा किया है, जिसमें हमारी वर्तमान युवा पीढ़ी अपने आपको भारी धन्य समझ जिस नग्नता, स्वच्छंद यौनाचार की दीवानी हो रही है उसके दुष्परिणामों में युवा पुरुषो के वीर्य में घट रही शुक्राणुओं की संख्या और युवा महिलाओं में घटती अंडाणुओं की संख्या के कारण बांछपन बढ़ रहा है। महिलाओं में बांछपन के कुछ महत्वपूर्ण कारण यह मुख्य रूप से जो सामने आया कि छात्राएं अपनी शिक्षा काल में अपने सहपाठियों, प्रेमियों से खुलकर स्वच्छंद यौनाचार करती है। इस बहाने वो न केवल आधुनिक होने का प्रदर्शन करती है और सुरक्षा की दृष्टि से जो गर्भ निरोधक बाजार में मिलने वाली सैकड़ों गोलियां जिनका प्रचार-प्रसार टीवी पर स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार से लेकर राज्य सरकारें भी भरपूर करती है। जिसमें माला डी के साथ कंपनियां भी अपने गर्भ निरोधक औषधियों का गैरकानूनी रूप से प्रचार-प्रसार करती है। स्वाभाविक कि युवा छात्राएं और महिलाएं इनका खुलकर प्रयोग कर रही है। हालात ये है उच्च शिक्षा में अध्ययनरत सहशिक्षा में 10 में से 8 युवतियों के कहीं न कहीं शारीरिक संबंध स्थापित किए और सुरक्षा की दृष्टि से सभी प्रकार के गर्भ निरोधकों जिनमें कंडोम से लेकर निगलने वाली गोलियां भी 10 में से 5 महिलाएं नियमित रूप से सेवन कर रही थी यह हालात भारत के छोटे शहरों के हैं। बड़े महानगरों में स्थिति और भी गंभीर है। माता-पिता अपने में व्यस्त और मस्त हैं। उनके युवा पुत्र-पुत्रियां यदि भविष्य के प्रति सचेत है तो वे भी पढ़ाई, दोस्तों और सहेलियों में व्यस्त है। नशा, किसी न किसी प्रकार का साथ ही आधुनिकता के झूठे दिखावे और स्वच्छंद यौनाचार में प्यार की आड़ में दोस्ती की आड़ में सब चल रहा है। यदि माता-पिता दोनों ही नौकरियों में है तो पुत्र-पुत्रियां माता-पिता की ओर माता-पिता पुत्र-पुत्रियों की और महीनों तक शक्ल नहीं देख पाते हैं। स्वाभाविक है कि उनके पीछे उनके ही आशियाने में क्या रंग रैलियां, नशाखोरी चल रही है, एहसास भी नहीं हो पाता है। नशीली दवाएं, गर्भनिरोधक गोलियां, महिलाओं की शादी से पहले ही बांझ बना रही है। क्योंकि नियमित रूप से गर्भनिरोधक गोलियां लेने से स्त्रियों के अंडाणु धीरे-धीरे बनना और गर्भाशय का मुंह सदा के लिए बंद हो जाता ही जाता है दूसरी तरफ युवा छात्रों में साथ में पढ़ने वाली लड़कियों के साथ ऊंची सोसाइटी, क्लबों आदि में बहुत साथ न केवल अपनी हमउम्र वरन् अपनी उम्र से दुगुनी भाभीयों, आंटियों के साथ स्वच्छंद यौनाचार वह भी 16 से 25 की उम्र में 24 घंटें में 3-4 बार उन्मुक्त यौनाचार के कारण फिर दोस्तों के साथ न केवल शराब, सिगरेट, नशे में कोकीन चरस से ज्यादा

खतरनाक नशीली गोलियां के नियमित सेवन फिर यौन क्षमता बढ़ाने, बनाए रखने के लिए 15 वर्ष से 25 वर्ष की उम्र में इतना अधिक सेवन कर लिया जाता है कि 30-35 वर्ष की उम्र तक पहुंचते-पहुंचते हमारी युवा पीढ़ी नपुंसकता की ओर बढ़ने लगती है। और नपुसंकता पूर्ण रूप से न भी आए तो वीर्य में शुक्राणुओं की संख्या 100-200 प्रति बूंद या प्रति मिली भी नहीं बचती बेशक पुरुष वीर्य में शुक्राणुओं की संख्या जो प्राकृतिक जीवनशैली में 1910 में 900000 हुआ करती थी, वह 1950 तक आते-आते 65000-70000 तक रह गई, 1970 तक 50000 से भी नीचे चली गई, 1990 तक मात्र 20000-25000 और सन् 2000 में प्रति बूंद 10000-12000 पर 20-30 वर्ष के युवाओं में ही सिमट गई, सन् 2005 9-10000 और सन् 2010 तक 7 से 9000 ही रह गई, बेशक इन हजारों जीवित शुक्राणुओं में से 2-4 शुक्राणु ही स्त्री के गर्भाशय में पहुंच अंडाणुओं से मिलकर नए जीवन की रचना करते हैं।

पुरुष वीर्य के शुक्राणुओं को इसे ग्रीव गति से ह्रास होने में टीवी, इंटरनेट पर उन्मुक्त यौनाचार के प्रदर्शन के साथ ही हमारे भोजन में जिसमें दूध, दही से लेकर फूलों-सब्जियों अनाजों, तिलहनों और दलहनों में बढ़ता खाद का प्रयोग और अंधाधुंध जहरीले घातक इंडोसल्फान जैसे विषैली कीटनाशकों के प्रयोग ने भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। फिर आधुनिकता के नाम पर शीतल पेयों यथा कोक, पेप्सा, थम्सअप, लिम्का आदि जिनमें कार्बनडाइआक्साइड मिलाकर दबाव पेक किया जाता है और जिसे हम अपनी सांस में छोड़ते हैं शरीर में पहुंचकर न केवल पाचन तंत्र, लीवर, हृदय और किडनी पर भी असर डालती है दूसरी तरफ शीतल पेयों के जल को कीटाणु रहित बनाने के लिए ये बहुराष्ट्रीय कं. भी कृषि के घातक कीटनाशकों का प्रयोग करती है जिस पर 2006 से हल्ला मचा था। परंतु इन बहुराष्ट्रीय कं. को जालसाजों ने इस अत्यंत सूक्ष्म बताकर शरीर की वहन क्षमता के अनुकूल बताकर कानून में ही परिवर्तन करवा दिया था, पर कानून के परिवर्तन से शरीर मानव शरीर की वहन क्षमता परिवर्तित नहीं हो गई, यह विष शरीर में सीधे ही पहुंचकर सबसे ज्यादा शुक्राणुओं को नष्ट कर पूरी भारतीय युवा पीढ़ी जो इन शीतलपेयों का उपयोग नियमित रूप से करते हैं न केवल गंभीर बीमारियों जिसमें हृदयाघात से लेकर किडनी खराब होना, मस्तिष्काघात, रोग तक युवावस्था में सामने आने लगे हैं। इसके साथ ही पैकेट बंद खाद्य पदार्थ, पिज्जा बर्गर, पेक्ड जूस जिनमें घातक रसायनों का प्रयोग भी शुक्राणुओं को समाप्त करने और युवा पीढ़ी को नपुसंक और महिलाओं को बांझ बनाने में उत्प्रेरक की भूमिका अदा कर रहे हैं। जिसकी सत्यता पुष्टि गाहे-बगाहे विदेशी चिकित्सीय संस्थानों की दैनिक समाचार पत्रों में छपी सूचनाएं करती रहती हैं।भारतीय विश्व की प्राचीनतम चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद ने स्पष्ट लिखा है प्राणी का जन्म यौनाचार से यौनाचार कर अपनी अगली पीढ़ी को जन्म देना है, यथार्थ में किसी भी प्राणी, वनस्पतियों का यहां इससे ज्यादा कोई उपयोग नहीं।

हमारे ऋषियों मुनियों ने न केवल चिकित्सा शास्त्रों में वरन् अनेकों पुराणों में स्पष्ट लिखा है कि जो नर-नारी पूर्ण रूप से स्वास्थ्य हो वे ही यौनाचार और समागम से अगली पीढ़ी को जन्म दें, अन्यथा यौनाचार ही न करें और करते हैं तो संतानों के प्रति कदापि न करें क्योंकि वह कमजोर पीढ़ी आने वाले भविष्य की पीढ़ियों को दुर्बल और विकलांग बनाकर पूरे समाज को बर्बाद करेगी जबकि वर्तमान में हर दूसरा व्यक्ति किसी न किसी रोग से पीड़ित है हर चौथा व्यक्ति मधुमेह से पीड़ित है और ये रोग वंशानुगत चलते चले आ रहे हैं। उस पर भी आधुनिकता के नाम पर पेक्ड फूड, शीतल पेक्ड पेय आदि हम धड़ल्ले से न केवल कर रहे है वरन उसका बढ़ावा देने के नाम पर हमारे धूर्त, गिद्ध, सत्ताधीशों ने बहुराष्ट्रीय कं. से मोटा कमीशन डकारने के लिए कानून तक बना दिए हैं। जिसे नाम दिया है खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम-06 जो घोर असुरक्षित, घातक रसायनयुक्त विष युक्त खाद्य पदार्थ पेक करने के लिए विश्व भर में बदनाम हो चुकी है और भारत में भी कोक, पेप्सी, केडबरी, आईटीसी, वालमार्ट,

(शेष 10 पर)

सरकारी स्वास्थ्य सेवायें कमीशन पर निजी चिकित्सालयों का स्वास्थ्य सुधार रही

गरीबों की चिकित्सा के नाम लुटाया जा रहा निजी अस्पतालों को

सरकारी स्वास्थ्य सेवायें भी मोटे कमीशन पर झाबुआ में निजी क्षेत्र में दे दी गई, आने वाले समय में पूरे प्रदेश और देश में सरकारी चिकित्सालय जन-धन को और जनता को लूटने सौंपे जायेंगे निजी चिकित्सालयों के नीच गिद्ध डॉक्टरों को जो पिछले 40 वर्षो से पीएमटी में चल रहे फर्जीवाड़े से पास होकर अपने चिकित्सालय चला रहे...

मप्र में और पूरे देश में जब से भुखेरा जन पार्टी ने सत्ता संभाली, इनके माई बाप देश के सबसे बड़े जालसाज पूंजीपति टाटा, अंबानी, बिरला, आईटीसी, हिंदुस्तान लीवर जैसे सैकड़ों हो गये, सत्ता चलाने का मूल उद्देश्य जनहितों के नाम अपने दीर्घकालीन स्वहितों को पूरा करना बन गया। लोकतंत्र में जनता को स्वास्थ्य शिक्षा, सड़कें तो कम से कम मिलना चाहिये थी, परंतु तीनो को ही, ये सत्ताधीश धूर्त अपने मोटे कमीशन और कमाई के लिए निजी क्षेत्रों में सौंपने पर तुले हैं। स्वास्थ्य के नाम पर रुपए 4.32 लाख करोड़ में से रुपए 1 लाख करोड़ का धन तो मंत्रालय में ही बंट जाता है। फिर संचालक दवा, अस्पताल सामग्री में ही रुपए 25 से 80 प्रश तक कमीशन हजम कर जाते हैं। इतिहास इन सब तथ्यों की पुष्टि कर चुका हैं। अभी नया खेल जो चल रहा है, वह है गरीबों और अनु. जाति, जनजाति के बीमारों की गर्भवती महिलाओं की प्रसुति, टीकाकरण, नसबंदी आदि के कार्यों को निजी चिकित्सालयों, चिकित्सा महाविद्यालयों आदि को सौंपकर उनकी कमाई करवाना और उसमें से मोटा हिस्सा डकारना, इस कांड में मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता योजना, जिलाधीश, मु. चि. अ. के माध्यम से प्रकरणों को स्वीकृत कर धन राशि का चेक, मांग पत्र सीधे मरीजों व उनके परिजनों को उस निजी चिकित्सालय के माध्यम से बांटे जा रहे हैं। ये हे स्वास्थ्य का तीन पी तरीका अर्थात पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का लूट का धंधा, इस तरीके में हजारों प्रकरण ऐसे भी हैं। बीमार को तुरंत चिकित्सा की आवश्यकता थी आवेदन की स्वीकृति हेतु प्रेषित कर दिया गया, इस बीच बीमार की चिकित्सा की गई और उससे धन मिलने पर लौटाने का वादा कर, तत्काल धन वसूल कर लिया गया, बाद में उन हरामखोर जालसाज गिद्ध निजी चिकित्सालयों के नाम से जो चेक या ड्राफ्ट सरकार से मिला वह भी हजम कर लिया गया,

(शेष 10 पर)

बैंकें बन चुकी है घोर जालसाजियों और भ्रष्टाचार का अड्डा

अकर्मण संपत्तियों के लिए बैंकों के भ्रष्ट अधिकारी जिम्मेदार

जनता से लूटो, पूंजीपतियों पर लुटाओं, अशोध्य ऋणों पर रुपए 35000 करोड़ जनधन के लुटाए

भारत में राज कर रही हर राजनीतिक पार्टी हर उद्योगपति पूंजी पति से चुनावी चंदा अरबों रुपए में वसूलती है। 90 प्रश उद्योगपति और पूंजीपति झूठे, जाली दस्तावेजों के आधार पर सरकारी, राष्ट्रीयकृत, निजी बैंकों के साथ ही अन्य वित्तीय संस्थानों से 2 से 10 प्रश का कमीशन बांटकर आसानी से वहां के अधिकारी बैंकों में जमा जन-धन के ऋण के रूप में इन उद्योगपतियों, पूंजीपतियों, भूमाफियाओं, कॉलोनी माफियाओं और सेवा प्रदात्ता कं. आदि को अरबों रुपए की ऋण के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान कर देते हैं। अब जब पूंजीपति, उद्योगपति, सेवा प्रदाता कं. के मालिकों यथा प्रबंध संचालकों, अध्यक्षों मालिकों आदि ने चार्टर्ड बनाम करप्ट एकाउंटेंट के फर्जी मूल्यांकनों, दस्तावेजों, लाभ-हानि और चिट्ठों के आधार पर 2 से 10 प्रश ऋण प्राप्त किया है तो पूर्ण सुनियोजित षड़यंत्रों के साथ हजम करने और वित्तीय संस्थान को घाटे में दिखाकर न देने के लिए ही लिया है तो 10-20 प्रतिशत मूल और ब्याज जमाकर खिसकने के लिए वह पूर्व नियोजित तरीके से बैंक के अधिकारियों के साथ मिलकरे डुबो ही देता है, जबकि इसके लिए सर्वप्रथम बैंक अधिकारी, शाखा प्रबंधक और वरिष्ठ स्वीकृति अधिकारी ही जिम्मेदार होता है। परंतु बैंकों की निहायत ढीली, जालसाजी पूर्ण कार्यप्रणाली का लाभ उठाते हैं। वहां के ऋण स्वीकृति करने वाला अधिकारी प्रबंध वरिष्ठ प्रबंधक जो कि जानबूझकर 2 से 10 प्रश कमीशन डकार कागजी खानापूर्ति कर वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाते है। बाद में आसानी से स्थानांतरीत होकर चले जाते हैं। यथार्थ में स्थानांतरण उन सभी भ्रष्ट, जालसाज, कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए अपने कुकृत्यों से मुक्ति पाने का आसान और सटीक वरदान सिद्ध होता है। नया उस पद पर नियुक्त कर्मचारी, अधिकारी उस लूट-खसोंट, जालसाजियों भ्रष्टाचार को उजागर करने से बेहतर अपनी कमाई की व्यवस्था में लग जाता है। यदि वह अपने पूर्ववर्ती अधिकारी के कुकृत्यों को उजागर करने की कोशिश भी करता है तो उससे वरिष्ठ और कनिष्ठ जो ऐसे ऋणों, अग्रिम, नगद साख, साख पत्रों आदि की जालसाजियों को उजागर करता है तो उससे जुड़े उसे पेरशान करने, प्रताड़ित करने लगते है।

(शेष 11 पर)

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक- अजमेरा एस.पी. कुमार द्वारा अपनी दुनिया प्रिंटर्स, 13 प्रेस कॉम्पलेक्स, ए.बी. रोड, इंदौर से मुद्रित एवं 299, अम्बेडकर नगर, इंदौर (म.प्र.) से प्रकाशित।
भोपाल प्रतिनिधि- एस.के. भारद्वाज मो. 9425637958, इंदौर कार्यालय- मोबा. 9425125569

This document was created with Win2PDF available at http://www.win2pdf.com.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.